लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

८

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

तेहरवां सत्र

Thirteenth Session

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

खंड 48 में अंक 1 से 10 तक हैं।

Vol. XLVIII contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

न्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

Preservation Unit
Fumigated 28-8-9
Parliament Library

विषय सूची/CONTENTS

अंक 8, बुधवार, 26 फरवरी, 1975/7 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 8 Wednesday, February 26, 1975/Phalguna 7, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	MEMBER SWORN	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	*ORAL ANSWERS TO QUESTIONS*	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
123. इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलाजी कारपोरेशन का पिक्चर ट्यूबें आयात करने का प्रस्ताव	Proposal made by Electronics Trade and Technology Corporation for Import of Picture Tubes	1–4
124. केरल में विदेशी स्वामित्व के बागान के राष्ट्रीयकरण पर अध्यादेश	Ordinance on Nationalisation of Foreign Owned Plantation in Kerala	4–7
126. पांचवीं योजना में उड़ीसा के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्वीकार की गयी प्रमुख परियोजनायें	Major Projects in Central Sector approved for Orissa in Fifth Plan	7–10
128. हिन्दुस्तान कागज निगम के कार्यालय को नई दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित करना	Shifting of Office of Hindustan Paper Corporation from New Delhi to Calcutta ..	10–13
129. छत्तरपुर, उड़ीसा के निकट उद्योग-समूह	Industrial Complex near Chhatrapur, Orissa	13–15
130. पश्चिम बंगाल में टी०वी० सेटों का उत्पादन करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स आयोग के पास अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र	Application for Production of T.V. Sets in West Bengal lying with the Electronics Commission	15–16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS*	
ता० प्र० सं० S.Q. Nos.		
121. केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मैसर्स न्यूमेटिक (इंडिया) और मैसर्स ईस्टर्न मशीन सेल्ज, कलकत्ता के कार्य की जांच	CBI Enquiry into the Affairs of M/s Pneumatic (India) and M/s Eastern Machine Sales, Calcutta	16–17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
122.	सीमेंट का उत्पादन	Production of Cement ..	17–18
125.	पी०टी०आई० को सरकारी निगम में बदलना	Conversion of P.T.I. into a Public Corporation ..	18
127.	'सुपर पावर स्टेशन'	Super Power Stations ..	18
131.	दिल्ली सदर बाजार के दंगे संबंधी प्रसाद आयोग का प्रतिवेदन	Prasad Commission report on Delhi Sadar Bazar disturbances	18
132.	भारत में विद्युत पारेषण में हानि	Transmission Loss of electricity in India	18–19
133.	मंत्रियों द्वारा संसद में दिये जाने वाले वक्तव्यों की अग्रिम प्रतियों को प्रधान मंत्री को दिखाने के बारे में प्रधान मंत्री सचिवालय द्वारा मंत्रालयों को दिए गये अनुदेश	Instructions issued by Prime Minister's Secretariat to Ministries to show advance copies of statements to be made by Ministers in Parliament to Prime Minister ..	19–20
134.	पंजाब और हरियाणा के सीमा संबंधी दावों को निपटाने के लिये सीमा आयोग	Boundary Commission to settle Punjab and Haryana Territorial claims	20
135.	आशय पत्रों/लाइसेंसों के लिए मध्य प्रदेश से प्राप्त अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र	Pending applications from Madhya Pradesh for letters of intent/licences	21
136.	धन की अपर्याप्तता का डाक तथा तार विभाग के विस्तार कार्यक्रमों पर प्रभाव	Effect of insufficiency of funds on expansion programmes of P & T Department ..	21
137.	आई०टी०आई० में इन्टरनशनल टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कारपोरेशन के शेयर	Shares of International Telephones and Telegraph Corporation in I.T.I.	22
138.	रोजगार बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों में रोजगार के अवसर पैदा करना	Generation of Employment in States under Employment Promotion Programme	22
139.	उत्तर प्रदेश में नरौरा में परमाणु बिजलीघर	Atomic Power Station at Narora in U.P.	22
140.	टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों के लिए 'ग्लास शेल्स' बनाने हेतु संयंत्र	Plant for manufacture of Glass Shells for T.V. Picture Tubes	23

अता०प्र०संख्या U. S. O. Nos.			
1201.	सरगुजा में निम्न ताप कार्बनीकरण संयंत्र	Low Temperature Carbonisation Plant in Surguja ..	23

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
1202.	पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में ऐसे क्षेत्र जिनमें कोयला न निकाला गया	Virgin Coal Bearing Area in Burdean District of West Bengal	23–24
1203.	पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के मेजला क्षेत्र में कोयला सर्वेक्षण सलाहकार समिति द्वारा किया गया सर्वेक्षण	Survey made by Coal Survey Advisory Committee in Mejla Area, District Bankura, West Bengal	24
1204.	लद्दाख में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in Ladakh	
1205.	कापियों की कमी	Shortage of Exercise Books..	25
1206.	इंडियन ह्यूम पाइप कम्पनी को क्रयादेश	Orders for Indian Hume Pipe Company	25
1207.	मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पांचवीं योजना में व्यवस्था	Provision for Rural Electrification in Madhya Pradesh in Fifth Plan	26
1208.	चंडीगढ़ का दर्जा	Status of Chandigarh ..	26
1209.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का मुख्यालय धनबाद से कलकत्ता बदला जाना	Shifting of Head Office of Bharat Coking Coal Ltd. from Dhanbad to Calcutta ..	26–27
1210.	उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्गों के लिए वर्ष 1975–76 में राज्य को विशेष वित्तीय सहायता	Special Financial Assistance to U.P. in 1975-76 for weaker sections of the State ..	27
1211.	डाकघर का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of a Post Office	27
1212.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा विदेशों में मशीनी औजार कारखानें स्थापित करना	Setting up of Machine Tool Factories in foreign countries by H M.T. ..	27–28
1213.	एम्पलिफायर और स्पीकरों का निर्माण करने वाली कम्पनियां	Companies manufacturing Amplifiers and Speakers	28
1214.	अखबारी कागज की कम सप्लाई	Short supply of News Print	28–29
1215.	राज्यों में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सहायक कार्यालयों की स्थापना	Setting up of subsidiaries of N.T.C. in States	29
1216.	त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधारों को लागू करना	Introduction of Administrative Reforms in Tribal Belts of Tripura	30
1217.	भारत तथा अन्य देशों में तापीय बिजलीघरों का कार्यकरण	Working of Thermal Units in India and other Countries	30
1218.	पड़ोसी देशों के साथ परमाणु जानकारी का आदान प्रदान	Sharing Atomic Know-how with Neighbouring countries	30–31
1219.	हंगरी को कोक भट्टी संयंत्र की सप्लाई	Supply of Coke Oven Plant to Hungary	31

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
1220.	मिजो नेशनल फ्रन्ट द्वारा लन्दन में समन्वय सैल का खोला जाना	Opening of Liaison Cell by Mizo National Front in London	31
1221.	कोयला खान प्राधिकरण और भारत कोकिंग कोल लि० की कोयला खानों में दुर्घटनायें	Accidents in colleries of Coal Mines Authority and Bharat Coking Coal Ltd. ..	31–32
1222.	वजन करने वाली मशीनों का विदेशों को निर्यात	Export of weighing machines to foreign countries.. ..	32–33
1223.	राष्ट्रीय आय में कमी	Fall in National Income	
1224.	कोयले का उत्पादन	Production of Coal ..	33
1225.	कालीनदी पर बिजली परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाना	Kalinadi Hydel-Project as National Project	33–34
1226.	मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण	Electrification of rural areas in Madhya Pradesh ..	34
1227.	मोदी फ्लोर मिल्स के विरुद्ध आरोप	Charges against Modi Flour Mills	34–35
1228.	दक्षिण कनारा जिले में 'कोरगा' जनजाति के लोग	'Koragas' Tribal People in South Kanara District ..	35
1229.	जामनगर के निकट ढुलकटो में एक पुजारी द्वारा हरिजन लड़के को पिटाई द्वारा मार डालना	Harijan boy beaten to death by a priest at Dhulktot near Jamnagar	35
1230.	हरिजनों पर अत्याचारों के मामलों में गुजरात न्यायालय का निर्णय	Gujarat Court Judgement in cases of atrocities on Harijans	35–36
1231.	आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग करने के बारे में राज्यों को अनुदेश	Instructions to states on use of MISA ..	36–37
1232.	कर्नाटक में 'जीता' (गुलाम) प्रथा का समाप्त किया जाना	Abolition of 'Jeeta' system in Karnataka	37
1233.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के लेखा अधिकारी के विरुद्ध जांच	Enquiry against accounts officer of N.I.D.C.	37–38
1234.	बोगस छोटे उद्योग	Bogus small industries ..	38–39
1235.	राज्य की वार्षिक योजना परिव्यय में उड़ीसा राज्य का हिस्सा	Share of Orissa state in the annual plan outlay for the state	39
1236.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों की बिक्री	Sale of shares of Scooters India Ltd.	39–40

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
1237.	महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज के कारखानों की स्थापना	Setting up of newsprint factories in Maharashtra, U.P. and H.P. ..	40–41
1238.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल द्वारा देश में गोली चलाए जाने की घटनाएं	Firings in the country by C.R.P. and B.S.F. ..	41
1239.	राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम	National Film Development Corporation	41–42
1240.	फिल्म समारोह के आयोजनों द्वारा की गई कथित अनियमितताएं	Alleged Irregularities Committed by Organisers of Film Festival	42
1241.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक की कथित टिप्पणी	Alleged remarks of Managing Director, N.I.D.C. ..	42–43
1242.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा पिंजोर में ट्रेक्टरों का उत्पादन	Production of tractors by HMT at Pinjore	43
1243.	औद्योगिक क्षेत्र पर अनुसंधान एवं विकास उपकर लगाया जाना	Levy of research and development cess on Industrial Sector	43–44
1244.	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन	Pensions to freedom fighters	
1245.	फिल्म समारोह में अल्जीरियाई और श्री लंका का प्रतिनिधि मंडल	Algerian and Sri Lanka delegation to Film Festival ..	44
1246.	अतिरिक्त टायरों और ट्यूबों के बिना स्कूटरों का दिया जाना	Delivery of Scooters without spare tyres and tubes ..	44–45
1247.	दिल्ली से तारों का भेजना	Despatch of Telegrams from Delhi	45–46
1248.	बिहार में जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन के विरुद्ध कठोर कार्यवाही	Stern action against movement launched by Shri Jaya Prakash Narayan in Bihar	46
1249.	फिल्म समारोह में आये प्रतिनिधियों के सम्मान में फिल्म फेडरेशन आफ इण्डिया द्वारा किया गया भोज	Dinner hosted by Film Federation of India in honour of Delegates to Film Festival..	46–47
1250.	हापुड़ में टेलीफोनों का कार्यकरण	Functioning of Telephones in Hapur	47–48
1251.	मोटरगाड़ी उद्योग में संकट	Crisis in Automobile Industry	48
1252.	मध्य प्रदेश में पांचवीं योजना में एक बड़े कारखाने की स्थापना करना	Setting up of big factory in M.P. in Fifth Plan ..	48
1253.	नागा विद्रोहियों द्वारा वार्ता पुन: आरंभ करना	Resumption of talks by Naga Rebels	49

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
1254.	रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण	Training for Unemployed Youth under Employment Promotion Programme ..	49
1255.	केरल में आदिजातियों के लोगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए समिति	Committee to study the problems of Tribals in Kerala ..	50
1256.	कलकत्ता के साप्ताहिक पत्र "फ्रन्टियर" तथा "दर्पण" के कार्यालयों की लूटपाट	Ransacking of offices of "Frontier" and 'Darpan' weekly papers of Calcutta ..	50
1257.	राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग का प्रशासकी ढांचा	Administrative set up of Nattionalised coal Industry ..	50
1258.	मैसर्स मारुति लिमिटेड द्वारा इंजन का आयात	Import of Engine by M/s Maruti Ltd.	50–51
1259.	विशिष्ट राजनीतिक दल की विचारा धारा में आस्था रखने वाल अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने के बारे में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय	Andhra Pradesh High Court's decision on Employment of candidates in Government services having faith in ideology of a particular Political Party	51–52
1260.	इलेक्ट्रानिक उद्योग के लिए कच्चे माल का आयात	Import of Raw Materials for Electronic Industry ..	52–53
1261.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारियों के विदेशी दौरों पर व्यय	Expenditure on foreign tours of persons of N.I.D.C. ..	53
1262.	दुर्बल वर्गों के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण करने के लिए योजना अवंटन में वृद्धि	Increase in plan allocation for public Distribution of Essential Commodities for weaker sections of Society	53
1263.	जय गुरुदेव के पूर्ववृत की जांच	Enquiry into Antecedents of Jai Gurudeva	54
1264.	नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Neta ji Inquiry Commission	54–55
1265.	दिल्ली में कई प्राधिकरणों का अस्तित्व	Multiplicity of Authorities in Delhi	55
1266.	भोपाल में केन्द्रीय संचार मंत्री के घर में गन पाउडर के गोलों का पाया जाना	Gunpowder Balls found in house of Union Communications Minister in Bhopal	55
1267.	कथित नकली स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension to Alleged Bogus Freedom Fighters	55–56

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
1268.	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के कर्मचारियों की मुअत्तिली	Suspension of Employees of Rajasthan Atomic Power Project	56–57
1269.	सीमेंट की दुहरी मूल्य-निर्धारण प्रणाली	Dual Cement Pricing System	57
1270.	वर्ष 1976 तक बिजली की स्थिति में सुधार	Improvement in Power Situation by 1976 ..	57
1271.	श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा आकाशवाणी के विरुद्ध आन्दोलन	Agitation by Shri Jaya Prakash Narayan against A.I.R. ..	58
1272.	वर्ष 1975 के दौरान कोयले के उत्पादन का लक्ष्य	Target for production of Coal during 1975	58
1273.	कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये ब्रिटेन से सहायता	U.K. assistance for raising coal output ..	58
1274.	'अमर प्रेमी शैनी विजानन्द' फिल्म पर रोक	Ban on Film "Amar Premi Sheni Vijanand" ..	59
1275.	दिल्ली-पुलिस के कर्मचारियों को छुट्टियों की मंजूरी	Grant of holidays to Employees of Delhi Police	59
1276.	केरल में उद्योगों की स्थापना करने के लिए आवेदन पत्र	Applications for setting up industries in Kerala ..	59–60
1277.	विद्युत संसाधनों के विकास के लिए कर्नाटक द्वारा वित्तीय सहायता का आवेदन	Financial assistance sought by Karnataka for Development of Power Resources ..	60
1278.	भारत द्वारा वैज्ञानिक उपग्रह छोड़े जाने के बारे में भारत और सोवियत संघ के बीच विचार-विमर्श	Discussions between India and USSR on launching of Scientific Satellite by India ..	60–61
1279.	कर्नाटक के लिये टेलीविजन कार्यक्रम रिले करने वाला केन्द्र	T.V. Relay Station for Karnataka ..	61
1280.	कर्नाटक में उद्योगों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Industries in Karnataka	61–62
1281.	पांडिचेरी में हिन्दू विवाह अधिनियम का लागू किया जाना	Application of Hindu Marriage Act in Pondicherry ..	62
1282.	पश्चिम बंगाल--बिहार क्षेत्र में सरकारी स्वामित्व वाली खानों में श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जाना	Flouting of labour laws in Government owned mines in West Bengal—Bihar Belt	63
1283.	आयुध कारखानों से गोलों की चोरी के बारे में जांच	Enquiry into Pilferage of Grenades from Ordnance Factory ..	64
1284.	पैकिंगों पर अनिवार्य रूप से मूल्य और वज़न अंकित किया जाना	Compulsory display of Prices and weight on ackings.. ..	64

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
1285.	मध्य प्रदेश में सिंगरौली में सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना	Setting up of a Super Thermal Power Station in Singrauli in Madhya Pradesh.. ..	64–65
1286.	इस्पात और सीमेंट के आबंटन के अभाव में मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्यों पर पड़ा बुरा प्रभाव	Construction work of Power Projects in M.P. affected by non-allotment of Steel and Cement	65
1287.	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माताटीला परियोजना का प्रतिवेदन मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराना	Making available Mata Tita Project Report to M.P. by U.P.	65
1288.	मध्य प्रदेश को हीराकुंड परियोजना से विद्युत की सप्लाई	Supply of Power to Madhya Pradesh from Hirakud Project	65
1289.	पूर्वी जोन के लिए औद्योगिक परियोनाएं	Industrial Projects for Eastern Zone	66
1290.	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय में कागज परियोजनाओं का स्थापित किया जाना	Setting up of Paper Projects in West Bengal, Tripura, Assam and Meghalaya ..	66–67
1291.	पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मनीपुर और मेघालय में डाकघर स्थापित करना	Setting up of Post Offices in West Bengal, Assam, Tripura, Manipur and Meghalaya	67–68
1292.	प्रति वर्ष प्रत्येक पत्रिका को एक पृष्ठ का विज्ञापन दिये जाने की मांग	Demand for one page Advertisement to each Magazine annually	68
1293.	ग्वालियर से लाहर और गोहद के लिए टेलीफोन लाइनों का डाला जाना	Laying of Telephone Lines from Gwalior to Lahar and Gohad	68
1294.	मोटर्स सेल्स लिमिटेड, लखनऊ द्वारा जीपों की बिक्री	Sale of Jeeps by Motors Sales Ltd., Lucknow	69
1295.	बिहार तथा अन्य राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में दंगे	Riots in Adivasi areas in Bihar and other States	69–70
1296.	कोयला खानों के विकास के लिए विदेशी सहायता	Foreign Assistance for Development of Coal Mines ..	70
1297.	फिल्म समारोह में दिखाई गई फिल्मों का देशवार ब्यौरा	Films shown at Film Festival, country wise	70
1298.	स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी	Sanction of Pension to Freedom Fighters	70–71
1300.	रक्षित बिजली घरों की स्थापना	Setting up of Captive Power Plants	71

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
1301.	केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं	Rural Electrification Schemes in Kerala	71–72
1302.	नई दिल्ली से कोचीन और नई दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	S.T.D. between New Delhi-Cochin and New Delhi-Trivandrum ..	72
1303.	उपग्रह कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में टी० वी० सेटों की स्थापना करना	Installation of T.V. Sets in Rural Areas for Receiving Satellite Programme..	72–73
1304.	केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों के नामांकन की कसौटी	Criteria for Nominating Members of Central Board of Film Censors	73
1305.	विभिन्न भाषाओं की फिल्मों के उत्पादन के लिये सहायता के बारे में सरकार की नीति	Government Policy on Assistance in production of Films in various Languages	73–74
1306.	गुरुगोबिन्द सिंह जी के जन्म दिन को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करना	Declaration of Guru Gobind Singh Ji's Birthday as a National Holiday	74
1307.	कोयला उद्योग के लिये आवश्यक विस्फोटकों के निर्माण हेतु नये एकक	New Units for Manufacture of Explosives for Coal Industry	74–75
1308.	राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले का उत्पादन	Production of Coal since Nationalisation	75–76
1309.	समानान्तर गणतन्त्र दिवस तथा समारोह	Parallel Republic Day Parade and Celebrations	76
1310.	चिनाव नदी पर सिलाल बिजली परियोजना का निर्माण	Construction of Selal Power Project on River Chanab ..	76
1311.	राष्ट्रीयकरण के पश्चात कोयले के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Coal since Nationalisation	76–78
1312.	सरकारी कर्मचारियों को नियत मूल्यों पर दैनिक प्रयोग की आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिये स्टोरों का खोला जाना	Opening of Stores for Supply of Essential Items of Daily Use at Fixed Prices to Government Employees ".. ..	78
1313.	अंडेमान सरकार कृषक कर्मचारी संघ, पोर्ट ब्लेअर की मांगें	Demands of Andaman Krashak Karmachari Sangh, Port Blair	79
1314.	शिक्षा सम्बन्धी फर्जी सर्टिफिकेटों की बिक्री	Sale of Bogus Educational Certificates	79
1315.	बहराइच (उत्तर प्रदेश) में बनों पर आधारित उद्योग	Forest-Based Industry in Bahraich (U.P.)	79–80

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Page
1316.	'पावर टिलरों' का उत्पादन — Production of Power Tiller	80
1317.	ट्रक्टर उत्पादन — Tractor Production ..	80–81
1318.	हरियाणा में बिजली की कम सप्लाई — Short Supply of Power in Haryana	81
1319.	परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में थोरियम का प्रयोग — Use of Thorium as Fuel for Nuclear Power Plants ..	81–82
1320.	खान मालिकों द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कोयले की सप्लाई रोकने की धमकी — Threat from Mine Owners to stop Supply of Coal to DESU	82
1321.	पीलीभीत में साम्प्रदायिक दंगा — Communal clash at Pilibhit	82–83
1322.	राज्यों को कोयले के वितरण के बारे में योजना — Scheme regarding Coal distribution to States	83
1323.	चौथी योजना में विद्युत बोर्डों द्वारा किये गये पूंजी निवेश पर लाभ की दर — Rate of Return on Investments made by Electricity Boards during Fourth Plan ..	83–84
1324.	पिछड़े जिलों में औद्योगिक लाइसेंस देना — Issue of Industrial Licences in Backward Districts ..	84–86
1325.	अकाशवाणी के अन्य केन्द्रों से संस्कृत में समाचार बुलेटिन — News Bulletins in Sanskrit from other Stations of A.I.R. ..	87
1326.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) विधयक — Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendement) Bill ..	87
1327.	केरल में नारियल जटा उद्योग को वित्तीय सहायता — Financial Assistance to Coir Industry in Kerala ..	88
1328.	मिजोरम में कानून और व्यवस्था की स्थिति का घटनास्थल पर अध्ययन — On-the-spot Study of Law and Order in Mizoram ..	88–89
1329.	केरल के स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी मामले — Cases of Pension of Freedom Fighters from Kerala	89–90
1330.	उत्तर प्रदेश को बिजली की सप्लाई — Supply of Power to U.P. ..	90
1331.	उत्तर प्रदेश में और अधिक विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना — Setting up of More Power Project in U.P.	90–91
1332.	शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये परमाणु ऊर्जा का प्रयोग — Use of Atomic Energy for peaceful Purposes..	91–93
1333.	स्वर्गीय बेगम अख्तर और स्वर्गीय अमीर खां साहेब पर टिकटें — Stamps of Late Begum Akhtar and Late Amir Khan Saheb	93
1334.	प्राथमिकता वाले उद्योगों को कोयले के प्रषण में वृद्धि — Increase in Coal Despatches to Priority Industries ..	93

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
1335.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का कार्यालय कलकत्ता स्थानान्तरित करने के प्रयत्न में लगे अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaint against Officers for Manipulation of Shifting of Office of Hindustan Paper Corporation	94
1336.	समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलवे लाईन के उद्घाटन के सम्बन्ध में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार बुलेटिनों में गलती	Discrepancy in News Bulletins Broadcast by A.I.R. on Inauguration of Samastipur-Muzaffarpur Railway Line ..	94–95
1337.	दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधे डायल करने की व्यवस्था	Delhi-Bhubaneswar Direct Dialling	95
1338.	आशय पत्र जारी करने के पश्चात उद्योग को चालू करने संबंधी प्रक्रिया	Procedure Followed for Commissioning of Industry after issue of Letter of Intent ..	95–97
1339.	भद्रक उड़ीसा में मुख्य डाकघर इमारत	Head Post Office Building at Bhadrak, Orissa	97
1340.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास निर्यात के लिये तथा अन्तर्देशीय क्रयादेश	Export and Domestic Orders with BHEL	98
1341.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिये सुविधाओं की कमी	Lack of facilities in setting up of Industrial Units in West Bengal	98–99
1342.	पश्चिम बंगाल में गांवों और कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Village and Cottage Industries in West Bengal	99
1343.	मिजोरम और नागालैंड के क्रियाकलापों में चीन का अन्तर्ग्रस्त होना	China's involvement in Mizoram and Nagaland Affairs ..	99
1344.	बाजार में बिक्री कम होने के कारण टेलीविजन निर्माण करने वाले एककों का बन्द होना	Closing down of Television Manufacturing Units due to sluggish sale Market ..	100
1345.	पाली (राजस्थान) में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Pali (Rajasthan)	100–101
1346.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अपने नवें प्रतिवेदन में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर जुर्माना लगाने की सिफारिश	Imposition of fines recommended by Central Vigilance Commission in their Ninth Report for certain I.A.S. and I.P.S. Officers	101
1347.	टेलीफोन शुल्क की बकाया राशि	Telephone Arrears ..	101–102

U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
1348.	भारत के समग्र राष्ट्रीय उत्पादन पर औद्योगिक क्षमता के उपयोग का प्रभाव	Effect of utilisation of Industrial Capacity on Gross National Product	102–103
1349.	गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में सीमेंट कारखाने	Cement plants in private and public Sectors	103
1350.	विदेशी मुद्रा पर स्कूटरों तथा मोटर कारों का आवंटन	Allotment of scooters and motor cars against foreign exchange	103–104
1351.	गोरखपुर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	Automatic telephone exchange at Gorakhpur	104–105
1352.	समस्तीपुर में बम विस्फोट	Bomb blast at Samastipur ..	105
1353.	स्वीटजरलैंड के सहयोग से घड़ियां बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जाना	Setting up of a watch factory in collaboration with Switzerland	105
1354.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना का पुनः तैयार किया जाना	Recasting of Science and Technology Plan ..	105–106
1355.	उन्नाव (उत्तर प्रदेश) में जाली औद्योगिक एककों का पंजीकरण रद्द किया जाना	Deregistration of bogus industrial units in Unnao (Uttar Pradesh)	106
1356.	गुजरात में गोली चलने से मरे लोग	Number of persons killed due to firings in Gujarat ..	107
1357.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by National Instrument Ltd., Calcutta ..	107
1358.	उपद्रवों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने का वैकल्पिक उपाय	Alternative to police firing to check disturbances	107–108
1359.	दिल्ली के निकट के कस्बों को स्थानीय टेलीफोन काल	Local calls to ring towns of Delhi	108
1360.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में राष्ट्रीयकरण से पूर्व तथा पश्चात कोयले का उत्पादन	Production of coal in Bharat Coking Coal Ltd., before and after Nationalisation ..	108–109
1361.	निवेशित पूंजी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिय पांचवीं योजना की नीति में परिवर्तन	Modification in strategy of Fifth Plan to achieve maximum benefits from investments made	109–110
1362.	विद्युत उत्पादन संयंत्रों और विद्युत उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की नई दिल्ली में दिसम्बर, 1974 में हुई बैठक	Meeting of power manufacturing plants and users of power in New Delhi in December, 1974.	110
1363.	औद्योगिक विकास नीति समूह का गठन करना	Setting up of Industrial Development Policy Group ..	110–111

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
1364.	समाचारपत्रों द्वारा अखबारी कागज के उपयोग पर लगे प्रतिबन्ध में छूट	Relaxations of restrictions on use of newsprint by Newspapers	111
1365.	पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के 'सेल' द्वारा किये गये कार्यों की पुनरीक्षा	Review of the work done by the cell for development of hill areas	112
1366.	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रतिनिधि	Delegates to International Film Festival ..	112
1367.	राष्ट्रीय फिल्म नीति	National Film Policy	112–113
1368.	वाणिज्यिक प्रसारणों से आय	Earnings by commercial broadcasting	113
1369.	उत्तर प्रदेश में छोटे समाचार पत्रों को लघु उद्योग घोषित करना	Declaration of small newspapers as small industry in U.P.	113
1370.	लद्दाख के विकास के लिये आवंटन में वृद्धि करना	Increase in allocations for development of Ladakh ..	113–114
1371.	अन्तः राज्यीय और अन्तः प्रदेशीय विद्युत सम्पर्कों की योजनाओं को कार्यान्वित करना	Implementation of schemes of inter-state and inter-regional power links	114
1372.	जनवरी, 1975 के दौरान ऊर्जा मन्त्री द्वारा कोयला खान क्षेत्र का दौरा	Visit by Minister of Energy to Coal Mine areas during January, 1975	114–115
1373.	इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट प्रोमोशन कारपोरेशन को बन्द करना	Winding up of Indian Motion Picture Export Promotion Corporation	115
1374.	राजस्थान विद्युत प्रणाली को भाखड़ा के समानान्तर बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal regarding paralleling of Rajasthan Power system with Bhakra	115–116
1375.	अफ्रीकी एशियाई चलचित्र समारोह का आयोजन	Holding of Film Festival of Afro-Asian Films	116
1376.	देश में 'बन्द'	Bundhs in the Country ..	116
1377.	वर्ष 1974-75 में बिहार में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of villages in Bihar during 1974-75 ..	116–117
1378.	बिजली की कमी के कारण हरियाणा में उद्योगों को हानि	Loss to industries in Haryana due to power shortage ..	117
1379.	नेपा मिल्स का कार्यकरण	Working of Nepa Mills ..	118
1380.	केरल में आदिम जाति ब्लाक खोले जाना	Opening of Tribal Blocks in Kerala	118

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Page
1381.	डाक-तार विभाग में ओवरसियरों द्वारा की गई मांगें — Demands made by overseers in P.&T. Department ..	118–119
1382.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधीन मुसुन्दा कोयला खानों में कदाचार — Malpractices in Kusunda Collieries under Bharat Coking Coal Ltd. ..	119
1383.	पटना में जे० पी० के जलूस पर बम फेंकने के सम्बन्ध में रामेश्वर नाथ याड से पूछताछ किया जाना — Interrogation of Rameshwarnath Yad, for throwing a bomb on J.P's procession at Patna	119
1384.	तरुण भारत-बेलगाम दैनिक के प्रतिनिधि को मान्यता दिये जाने के बारे निलम्बित पड़ा आवेदन पत्र — Pending application of representative of Tarun Bharat, Belgaum daily for accredition	119–120
1385.	पूर्वोत्तर प्रदेश में ईसाई धर्म में परिवर्तन — Conversion to Christianity in N.E. region	120
1386.	मैसर्स मारुति लिमिटेड को छोटी कार के लिये आशय पत्र जारी करना — Issue of letter of intent to M/s Maruti Ltd. for small car ..	121
1387.	औद्योगिक लाइसेंस नीति में परिवर्तन — Changes in Industrial Licence Policy	121–122
1388.	अत्यावश्यक वस्तुओं तथा आम उपयोग की वस्तुओं सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति — Implementation of Recommendations made by Committee on Essential Commodities and articles of Mass consumption	122–123
1389.	रेलवे को वैगनों की सप्लाई — Supply of wagons to Railway	123
1390.	स्कूटरों के लिए टायर और ट्यूबों का आयात — Import of Tyres and Tubes for scooters	123 124
1391.	"लास्ट डेज आफ नेताजी" नामक पुस्तक के प्रकाशन के लिए सामग्री — Material for publication of book "Last Days of Netaji"	124
1392.	आजाद हिन्द फौज के असैनिक कर्मचारियों तथा आई० आई० एल० के सदस्यों में से स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना — Grant of pension to freedom fighters amongst INA civilians and members of I.I.L. ..	124–125
1393.	संसद के घेराव की धमकी — Threat to 'gherao' the Parliament	126
1394.	परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और कनाडा के बीच सहयोग — Cooperation between India and Canada in the field of Nuclear Energy	126
1395.	उष्मसहों (रिफ्रैक्टरीज) के उत्पादन के लिये कर्नाटक राज्य औद्योगिक विकास निगम को आशय पत्र — Letter of intent to Karnataka State Industrial Development Corporation for Production of Refractories	126–127

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
1396.	हाइड्रोथर्मल परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए कर्नाटक द्वारा सहायता की मांग	Assistance sought by Karnataka for implementation of Hydro Thermal Projects	127
1397.	पश्चिमी "घाटों के विकास" हेतु उपयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Sub-Plan for Development of Western Ghats ..	127–128
1398.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (इंटरनेशनल)	HMT (International) ..	128
1399.	छोटे समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन	Government Advertisements to Newspapers	128
1400.	"पूअर प्लांट मैंटेनेंस ब्लेम्ड फार पावर कट्स शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	News items captioned "Poor Plants Maintenance Blamed for Power cuts"	129
सभा पटल पर रखे गये पत्र		Papers laid on the Table ..	129–131
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकलपों सम्बन्धी समिति		Committee on Private Members Bills and Resolutions	
51वां प्रतिवेदन		Fifty-first Report ..	131
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव		Motion of Thanks on the President's Address	132
	श्री प्रताप सिंह नेगी	Shri Pratap Singh Negi	132
	श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	Shri C.H. Mohamed Koya	133
	श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji	134
	श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	134
	श्री शिव कुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri	134–135
	श्री आर० पी० यादव	Shri R.P. Yadav ..	136–137
	श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee ..	137
	श्री तारकेश्वर पाण्डेय	Shri Tarkeshwar Pandey ..	137
	श्री सरजु पाण्डे	Shri Sarjoo Pandey	138
	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित	Shri Jagdish Chandra Dixit	138
	श्री सुधाकर पाण्डेय	Shri Sudhakar Pandey ..	138–139
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	139–140
	श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam ..	140–141
	श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni ..	141–142

विषय	Subject	पृष्ठ Page
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	143–144
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	144–146
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha ..	146–147
श्री एन० ई० होरो	Shri N.E. Horo	147–148
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani ..	148–149
श्री राम हेड़ाऊ	Shri Ram Hedaoo ..	149–150
श्री पाओकोई हाओकिप	Shri Paokai Haokip ..	150–151
श्री बीरेन एंगती	Shri Biren Engti..	151
दिल्ली के अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन के बारे में	Re-Demonstration by Delhi teachers	
कार्य मंत्रणा समिति 52वां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Fifty-second Report ..	151

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 26 फरवरी, 1975/7 फाल्गुन, 1896 (शक)
Wednesday, February 26, 1975/Phalguna 7, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री इस्माइल हुसैन खां (बारपेटा-आसाम)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलाजी कारपोरेशन का पिक्चर ट्यूबें आयात करने का प्रस्ताव

+

*123. **श्री वसन्त साठे**

श्री धामनकर :

क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलाजी कारपोरेशन ने 40,000 पिक्चर ट्यूबें आयात करने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एवं (ख) सरकार ने 40,000 टी० वी० पिक्चर ट्यूब इलैक्ट्रोनिवस व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम के जरिए आयात करने का निर्णय किया है। यह निगम इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान है। पिक्चर ट्यूबों के आयात को अब प्रभाव में लाया जा रहा है।

श्री वसंत साठे : सबसे पहले मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि वर्ष 1971 से भारत इलैक्ट्रोनिक्स द्वारा देश में बनाई जाने वाली पिक्चर ट्यूबों का मूल्य 220 रुपये से बढ़कर 565 रुपये हो गया है ? इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग में और विशेषकर टेलीविजन क्षेत्र

में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है क्योंकि उपग्रह टेलीविजन कार्यक्रम, जिससे ग्रामीण क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे, को ध्यान में रखते हुए यह विकासशील क्षेत्र है ? टेलीविजन सैटों और विशेषकर पिक्चर ट्यूबों के निर्माण में, जिनका आजकल अभाव है, देश को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक भारत इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित टेलीविजन ट्यूबों के मूल्यों का संबंध है, हाल में उत्पन्न आर्थिक विवशताओं के अतिरिक्त हमने सोचा है कि स्वदेशी तथा आयातित पिक्चर ट्यूबों के मूल्य में समता होनी चाहिए । अतः पूल मूल्य प्रणाली बनाई गई है जो उत्पादन मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य पायी गई है । हमारा देश ट्यूब निर्माण के मामले में लगभग आत्मनिर्भर है । मूल प्रश्न भारत इलैक्ट्रोनिक्स द्वारा बनाई जा रही पिक्चर ट्यूबों के बारे में है । चार अन्य पार्टियों को पिक्चर ट्यूबों के निर्माण के लिए लाइसैंस दिये गए हैं और उनमें से दो या तीन पार्टियों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है । जहां तक ग्लास ट्यूब के निर्माण का संबंध है, यह पिक्चर ट्यूब का मुख्य भाग है और अब इसकी भी प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तथा आशा करते हैं कि शीघ्र ही हम यह प्रौद्योगिकी तैयार कर लेंगे और ग्लास ट्यूब बनाना शुरु करेंगे ताकि देश में टेलीविजन सैटों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम आत्मनिर्भर हो सकें ।

श्री वसंत साठे : लघु उद्योग और विशेषकर इलैक्ट्रानिक्स तथा मनोरंजन उद्योग को प्रोत्साहित करने की हमारी नीति को ध्यान में रखते हुए, हमने यह वांछनीय समझा कि लघु एककों को पूरा प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे विकसित हो सके और वास्तव में उनका विकास हुआ है और हम जानते हैं कि देश में टेलीविजन सैट तथा अन्य इलैक्ट्रानिक्स उपकरण बनाने के लिए पर्याप्त क्षमता है । लेकिन देखने में आया है कि हमारी नीति के कारण उद्योग को कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई अथवा भारत इलैक्ट्रानिक्स द्वारा बनाये गए उपकरण तक नहीं मिल पाते । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है ? क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है ? यदि हां, दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय या कार्यवाही की जाती है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि हमने इस बात पर जोर दिया है कि टेलीविजन निर्माण कार्य का केन्द्रीकरण किया जाए तथा लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योग में इसके निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाए और अधिकांश मामलों में ऐसा किया भी गया है । उनकी शिकायत आयातित अथवा स्वदेशी पिक्चर ट्यूबों के लिए दुर्लभ कच्चे माल के वितरण तथा छोटे एककों के साथ निष्पक्षता न बरतने के बारे में है । हम टेलीविजन सैटों की उपलब्धता और उत्पादन के बारे में मुख्य रूप से जोर देते रहे हैं और इसलिए हमने उपक्रम के आकार की ओर ध्यान न देकर उत्पादन की ओर ध्यान दिया है , अर्थात् यदि उत्पादन 50 प्रतिशत है और क्षमता अधिक है तो हमने अधिक संख्या में पिक्चर ट्यूबें आवंटित की हैं और यदि उत्पादन 50 प्रतिशत से कम है तो हमने कम आवंटन किया । ऐसा करने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य यह रहा कि जब पिक्चर ट्यूब आवंटित की जाए तो उनका सही प्रकार से उपयोग किया जाए और वे उपभोक्ता बाजार में यथासंभव शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध हो सकें । अतः वितरण प्रणाली के बारे में यह पक्षपात छोटे उत्पादकों के विरुद्ध नहीं है । हमने इस बात पर जोर दिया है कि टेलीविजन सैट शीघ्र बनाए जायें और जितनी जल्दी संभव हो, इन्हें उपभोक्ता के पास पहुंचाया जाए ।

श्री वसंत साठे : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने कहा था कि सरकार के ध्यान में विशिष्ट मामले लाए गए हैं। यद्यपि उत्पादन क्षमता के अनुरूप हुआ, फिर भी उन्हें सप्लाई नहीं किया गया। यदि आप चाहें तो मैं उनके नाम बता सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ऐसे मामलों को ध्यान में लाए जाने के बाद क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विद्याचरण शुकल : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं हमारी नीति यह नहीं रही कि मध्यम एवं लघु क्षेत्र को नुकसान पहुंचे। यह हमारी मूल नीति रही है। हमें इसको ध्यान में रखना होगा। दूसरे, यदि कहीं कोई चूक हुई है, तो माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह तथ्य पेश करें ताकि हम उसे ठीक कर सकें।

श्री धामनकर : गत दो वर्षों में सरकार ने टैलीविजन की किस्म का ध्यान न रखते हुए अधिक संख्या में टेलीविजन तथा इलैक्ट्रानिक्स निर्माण पर जोर दिया। इससे पिक्चर ट्यूबों का अभाव हो गया। पिक्चर ट्यूब बनाने का एकाधिकार भारत इलेक्ट्रीकल्ज के पास है और उन्होंने भारी लाभ कमाया है। उन्होंने 335 रुपये में ट्यूब आयात करके वह 565 रुपये में बेची है और सरकार को 40,000 पिक्चर ट्यूबों का आयात करने के लिए विवश होना पड़ा। अब मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आयातित माल और उपकरणों के मनोरंजन इलेक्ट्रानिक्स पर निर्भरता कम करने क लिए सरकार क्या कदम उठाती है। दूसरे, क्या सरकार पर्याप्त विशेष अनुभव का दावा करने वाले लघु उद्योगों के दावों पर विचार करेगी ? ऐसे मामले में पिक्चर ट्यूब के निर्माण का कार्य लघु उद्योग को देना चाहिए। क्या रिजर्व बैंक की बिल विपणन सुविधायें लघु उद्योगों को उपलब्ध कराई जायेंगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि हम संकेत दे चुके हैं, हमारी नीति यह है कि हम विशिष्ट उपक्रम के उत्पादन/निष्पादन के आधार पर इन पिक्चर ट्यूबों का आवंटन करते हैं चाहे वे भारत में निर्मित की गई हों अथवा आयातित हों। जो पिक्चर ट्यूब उपक्रम को भेजी जाती हैं उनका उपयोग टेलीविजन निर्माण के लिए नहीं किया जाता है। उस मामले में टेलीविजन ट्यूबों का आवंटन उपयोग में लाया जा सकेगा।

अतः उत्पादन कार्यक्रम और कार्यकरण पर निर्भर रह कर हम इन पिक्चर ट्यूबों की अनुमति देते हैं। इनका अधिकांशतः समुचित उपयोग किया गया है। यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो माननीय सदस्य उसे मेरे ध्यान में लायें।

Shri Madhu Limaye : Whether it is a policy decision of the Government to produce picture tubes only in public sector; if not, the action being taken to increase its production? Whether Government are aware of the fact that some big companies purchased the picture tubes and sold them in black market ?

Shri Vidya Charan Shukla: Although the picture tubes will be mostly produced in public sector, we have allowed four firms to produce them. As I have already stated in my reply that two companies out of them have done commendable progress and their production will shortly come in market. So far as black marketing is concerned, we have not received any complaint in this regard. If there are any such instances, I would like to know that from the Hon. member and then we will look into the matter.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को प्रश्न संख्या 140 से मिलाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 140 को पेश करने वाले सदस्य भी यहां उपस्थित हैं। वह अपना प्रश्न भी पेश कर सकते हैं। श्री मधुकर यहां नहीं हैं। श्री लकप्पा।

श्री लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रोनिक्स को विकसित किया जा रहा है। किन्तु आज भी हम आयातित पिक्चर ट्यूबों पर निर्भर कर रहे हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इनका आयात क्यों कर रही है? क्या इसका कारण यह है कि भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड जो पिक्चर ट्यूबें बना रहा है वे अच्छे स्तर और अच्छी किस्म की नहीं हैं? इसके परिणामस्वरूप दूरदर्शन कार्यक्रम पर, जो कि विभिन्न राज्यों में चल रहा है, बरा प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि टलीविजन सैटों के निर्माण के विस्तार के लिए किस्म और मात्रा का ध्यान रखा जाएगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य की यह धारणा सही नहीं है कि प्रौद्योगिकी की अक्षमता या अन्य किसी कारण से पिक्चर ट्यूबों का निर्माण घट गया है। भारत इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा निर्मित पिक्चर ट्यूबें यदि आयातित पिक्चर ट्यूबों से बढ़िया नहीं हैं तो भी उनके समान ही अच्छी हैं। यदि उत्पादन घटा है तो इसका कारण यह है कि कर्नाटक सरकार ने बिजली की सप्लाई में कमी कर दी है। इसके अतिरिक्त कच्चे माल की भी कमी है।

श्री एम० एस० संजीवी राव : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार पिक्चर ट्यूबों की कमी को दर करने क लिए क्या कदम उठा रही है? मुझे समाचार पत्रों से पता चला है कि पश्चिम बंगाल सरकार भारत इलेक्ट्रानिक्स के सहयोग से एक दूरदर्शन ट्यूब फैक्ट्री स्थापित करने जा रही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार पिक्चर ट्यूबों के लिए ग्लास शेल्स के निर्माण के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने इन बातों का पहले ही उत्तर दे दिया है। देश में उत्पादित पिक्चर ट्यूबों की कमी के कारण हमने कुछ पिक्चर ट्यबों के आयात की अनुमति दी है। वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए इतनी ही पिक्चर ट्यूबें पर्याप्त हैं। पिक्चर ट्यूबों के लिए जहां तक ग्लास शेल्स का संबंध है, यह मामला हमारे विचाराधीन है और हमने ग्लास शेल्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं और आशा है कि हम शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय कर लगे। जैसे ही ऐसा हो जाएगा, हम इस क्षेत्र में आत्म निर्भर हो जायेंगे।

केरल में विदेशी स्वामित्व के बागान के राष्ट्रीयकरण पर अध्यादेश

*124. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में विदेशी स्वामित्व के बागानों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अध्यादेश जारी करने की स्वीकृति देने के प्रस्ताव पर, जो केरल सरकार ने प्रस्तुत किया था और जो केन्द्रीय सरकार के निर्णय के लिए कई वर्षों से विचाराधीन था, अंतिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में इस वर्ष अक्तूबर तक केरल सरकार तथा विधान सभा की वर्तमान कालावधि में निर्णय कर लेने का विचार है?

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) अभी नहीं, श्रीमान।

(ख) राज्य सरकार के प्रस्ताव के निहितार्थों की जांच के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त दल का गठन किया गया था। इस दल ने 3 फरवरी, 1975 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। दल की सिफारिशों को ध्यान में रख कर इस मामले में यथा शीघ्र कोई निर्णय किया जायेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने निराशाजनक उत्तर दिया है। यह प्रश्न गत चार वर्षों के दौरान इस सभा में 10 से अधिक बार उठाया गया है। इस पर हमने आधे घंटे की चर्चा भी की थी। प्रत्येक बार सरकार ने वही घिसा-पिटा उत्तर दिया। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या यह सही है कि सरकार केरल सरकार को बागानों के राष्ट्रीयकरण की अनुमति देना चाहती है ? अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन देने में चार वर्ष से अधिक समय लिया है। छः महीनों के बाद केरल सरकार के कार्य-काल की अवधि समाप्त होने जा रही है। क्या सरकार इस संबंध में निर्णय छः महीने की अवधि के पूरा होने से पहले ले लेगी या यह मामला अनिर्णित ही रहेगा ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह सही है कि इसमें कुछ समय लगा है। किन्तु यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे केरल के ही नहीं अपितु देश के सभी बागान प्रभावित होंगे। यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें 10 या 12 मंत्रालय अन्तर्ग्रस्त हैं। निस्संदेह इसमें कानूनी रुप से सक्षम होने के प्रश्न पर भी संदेह है। अतः श्रीमान इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक उच्च शक्ति प्राप्त दल की स्थापना की गई है। उन्होंने कुछ ही दिन पूर्व अपनी सिफारिशें पेश की हैं। उन पर वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जायेगा और बाद में अन्य संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके सरकार ठीक समय पर निर्णय लेगी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय यह क्या उत्तर दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी है, यह एक स्पष्ट उत्तर है। अब आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: उन्होंने वही उत्तर दोहराया है। मैं यह जानने के लिए उत्सुक नहीं था कि इस मामले में कितने मंत्रालय अन्तर्ग्रस्त हैं और सरकार किस ढंग से इस पर निर्णय लेना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने कह दिया है कि "अभी नहीं" तो आप कारण पूछिए। जब उन्होंने कारण बताये तो आपने उनमें कोई रूचि नहीं ली।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : चूंकि प्रधान मंत्री यहां है और चूंकि इस पर गृह मंत्री से प्रश्न पूछना व्यर्थ है, मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय लेने में रूचि रखती है ? श्रीमान यह एक महत्वपूर्ण मामला है। यही कारण है कि हम सरकार का निर्णय जानने के लिए उत्सुक हैं और यदि वे यह कह दें कि हम यथा सम्भव शीघ्र निर्णय ले लेंगे तो हम उनके आभारी होंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न गृह मंत्री को संबोधित है। आप प्रधान मंत्री से यह प्रश्न किस तरह पूछ सकते हैं ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : श्रीमान यह रूचि लेने अथवा न लेने का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न तो ऐसा है कि इसकी विभिन्न जटिलताओं की पूरी जांच की आवश्यकता है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्रीमान क्या यही उत्तर है ? आप उनसे ठीक उत्तर देने के लिए क्यों नहीं कहते ?

अध्यक्ष महोदय : आप यह तर्क मत दीजिये कि मैं भी अपनी राय व्यक्त करूं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : हम उत्तर जानना चाहते हैं । अन्यथा प्रश्न पूछने का क्या लाभ है ?

अध्यक्ष महोदय : वह आपको क्या बता रहे हैं ? यदि यह उत्तर नहीं है तो फिर क्या है ? वह आपकी पसंद का उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्रीमान गत चार वर्षों के दौरान दस बार यही उत्तर दिया गया है ।

श्री वसंत साठे : एक ही प्रश्न के लिए वही उत्तर होगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय गृह मंत्री ने श्री चन्द्रप्पन के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या सरकार की विदेशी स्वामित्व वाले बागानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई नीति है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को पता है कि कई बागान रुग्ण हो गए हैं और ऐसे में क्या सरकार की इन रुग्ण बागानों को अपने हाथ में लेने की कोई नीति है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब वे रुग्ण होंगे केवल तभी उन्हें अपने हाथ में लिया जाएगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार की इन बागानों के राष्ट्रीयकरण की कोई नीति है क्योंकि कई बार ऐसा कहा गया है और मैं नहीं जानता कि सरकार की वास्तविक नीति क्या है ? पश्चिम बंगाल में कई बागान हैं और सरकार ने कई बार कह दिया है कि उन्हें अपने हाथ में ले लिया जायेगा । किन्तु कुछ भी नहीं किया गया है । कोई कदम नहीं उठाया गया है । मेरा प्रश्न है कि सरकार विदेशी स्वामित्व वाले तथा भारतीय एकाधिकारियों के रुग्ण बागानों के बारे में क्या ठोस कदम उठा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आप का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं ? केरल में विदेशी स्वामित्व वाले बागानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में एक अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए अनुमति के बारे में स्पष्ट प्रश्न है । यदि यह रुग्ण बागानों के बारे में है तो यह दूसरी बात है । मेरे विचार से रुग्ण बागानों से गृह मंत्री का कोई संबंध नहीं है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्रीमान यदि आप श्री चन्द्रप्पन द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को देखें तो आप देखेंगे कि इसका संबंध कई मंत्रालयों से है । इतना ही नहीं, इसका संबंध समूचे भारत से है न कि केवल केरल से । इसीलिये मैंने यह प्रश्न पूछा है ।

श्री वसंत साठे : यह व्यर्थ का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न असली बात से बिल्कुल भिन्न है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय द्वारा अभी अभी दिये गए उत्तर में नई बात केवल यह है कि इस प्रश्न की जांच के लिए जो उच्च शक्ति प्राप्त दल नियुक्त किया गया था, उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है । विदेशी स्वामित्व वाले बागानों को अपने अधिकार में लेने का प्रश्न आखिर एक

नीति संबंधी प्रश्न है । यह स्पष्ट है कि यह कार्यकारी दल राष्ट्रीयकरण संबंधी बातों के अध्ययन के लिए स्थापित किया गया था क्योंकि कोई भी कर्यकारी दल नीति के प्रश्नों पर विचार नहीं करेगा । उसके लिए तो मंत्रिमंडल की समिति नियुक्त करने की सलाह दी जायेगी । चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने कार्यकारी दल नियुक्त किया इसलिए हमने यह सही कहा कि जहां तक अपने अधिकार में लेने के लिए नीति निर्णय का संबंध है, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और इस अध्ययन दल की नियुक्ति राष्ट्रीयकरण संबंधी विस्तृत बातों पर विचार करने के लिए की गई थी । इसी पर उन्होंने सरकार को प्रतिवेदन दिया होगा ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : आपने सही कहा है कि इन बागानों को अपने अधिकार में लेने के प्रश्न का मेरे मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है । यह तो वाणिज्य मंत्रालय का काम है । जहां तक कार्यकारी दल का संबंध है, इसे इस प्रश्न की जांच के लिए कहा गया था कि क्या केरल में विदेशी स्वामित्व वाले बागानों को अपने अधिकार में लेने में कोई औचित्य है अथवा नहीं ? इस पर उन्होंने अपना प्रतिवेदन पेश किया है जो कि वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे प्रश्न को टाला जा रहा है । कृपया सभा को इस तरह अंधेरे में मत रखिये । इस कार्यकारी दल को जिसमें कुछ मंत्रालयों के प्रतिनिधि थे, इस प्रकार के मामले पर नीति निर्णय लेने का कार्य नहीं सौंपा जा सकता था । अत: मैं इसे दो विभिन्न रूपों में जानना चाहता हूं । पहला नीति का प्रश्न है । क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है ? दूसरा पृथक प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रीयकरण संबंधी बातों पर विचार करने का कार्य इस दल को सौंपा गया था जिसने सरकार को अपना प्रतिवेदन दिया है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रोनिक्स मन्त्री, अन्तरिक्ष मन्त्री, योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : नीति के प्रश्न पर भी केवल तभी निर्णय किया जा सकता है जब सभी तथ्य उपलब्ध हों ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन तमाम वर्षों में आप तथ्यों को एकत्रित नहीं कर सके ? केरल सरकार कई वर्ष पहले तथ्य दिये थे ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : तथ्य केरल सरकार की एक विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन में दिए थे ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उन्होंने केरल की स्थिति के बारे में प्रतिवेदन पेश किया है । किन्तु निर्णय तो सारे देश की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना है न कि केवल केरल की स्थिति को । किसी भी निर्णय के विभिन्न रूपों में क्या-क्या परिणाम होंगे, अर्थात् इसका राज्य पर, हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव होगा ? इस प्रकार की कई बातों पर विचार करना है । स्थिति में परिवर्तन हो रहा है विशेष रूप से पिछले एक साल से । उदाहरण के लिए माननीय सदस्यों को मालूम है कि अन्य देशों में कई चाय बागान बन रहे हैं । इससे हमारे चाय बागानों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न जायेंगी । इन सब बातों पर विस्तार से विचार करना है ।

पांचवी योजना में उड़ीसा के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्वीकार की गयी प्रमुख परियोजनायें

*126. **श्री गजाधर मांझी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की कौन कौन सी मुख्य परियोजनायें किस किस स्थान के लिए स्वीकृत की हैं; और

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने कितनी धन राशि मंजूर की है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

पांचवीं योजना प्रारूप में शामिल केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत उड़ीसा में बड़ी परियोजनाओं के नाम तथा योजना में उनके लिए रखी गई राशि व स्थान निम्न प्रकार से है :—

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	परियोजना	स्थान	पांचवीं योजना प्रारूप में सुलभ परिव्यय
1	2	3	4
1.	राउरकेला इस्पात संयंत्र—बाधा-निरोधक व विविधीकरण परियोजनायें	राउरकेला	105.00
2.	फेरो बनाडियम परियोजना		10.00
3.	सरगीपल्ली लीड माइन	सरगीपल्ली	4.00
4.	सुकिन्दा निकिल परियोजना	सुकिन्दा	39.50
5.	तलचर उर्वरक परियोजना	तलचर	47.44
6.	परदीप बन्दरगाह का विकास	परदीप	16.25
7.	पोटेरु सिंचाई परियोजना	पोटेरु	13.28

उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त उड़ीसा में, विभिन्न उपक्रमों, जैसे कोयला खान प्राधिकरण, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लिए समेकित प्रावधान में से पूंजी-निवेश का एक भाग खर्च किया जाएगा तथा नई उर्वरक परियोजनाओं के लिए व्यवस्था की जाएगी ।

श्री गजाधर माझी : क्या राज्य सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान प्राथमिकता के आधार पर उड़ीसा में सरगीपाली में एक बड़े स्मेल्टर संयंत्र को स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : राज्य सरकार द्वारा भेजे गए सभी प्रस्तावों पर विचार किया गया है । सभा पटल पर रखे गए विवरण में हमने सुकिंज परियोजना का उल्लेख किया है जिसके लिये 39.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इस पर कार्यवाही की जा रही है और ज्यों ही इस मामले को अंतिम रूप दे दिया जायेगा तो हम इस परियोजना पर कार्य आरम्भ कर देंगे ।

श्री गजाधर माझी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार की राज्य सरकार की मांग पर विचार किया गया है ? और संयंत्र की परियोजना विविधीकरण से संयंत्र के विस्तार में कहां तक सहायता मिलेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : पांचवीं योजना की अवधि के दौरान राउरकेला संयंत्र के विस्तार अड़चन दूर करने, और विविधीकरण के लिए 105 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । मुझे यह पता नहीं है कि जमीन पर कितना कार्य कर लिया गया है अथवा नहीं । शायद इस संबंध में इस्पात और खान मंत्रालय कुछ संकेत दे सके । हमने इसके लिए प्रावधान कर दिया है और हम इसे उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : संतोष की बात है कि राज्य योजना को छोड़कर सरकार पांचवीं योजना के परिव्यय में से 145.47 करोड़ रुपये केन्द्रीय परियोजनाओं को देने के लिए सहमत हो गयी है । क्या कारण है कि लगभग 265 करोड़ रुपये की लागत की परादीप उर्वरक परियोजना को, जिस पर प्रारम्भिक कदम उठा लिए गए हैं, पांचवीं योजना की केन्द्रीय परियोजनाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है ? कोयला खान प्राधिकरण, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम आदि विभिन्न उपक्रमों से समेकित प्रावधान की कुल कितनी राशि है और पांचवीं योजना में उर्वरक परियोजनाओं के लिए कितना प्रावधान है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : परादीप उर्वरक कारखाने के लिए जो धन का प्रावधान किया गया है उसे विवरण में इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि इसके लिए पांचवीं योजना में एकमुश्त प्रावधान किया गया है । माननीय सदस्य को आश्वासन दिया जाता है कि उर्वरक परियोजना के लिए योजना मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली धनराशि में कमी नहीं की जायेगी । कुल प्रावधान की राशि के बारे में इस समय बताना मेरे लिए कठिन है । परादीप में उर्वरक परियोजना के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तथा कोयला खान प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली राशि काफी है । उड़ीसा में परियोजनाओं के विकास के लिए जो धन दिया जायेगा उसके बारे में मैं सही नहीं बता सकता किन्तु यह धनराशि पर्याप्त होगी ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : सरगीपाली सीसा खान परियोजना तथा सुकिंज निकल परियोजना 1970 में कट्टक उप-चुनाव के दौरान आरम्भ की गई थी । इस उप-चुनाव में वर्तमान मुख्य मंत्री प्रत्याशी थीं । सरगीपाली तथा सुकिंज में इन दोनों परियोजनाओं के लिए आधार शिलाएं रखी गई थीं । क्या मैं जान सकता हूं कि इन दोनों परियोजनाओं को पांचवीं योजना में क्यों रखा गया और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनकी आधार शिला काफी समय पूर्व रख दी गई थी इन पर कार्य चौथी योजना में आरम्भ क्यों नहीं किया गया ? क्या यह सब कुछ मतदाताओं पर प्रभाव डालने के लिए ही किया गया था, जैसा कि स्पष्ट है ? दूसरे 1971 में प्रधान मंत्री ने परादीप उर्वरक परियोजना की आधार शिला रखी थी . . . (**व्यवधान**) क्या यह भी मतदाताओं पर प्रभाव डालने के लिए ही किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं । नियम यह है कि आप सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं किन्तु यदि ऐसा हो जायेगा वैसा हो जायेगा आदि जैसी बातें मत करिये । हमने कई मामलों पर वाद-विवाद की अनुमति दी है । आप सीधा प्रश्न पूछिए ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं । विवरण में परादीप उर्वरक परियोजना को क्यों नहीं दिखाया गया है जबकि प्रधान मंत्री ने 1971 में उसकी आधार शिला रख दी थी । क्या यह सब मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया गया ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं आपको बता दूं कि इन परियोजनाओं को कट्टक में उप-चुनाव से बहुत पहले नियोजित कर लिया गया था। उस समय तो कट्टक में उप-चुनाव का कोई पता भी नहीं था। माननीय सदस्य द्वारा दो बातों को एक साथ जोड़ना बड़ा अनुचित है। परियोजना को पांचवीं योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : कहां ? आपके विवरण में इसे नहीं दिखाया गया है। तलचर तथा पारादीप में केवल दो ही उर्वरक संयंत्र हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित दोनों ही परियोजनाओं के बारे में मैंने उन्हें जानकारी दे दी है। परादीप उर्वरक संयंत्र के बारे में मैंने कहा है कि उसके लिए धनराशि की व्यवस्था एक मुश्त में की है और उसे पांचवीं योजना में सम्मिलित किया गया है। इसे स्थापित करने के लिए हमने कदम उठाये हैं। अतः शिला-न्यास रखने और उस पर कार्य आरम्भ न करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि मैंने कहा है इन पर देश के सामान्य विकास के लिए सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। इनका उप-चुनावों या आम चुनावों से कोई संबंध नहीं है चाहे वे कहीं भी हो रहे हों। और हम यह भी नहीं जानते कि जब इन परियोजनाओं को तैयार किया गया था तो उस समय चुनाव हो रहे थे या होने वाले थे।

हिन्दुस्तान कागज निगम के कार्यालय को नई दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित करना

*128. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कागज निगम के कार्यालय को नई दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी०पी० मौर्य): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हिन्दुस्तान कागज निगम के निदेशक मण्डल ने निगम के मुख्यालय के दिल्ली, कलकत्ता एवं अन्य किसी स्थान पर वैकल्पिक रूप में स्थापित किये जाने की अच्छाइयों और कमियों पर विचार करने के बाद यह निर्णय दिया कि मुख्यालय को हटाकर कलकत्ता ले जाना अपेक्षाकृत लाभप्रद होगा। इससे निगम उन नई परियोजनाओं से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा जिनमें से अधिकांश देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किए जाने की आशा है और जहां वन साधनों की बहुतायत है। इस प्रकार निगम प्रमुख मशीन निर्माताओं और निकट क्षेत्र में स्थित इन्जीनियरी उद्योग से निरन्तर घनिष्ट सम्बन्ध बनाए रख सकेगा।

कलकत्ता में किराए पर सस्ता कार्यालय स्थान मिल जाने और मुख्यालय के कार्यालय से परि-योजना स्थल तक दूरी कम होने से अधिकारियों के यात्रा व्यय से बचने वाली धनराशि से मुख्यालय के स्थानान्तरण पर होने वाले प्रारम्भिक खर्च की पूर्ति हो जाने की आशा है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मन्त्री महोदय ने हिन्दुस्तान कागज निगम को तीन साल के बाद दिल्ली से कलकत्ता ले जाने के जो कारण बताए हैं वे निराशाजनक तथा स्पष्ट नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : बेहतर यह है कि आप अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : इस बात का ध्यान में रखते हुए कि यह तीन वर्षों से यहां कार्य कर रहा था, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सरकार है या गौरमेन्ट ।

They consider after every minute.

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : दिल्ली में स्थिति अधिक अनुकूल है । कलकता में यह मंहगा पड़ेगा । उन्होंने 300 कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा **(व्यवधान)** आप लोग बीच में क्यों टोकते हैं ? आप इसे कलकत्ता या कहीं और या मास्को ले जाइये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मुझे अपना प्रश्न पूछने दीजिए ।

उन्होंने कर्मचारियों की सुविधा या कठिनाइयों तथा उनके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान नहीं रखा । वहां स्कूल का वर्ष जनवरी से आरम्भ होता है किन्तु दिल्ली में जून से आरम्भ होता है । उनके बच्चों का क्या होगा ? दिल्ली में आवास की व्यवस्था ठीक है । कलकत्ता मे पंखे और बिजली नहीं दो जाती जबकि दिल्ली में मकान मालिक ये सारी सुविधाएं देता है ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या एक ही व्यक्ति अर्थात् चेयरमैन की सुविधा के कारण ही हिन्दुस्तान कागज निगम कलकत्ता ले जाया जा रहा है ? यह व्यक्ति पिछले 30 वर्षों से थापर लोगों (व्यापार गृह) की सेवा में रहा है और क्या यह भी सही है कि उसे थापर से जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, गुप्त रूप से 3,000 रुपये का वेतन मिल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष को समुचित सूचना दिए बिना, कृपया किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो इस समय सभा में नहीं हैं, इस तरह के आरोप मत लगाइये ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : आपको इसमें क्या आपत्ति है ?

अध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद का समय नहीं है । मैं केवल आपके प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा हूं ।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री टी० ए० पाई): माननीय सदस्य के लिए सरकारी क्षेत्र के एक अधिकारी पर आरोप लगाना अनुचित है । इस आरोप को वह साबित भी नहीं कर सकते । जब इस निगम को यहां से कहीं भी ले जाने का निर्णय किया गया है तो उसमें किसी एक व्यक्ति की सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया है । जब हिन्दुस्तान कागज निगम बना था तो इसका अपना कोई कारखाना नहीं था । इसने पहला कारखाना जो अपने अधिकार में लिया वह मान्डया में था जो कि एक रुग्ण एकक था । पांचवीं योजना में इसने पहली बार नई परियोजनाएं ली हैं । एक केरल में तथा तीन पूर्वोत्तर क्षेत्र में । 1 नागालैंड में तथा 2 आसाम में । इन योजनाओं को समय पर चालू करने तथा इनका समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से यदि इसको कहीं अन्यत्र ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर निर्णय किया जाएगा । ऐसा करते हुए कर्मचारियों की कठिनाइयों को ध्यान में अवश्य रखा जायेगा और हम किसी को किसी तरह की कठिनाई नहीं पहुंचने देंगे ।

श्री मुं तयार सिंह मलिक : क्या आसाम में आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं को लोक निवेश बोर्ड ने अनुमति दे दी है और क्या इस तरह की परियोजनाएं देश के अन्य भागों में भी आरम्भ की जाएगी ?

श्री टी० ए० पाई : नागालैंड में 1 तथा आसाम में 3 परियोजनाओं को पांचवीं योजना में सम्मिलित किया गया है। लोक निवेश बोर्ड द्वारा स्वीकृति का दिया जाना उनके द्वारा परियोजना प्रतिवेदन पर विचार किए जाने पर निर्भर करता है। आसाम में भूमि आजित कर ली गई है और हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि परियोजनाएं आरम्भ की जाएं। यदि लोक निवेश बोर्ड किसी परियोजना की स्वीकृति नहीं देता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि परियोजना नहीं बनाई जायेगी। यह तो औपचारिकता की बात है जिसे पूरा करना ही है।

Shri Awadhesh Chandra Singh : When the office is shifted from one big city to another big city and projects are started in Nagaland and Assam, whether Government would consider to shift such office to a smaller place where staff do not face any difficulties and where the population is less ?

श्री टी० ए० पाई : मैं इस बात से सहमत हूं कि कार्यालय को एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर में ले जाने से समस्या हल नहीं होती। किन्तु जब कार्यालय को किसी छोटे स्थान पर ले जाया जायेगा तो कर्मचारियों की अपने बच्चों की पढ़ाई की समस्या पर भी विचार करना होगा।

श्री राम सहाय पांडे : निगम के निदेशक बोर्ड ने अपना कार्यालय दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है। क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने वन संसाधनों तथा अन्य उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कागज उद्योग की स्थापना करके पूर्वी भाग के विकास को ध्यान में रखा है ? निर्णय करने से पूर्व क्या उन्होंने वहां जाने वाले कर्मचारियों के संदर्भ में कलकत्ता की आवास की अत्यधिक कठिन समस्या पर उपयुक्त ध्यान दिया है ?

श्री टी०ए० पाई : निर्णय पर सरकार ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है। वस्तुतः हमें यह देखना होगा कि योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तम ढंग कौनसा है; क्या पंजीकृत कार्यालय को स्थानान्तरित करना आवश्यक है अथवा प्रत्यक परियोजना के लिए नियुक्त किये जाने वाले पदाधिकारियों को परियोजनाओं के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाए ? हम यह महसूस करते हैं कि अन्तिम निर्णय करने से पूर्व इन पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

श्री मोइनुल हक चौधरी : सरकारी क्षेत्र में शुरु की जाने वाली परियोजनाएं देश के पूर्वी क्षेत्र में, उदाहरणार्थ आसाम और नागालैंड में तैयार हो रही हैं और सरकार ने त्रिपुरा तथा मनीपुर में शुरु होने वाली परियोजना के बारे में निर्णय किया है। ये सभी परियोजनाएं पूर्वी क्षेत्र—आसाम, त्रिपुरा मनीपुर और नागालैंड में स्थापित की जा रही हैं। वहां सभी वन संसाधन उपलब्ध हैं। सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि निर्माण स्थल और संसाधनों की सामीप्यता को ध्यान में रखते हुए कार्यालय दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित कर दिया जाए। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यालय को कलकत्ता की बजाय आसाम में स्थानान्तरित क्यों नहीं किया जाता जबकि आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह अभ्यावेदन भेजा है कि यदि कार्यालय स्थानान्तरित किया जाना है तो उसे आसाम में ही किया जाये क्योंकि वहां न केवल निर्माण-स्थल निकट होंगे बल्कि वहां पर उपलब्ध वन संसाधन भी समीप होंगे ?

कलकत्ता को प्राथमिकता देने की बात मुझे समझ नहीं आई। इससे केवल अधिकारियों के विमान किराये में कुछ रुपयों की बचत होगी। इससे कार्य कुशलता नहीं बढ़ेगी। मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस कार्यालय को आसाम में स्थानान्तरित करने पर विचार करें।

एक माननीय सदस्य : कार्यालय शिलांग में स्थानान्तरित किया जाए।

श्री मोइनुल हक चौधरी : मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है। वहां कई खाली मकान हैं और कर्मचारियों के बच्चों के लिए अच्छे विद्यालय, महाविद्यालय एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं।

श्री टी० ए० पाई : अन्ततः हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का सम्बन्ध केवल योजना एवं समस्त प्रशासन से है। प्रत्येक परियोजना के लिए, चाहे वह आसाम में हो या त्रिपुरा में, केरल में अथवा मध्य प्रदेश में, एक प्रशासनिक कार्यालय होगा। मेरे विचार में सभी क्षेत्रों की मांग इस प्रकार पूरी की जा सकेगी। यह आवश्यक नहीं है कि केन्द्रीय कार्यालय विशिष्ट क्षेत्र में स्थापित किया जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय के कथनानुसार आसाम में दो तथा नागालैंड में एक नई परियोजना की स्वीकृति दी गई है ...

एक माननीय सदस्य : त्रिपुरा में भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका यहां इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। मुख्यालय की स्थापना कहीं भी की जाए, उसके निष्पादन की समीक्षा बाद में की जाएगी। लेकिन कागज की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए, क्या अन्य परियोजनाएं भी विचाराधीन है और विशेषकर मेघालय, मनीपुर, त्रिपुरा तथा उत्तरी बंगाल में जो कि अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है अथवा सरकार केवल आसाम तथा नागालैंड में ही एक एक परियोजना शुरु करेगी ?

श्री टी० ए० पाई : पश्चिम बंगाल में भी परियोजना स्थापित की जा सकती है। योजना आयोग ने मनीपुर में दो लघु परियोजनाओं तथा त्रिपुरा में एक परियोजना के सर्वेक्षण के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश-बस्तर में बड़ी परियोजना की भी सम्भावना है। प्रत्येक परियोजना पर पूंजीगत लागत के रूप में 100 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसीलिए हमारी पहली समस्या यह है कि इन तीन परियोजनाओं को किस प्रकार एक साथ शुरु किया जाए और शीघ्रता से पूरा किया जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आखिरकार परियोजनाएं बड़ी भी हो सकती है और मध्यम एवं लघु भी। क्या प्रत्येक पर 100 करोड़ रुपये व्यय आएगा ? छोटी परियोजनाएं भी शुरु क्यों नहीं की जाती ?

श्री टी० ए० पाई : बड़ी संख्या में लघु कागज परियोजनाओं में कृषि अपशिष्टों को देश के विभिन्न भागों में पुनः उपयोग करने के लिये लाइसेंस दिए गए हैं। कुछ ही वर्षों में उनके द्वारा 80,000 टन उत्पादन करने की आशा है।

छत्तरपुर, उड़ीसा के निकट उद्योग समूह

*129. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में छत्तरपुर के निकट उद्योग समूह की स्थापना करने के बारे में 20 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1272 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तरपुर उड़ीसा के निकट उद्योग समूह की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) क्या परियोजना के कार्य के निष्पादन के लिये वित्तीय संस्थाओं का एक समूह गठित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) समुद्र तट की रेत में विद्यमान खनिजों पर आधारित एक उद्योग समूह की स्थापना छत्तरपुर के पास करने के प्रस्ताव पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है ।

श्री अर्जुन सेठी : इससे पूर्व इस प्रश्नका उत्तर देते हुए प्रधान मन्त्री ने बताया था कि भूमि अर्जन, परामर्श प्रबन्ध तथा अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में कम्पनी प्रारम्भिक कार्य-वाही कर रही है । इस संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भूमि का अर्जन कर लिया गया है एवं परामर्श प्रबन्ध कर लिए गए हैं और यदि हां, तो यह उद्योग समूह कब तक तैयार हो जाएगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : भूमि अर्जित कर ली गई है । इस परियोजना को शुरु करने के लिए हमने परामर्शदाता नियुक्त कर दिए हैं । इस मामले में कुछ प्रगति हुई है ।

श्री अर्जुन सेठी : पूंजी निवेश की दृष्टि से इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सम्भाव्यता प्रतिवेदन अभी तक विचाराधीन है और वित्तीय पहलू के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि उद्योग समूह के निर्माण के प्रथम चरण पर 32.30 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है जिसमें 3.15 करोड़ रुपये कार्यकारी पूंजी भी शामिल है । निस्संदेह इसमें विदेशी पूंजी का अंश भी होगा । लेकिन जब तक पूरे आंकड़े न पता चल जाएं और सरकार उसको अनुमोदित न कर दे तब तक मैं नवीनतम आंकड़े नहीं बता सकता ।

श्री जगन्नाथ राव : प्रत्येक माह या दो माह में रेडियो पर यह घोषणा की जा रही है कि रेत से खनिज निकालने की परियोजना छतरपुर में स्थापित की जाएगी । मन्त्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि सब कुछ तैयार है । मैं जानना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के निकट उद्योग शुरु करने में क्या बाधा है ? क्या संसाधनों की कमी इसका कारण है अथवा इसका कारण यह है कि गोपालपुर लघु पत्तन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ? परियोजना पूरी करने के मार्ग में क्या वास्तविक बाधाएं हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वास्तव में कोई बाधा नहीं है । हम इस मामले में सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि यह एक बड़ा उद्योग समूह है और जब तक हम सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से न चलें, गलती होने की सम्भावना है जो महंगी पड़ सकती है । अतः एक नये प्रकार की परियोजना शुरु करते समय गति का थोड़ा धीमा होना स्वाभाविक है ।

Shrimati Sahodra Bai Rai: Whenever any scheme is formulated for Madhya Pradesh, six months are taken in its assessment and entire money is spent and after that venue of the scheme is shifted to Calcutta and other places. With regard to the scheme formulated for Chhatar Pur, I would like to know whether it is not the case that after six months the venue of the scheme is shifted to another place ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is not the Chhatar Pur of Madhya Pradesh to which the hon. Member has referred to.

Shrimati Sahodra Bai Rai : Then set it up in Chhatar Pur of Madhya Pradesh also.

Shri Vidya Charan Shukla : I would like to say that there is no proposal to shift the venue of the scheme.

पश्चिमी बंगाल में टी० वी० सेटों का उत्पादन करने के लिए इलैक्ट्रोनिक्स आयोग के पास अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र

*130. **श्री आर० एन० बर्मन**: क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में टी० वी० सैटों का उत्पादन करने के लिए भारी संख्या में आवेदन पत्र इलैक्ट्रोनिक आयोग के पास दो वर्षों से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो अनिर्णीत पड़े ऐसे आवेदन पत्रों की कुल संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसे लाइसेंस जारी न करने की वजह से पश्चिम बंगाल के टी० वी० ग्राहकों को केवल दिल्ली के निर्माताओं का आश्रय लेना पड़ता है और इस प्रकार टेलीविजनों की एक व्यापक मांग टी० वी० सैटों के वर्तमान निर्माताओं के लिए ही सुरक्षित है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल में टी० वी० सैटों के उत्पादन हेतु कोई आवेदन पत्र इलैक्ट्रोनिक्स विभाग अथवा इलैक्ट्रोनिक्स आयोग के पास अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री आर० एन० बर्मन: मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न नहीं किया है। मैंने पूछा था कि क्या आवेदन-पत्र दो वर्ष से विचाराधीन पड़े हैं अथवा नहीं ? मन्त्री महोदय ने बताया है कि कुछ भी विचाराधीन नहीं है। कुछ भी हो, सच तो यह है कि आवेदन-पत्र दो वर्ष से विचाराधीन हैं और जब पश्चिम बंगाल में टेलीविजन की सुविधा शुरू की जाएगी, बजार में कोई राज्य-निर्मित टेलीविजन सैट नहीं होगा और लोगों को दिल्ली, पंजाब, बम्बई और अन्य स्थानों से टेलीविजन खरीदना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि आवेदन पत्र कब प्राप्त हुए, कब स्वीकृति दी गई और कितनी क्षमता की अनुमति दी गई और इन फर्मों द्वारा बनाए गए टेलीविजन सैट कब तक बजार में आ जायेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी आसानी से दी जा सकती है। इन यूनिटों को लाइसेंस देने के मामले में पश्चिम बंगाल के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। पश्चिम बंगाल में 7 एककों को लाइसेंस दिए गए हैं और आशा है कि वे प्रति वर्ष 20,000 सेट बनाएंगे। यह कार्य लगभग तमिलनाडु की भांति ही होगा और चूंकि उनकी क्षमता में विस्तार किया जा सकता है, हम आशा करते हैं कि जब भी विस्तार होगा और विस्तार की गई क्षमता का प्रयोग किया जाएगा, पश्चिम बंगाल में उत्पादन 40,000 सैट तक पहुंच जाएगा। इससे कलकत्ता टेलीविजन केन्द्र स्थापित होने से उत्पन्न मांग पूरी हो सकेगी। इसीलिए माननीय सदस्य

को ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि टेलीविजन एककों के मामले में पश्चिम बंगाल अथवा पूर्वी क्षेत्र के विरुद्ध कोई पक्षपात बरता गया है।

श्री आर० एन० बर्मन : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि देश में टेलीविजन सैटों के निर्माण में हम विदेशी आयात पर किस हद तक निर्भर हैं और क्या यह सच है कि टेलीविजन ट्यूबों के लिए 'ग्लास शेल्स' के निर्माण के बारे में भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की योजना त्याग दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में पहले ही जानकारी दे दी है कि योजना को छोड़ा नहीं गया है और हम तत्परता से मामले पर कार्यवाही कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हम शीघ्र ही पिक्चर ट्यूब और 'ग्लास शैल' एकक स्थापित कर सकेंगे।

श्री पीलू मोदी : क्या सरकार की यह नीति है कि टेलीविजन सैटों का निर्माण केवल उन्हीं राज्यों में किया जाये जिनमें उनका प्रयोग किया जा रहा है ? जिस गम्भीरता से उन्होंने उत्तर दिया उससे तो ऐसा ही लगता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार की यह नीति नहीं है। हमने विभिन्न एककों को लाइसेंस दिए हैं। लेकिन साथ ही यह भी वांछनीय है कि उन क्षेत्रों के एककों को लाइसेंस दिए जाएं जहां टेलीविजन केन्द्र लगे हुए हैं और टेलीविजन दर्शक हैं। हमने सारे देश में एककों को लाइसेंस दिये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मैसर्स न्यूमेटिक (इन्डिया) और मैसर्स ईस्टर्न मशीनज़ सेल्ज, कलकत्ता के कार्य की जांच

*121. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मैसर्स न्यूमेटिक (इण्डिया) और मैसर्स ईस्टर्न मशीनज़ सेल्ज कलकत्ता द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ किए 14 लाख रुपये के धोखाधड़ी के मामलों की कोई जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई मुकदमा चलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा): (क) से (ग) समझा जाता है कि तात्पर्य राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड से है राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से नहीं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत मैसर्स ईस्टर्न मशीन सेल्स, कलकत्ता सहित किराये पर लेने वालों में से कुछ ने मैसर्स न्यूमेटिक (इंडिया)

कलकत्ता को जिंक प्लेटिंग प्लांट/आटोमेटिक पंच टेप प्लांट की सप्लाई के लिये आवेदन-पत्र दिया था। पार्टियों ने मैसर्स न्यूमेटिक (इण्डिया), कलकत्ता को जिन मशीनों के लिए आवेदन पत्र दिया था वे आवेदनों को राष्ट्रीय लघु निगम लिमिटेड द्वारा प्राप्त करके दे दी गई थी । निगम को बाद में पता चला कि सप्लाई की गई मशीनों के दाम बहुत बढ़ा दिये गये थे और वे मशीनें उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं थी जिसके लिए कि वे खरीदी गई थी।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा यह बात केन्द्रीय जांच ब्यूरो को बता दी गई थी जो इस मामले की जांच कर रहा है ।

सीमेंट का उत्पादन

*122. **श्री वरके जार्ज :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में सीमेंट का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इस अवधि में देश की आन्तरिक मांग कितनी रही और कितनी मात्रा में सीमेंट निर्यात किया गया; और

(ग) घरेलू मांग तथा निर्यात दायित्वों को पूरी तरह पूरा करने के लिए सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) 1973-74 में सीमेंट का कुल उत्पादन 146.10 लाख मी० टन हुआ था। इस उत्पादन में से 130246 मी० टन सीमेंट का निर्यात किया गया तथा शेष सीमेंट की खपत देश में हुई थी । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सीमेंट उद्योग विषयक कृतिक दल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 1973-74 में सीमेंट की कुल मांग 190 लाख मी० टन के लगभग थी ।

वर्तमान क्षमता में से अधिकतम सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए सीमेंट को नियमित रूप से रेल द्वारा लाने ले जाने की समीक्षा की जाती है जिससे ढुलाई में कठिनाई महसूस कर रहे कारखानों की यथा संभव सहायता की जा सके। ऊर्जा मन्त्रालय के अधीन कोयला विभाग में कोयले के संबंध में एक स्थायी संपर्क समिति (स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी) की स्थापना कर दी गई है तथा उनकी कोयले की आवश्यकताओं का पता लगा कर सीमेंट के विभिन्न कारखानों को कोयला क्षेत्रों से सम्बद्ध कर दिया गया है । सीमेंट के विभिन्न कारखानों को प्रत्येक 10 दिनों की कोयले की सप्लाई की संवीक्षा करने के लिये कलकत्ता में एक मानटरिंग सेल बनाया गया है। सीमें कारखानों को कोयले की ढुलाई में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए इस मन्त्रालय में भी एक सेल बनाया गया है। जिन कारखानों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई नहीं हुई थी उन्हें सरकार ने भट्टी का तेल प्रयोग करने की विशेषरूप से अनुमति दी थी जिससे कि वे अपनी क्षमता का और अधिक उपयोग कर सकें।

अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए 202.50 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस तथा आशयपत्र जारी कर दिए गए हैं । इस अतिरिक्त क्षमता में से 1975 के अन्त तक 18.60 लाख मी० टन की क्षमता कार्यान्वित हो जाने की संभावना है।

पी० टी० आई० को सरकारी निगम में बदलना

*125. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० टी०आई० को सरकारी निगम में बदलने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल): (क) से (ग) समाचारपत्रों को बड़े व्यापार घरानों के हितों से असम्बद्ध करने के प्रश्न के साथ समाचार एजेन्सियों को सरकारी निगम में बदलने के प्रश्न की जांच तथ्य अन्वेषण समिति द्वारा हाल ही में सरकार को दी गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।

'सुपर पावर स्टेशन'

*127. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल**: क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति ने देश के बिजली संकट को दूर करने के लिए सुपर पावर स्टेशन बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक तकनीकी ज्ञान तथा धनराशि के अभाव में परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष ने ऐसे निर्णय का विरोध किया है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, अन्तरिक्ष मन्त्री, योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली सदर बाजार के दंगों सम्बन्धी प्रसाद आयोग का प्रतिवेदन

*131. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव**
श्री भान सिंह भौरा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सदर बाजार के दंगों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त प्रसाद आयोग ने इस बीच अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो जांच आयोग के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) आयोग की रिपोर्ट की जांच हो रही है।

Transmission Loss of Electricity in India

*132 **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether India suffers 27 percent loss in transmission of electricity whereas it is 7 per cent to 12 per cent in the case of other countries ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to reduce this loss?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) The average loss in transformation, transmission and distribution including losses due to energy unaccounted for during the year 1973-74 was about 19.4 percent.

(b) The main reasons for higher transmission and distribution losses in India as compared to other developed countries are :

(1) low power factor operation due to large incidence of industrial loads and agricultural pumping loads ;

(2) low load density and long lengths of distribution lines in rural areas; and

(3) inadequate distribution system.

The transmission and distribution losses also include a certain element of unaccounted energy due to pilferage etc.

(c) The question of high transmission and distribution losses has been studied by the Power Economy Committee in 1971. Again in 1974 the Ministry of Energy had appointed another Committee to study in depth and suggest remedial measures. On the basis of the recommendations of these Committees, the Ministry of Energy have advised the various State Electricity Boards to formulate time-bound programmes to reduce energy losses through installation of shunt-capacitors strengthening of transmission lines and erection of new sub-stations. For system improvement, the Rural Electrification Corporation, is advancing loans, the main objective being to reduce the transmission and distribution losses. For checking the pilferage of electricity, the Ministry of Energy has made a number of suggestions to the State Electricity Boards such as appointment of vigilance squads and modifications of metering arrangements so as to avoid tampering.

Instructions issued by Prime Minister's Secretariat to Ministries to show advance copies of statements to be made by Ministers in Parliament to Prime Minister

***133. Shri Atal Bihari Vajpayee**
Shri Madhu Limaye :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether her attention has been drawn to the news item published in a local English Daily dated the 24th December, 1974 that a circular was issued by the Prime Minister's Secretariat to all Ministries on the 28th October,1974 saying that the Prime Minister would like to see advance copies of all statements to be made by the Ministers in the Parliament as also of briefs for answering supplementary questions, if any; if so, the text of the circular ;

(b) whether she had denied in the Lok Sabha on the 4th December, 1974 that any such circular was issued; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Space, Minister of Planning and Minister of Science and Technology (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir. A copy of the circular issued by the Prime Minister's Secretariat on 28th October, 1974 is placed on the Table of the House.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Copy of The Circular

IMMEDIATE

PRIME MINISTER'S SECRETARIAT

(Pradhan Mantri Sachivalaya)

No. 56(43)/74-*Parl.* *New Delhi*-110011
October 28, 1974.

OFFICE MEMORANDUM

The undersigned is directed to say that as in the past, the Prime Minister would like to see advance copies of all statements to be made in Parliament by Ministers as also of briefs for answering supplementary questions, if any. The Ministries are, therefore, requested to forward four copies of such statements and briefs to this Secretariat as soon as they are finalised. During working hours these copies may kindly be sent to Shri B.N. Tandon, Joint Secretary to the Prime Minister, in Room No. 8, Parliament House and at the Prime Minister's House after working hours and on holidays.

Sd-
(B.M. Malhotra)
Section Officer

To

All Ministries/Departments of the Government of India.

पंजाब और हरियाणा के सीमा सम्बन्धी दावों को निपटाने के लिए सीमा आयोग

*134. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा के एक दूसरे के क्षेत्र पर दावे का न्याय-निर्णय करने के लिये हरियाणा ने शीघ्र ही सीमा आयोग नियुक्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी): (क) और (ख) यद्यपि हरियाणा के मुख्य मन्त्री से इस संबंध में हाल में कोई पत्र नहीं मिला है तथापि एक सीमा आयोग नियुक्त करने के बारे में संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

आशयपत्रों/लाइसेंसों के लिए मध्य प्रदेश से प्राप्त अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र

*135. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने के लिये आशय पत्रों और लाइसेंसों के लिए प्राप्त अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों की संख्या और तारीख क्या है ;

(ख) उनमें से कितने आवेदन पत्र सहकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने के लिए हैं और कितने मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के अधीन उद्योगों के लिए हैं; और

(ग) उनमें से कितने आवेदन पत्र चीनी मिलों या खण्डसारी मिलों की स्थापना के लिए हैं और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) मध्य प्रदेश में उद्योग चालू करने के लिये 26 औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन-पत्र अनिर्णीत हैं। इन आवेदन-पत्रों में से 24 आवेदन-पत्र 1974 के दौरान भिन्न भिन्न तारीखों को व दो जनवरी, 1975 में प्राप्त हुए थे।

(ख) इन अनिर्णीत आवेदन-पत्रों में से एक सहकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में है और दूसरा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(ग) आवेदन पत्रों में से एक नरसिंहपुर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) में प्रति दिन 1,250 मीट्रिक टन गन्ना पेरने की क्षमता वाला एक नया सहकारी चीनी का कारखाना स्थापित करने के लिए दिया गया है।

धन की अपर्याप्तता का डाक तथा तार विभाग के विस्तार कार्यक्रमों पर प्रभाव

*136. **श्री विजयपाल सिंह**
श्री रामसहाय पांडे :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग धन की अपर्याप्तता के कारण अनेक विस्तार कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्या हैं ;

(ग) क्या इसी कारण से, देश में बने टेलीफोन और दूर संचार उपकरणों की देश में बहुतायत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) ऊपर (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

आई०टी०आई० में इन्टरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन के शेयर

*137. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की इण्टरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन द्वारा आई० टी० आई० लिमिटेड, बंगलौर में अपने शेयर छोड़ देने के मामले में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

रोजगार बढ़ाने सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों में रोजगार के अवसर पैदा करना

*138. **श्री कुमार मांझी :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों से इस प्रकार की रिपोर्टें मिली हैं कि रोजगार बढ़ाने सम्बन्धी कार्यक्रम से आशाओं के अनुरूप रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो सके हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र से कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह बताया गया हो कि सम्भावित स्तर तक रोजगार सुलभ करने में रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है। परन्तु कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समुचित संगठनात्मक और बुनियादी आधार की सुविधाओं के निर्माण में विलम्ब हुआ है।

उत्तर प्रदेश में नरोरा में परमाणु बिजलीघर

*139. **श्री नरसिंह नारायण पांडे :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में नरोरा में परमाणु बिजलीघर की स्थापना के प्रस्ताव को अब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक यदि कोई प्रगति हुई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, अन्तरिक्ष मन्त्री, योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) माल गोदाम, कंक्रीट की प्रयोगशाला, संयंत्र स्थल को जाने वाली सड़कों इत्यादि का निर्माण जैसे प्रारम्भिक कार्य संयंत्र स्थल पर शुरू किये जा चुके हैं। परियोजना स्थल के इर्द गिर्द आधे मील के अर्ध व्यास में पड़ने वाले क्षेत्र के बड़े भाग तथा टाउनशिप के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। मुख्य संयंत्र का डिजायन तैयार किया जा रहा है। टर्बो--जनित्र एवं भाप-जनित्रों के निर्माण के लिये आशय पत्र जारी किये जा चुके हैं। आयात की जाने वाली केलेन्ड्रिया, एंड-फिटिंग, इत्यादि जैसी ऐसी सामग्री; जिसकी डिलीवरी में लम्बा समय लगेगा, को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों के लिए "ग्लास शैल्स" बनाने हेतु संयंत्र

*140. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक्स आयोग के विशेषज्ञों ने टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों के लिए "ग्लास शैल्स" बनाने हेतु एक संयंत्र की स्थापना करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, अन्तरिक्ष मन्त्री, योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) मामले पर विचार हो रहा है।

सरगुजा में निम्न ताप कार्बनीकरण संयंत्र

1201. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री सरगुजा में निम्नताप कार्बनीकरण संयंत्र के बारे में 4 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त निम्न तापीय कार्बनीकरण संयंत्र के प्रस्ताव पर सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार सहित अन्य संबद्ध प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। मध्य प्रदेश सरकार को सलाह दी गई कि वे कोयला खान प्राधिकरण तथा केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के परामर्श से संशोधित साध्यता अध्ययन रिपोर्ट भेजें। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में ऐसे क्षेत्र जिनमें कोयला न निकाला गया

1202. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में ऐसे क्षेत्र जिनमें कोयला न निकाला गया के बारे में 27 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2238 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) तथा (ख) आसनसोल से प्रकाशित "कोल फील्ड ट्रिबून" के 19 अक्टूबर, 1974 के अंक में "नेग्लैक्टेड बांकुरा कोल माइन्स" शीर्षक से एक लेख निकला था। इसमें बांकुरा जिले की बन्द खानों को फिर से खोलने की आवश्यकता बताई गई थी।

इस जिले में ऐसी दस छोटी खानें हैं जो कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत हैं। ये हैं :—अर्धग्राम खास, न्यू अर्धग्राम, गोपालपुर, चकबागा खास, हमीरपुर, जमुना कनाली, न्यू कालिकापुर, कालीदासपुर, बांसकुरी तथा खिरतोरी खास। इनमें से केवल प्रथम तीन ही काम कर रही हैं; शेष खानें बन्द होने के कारण काफी पहले त्याग दी गई थीं।

यद्यपि उपर्युक्त लेख में, जिसमें कोयला सर्वेक्षण सलाहकार समिति के निष्कर्षों को दर्शाने वाली 1897 की निरीक्षण रिपोर्टों का उल्लेख था, त्यागी गई खानों में कोयला होने की बात कही गई है तथापि

कोयला खनन की पूर्ण कालिक खुदाई की योजना बनाने के लिए उपलब्ध भू-वैज्ञानिक आंकड़े अभी भी अपर्याप्त हैं। तीन चालू खानों में से दो खानों---अर्धग्राम खास तथा न्यू अर्धग्राम में भी अब भण्डार बहुत कम समय तक चलने वाले हैं। बिजली सप्लाई, रेलवे साइडिंग तथा पहुंच मार्गों जैसी आधारभूत सुविधाएं भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं। इस क्षेत्र की कई खानें दामोदर नदी के बाढ़-बहुल क्षेत्र में स्थित होने के कारण मौसमी प्रकार की होंगी।

कोयला खान प्राधिकरण कालीदासपुर कोयला खान को पुन: खोलने के लिए साध्यता अध्ययन कर रहा है परन्तु आवश्यक आधार भूत सुविधाओं के न होने तथा खानों के मौसमी स्वरूप के कारण हो सकता है कि इस खान को अथवा अन्य बन्द खानों को शीघ्र खोलना संभव न हो।

पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिलें के मेजला क्षेत्र में कोयला सर्वेक्षण सलाहकार समिति द्वारा किया गया सर्वेक्षण

1203. **श्री टुना उरांव** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला सर्वेक्षण सलाहकार समिति को पश्चिम बंगाल में, बांकुरा जिले के मेजला क्षेत्र में नये और उपयोगी कोयला संसाधनों का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो कोयला सर्वेक्षण सलाहकार समिति द्वारा अब तक किये गए सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) बांकुरा जिले के मझिया क्षेत्र में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने 11 स्थानों पर क्षेत्रगत बोरिंग किया। इस क्षेत्र में 7 मुख्य कोयला पट्टियां क्षेत्रीय आधार पर विकसित की गई हैं जिनकी मोटाई 0.68 से 9.79 मीटर (बंधों सहित) है। बंधों को छोड़कर पट्टियों की किस्म श्रेणी II से लेकर श्रेणी- IV (भा०मा०प०) तक है। भारतीय मानक पद्धति के अनुसार 1.2 मीटर तथा अधिक मोटाई वाली पट्टियों में 480 मीटर तक की अधिकतम गहराई तक 1808.40 लाख टन कोयला भण्डार आंका गया है।

Rural Electrification in Ladakh

1204. **Shri Kushok Bakula:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether a large part of Leh and Kargil and other parts of Ladakh have not yet been electrified:

(b) whether electricity arrangements in those parts of Ladakh which are presently electrified, are also not satisfactory ;

(c) whether the villages of Ladakh have almost been left untouched under the rural electrification programme ;

(d) the programme of electrification of Ladakh on a large scale in the coming years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कापियों की कमी

1205. **श्री एम० एम० जोजफ**
श्री बरके जार्ज :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में छात्रों को कापियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो छात्रों को उचित मूल्यों पर कापियां उपलब्ध करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) हाल में, देश के किसी भी भाग से कापियों की कमी के बारे में जानकारी नहीं मिली है । सरकार ने एक वितरण प्रणाली बनाई है उसके अनुसार कागज उद्योग शैक्षणिक क्षेत्र के लिये नियत उचित मूल्य पर प्रति वर्ष 1,20,000 मी० टन छापने के सफेद कागज की उपलब्धि कराने के लिए सहमत हो गया है । इस मात्रा में से विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित राज्य स्तर की समितियों द्वारा कापियां बनाने वाले को कागज दिया जा रहा है ।

इंडियन ह्यूम पाइप कम्पनी को क्रयादेश

1206. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी को सी० एम० डी० ए० और इंदौर जल सम्भरण परियोजना को पाइप सप्लाई करने के बहुत अधिक क्रयादेश प्राप्त हुए हैं और कम्पनी उक्त क्रयादेशों की मांग पूरा करने के लिए अपने संयंत्र का विस्तार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी ने स्पेन की 'टोसा' कम्पनी से तकनीकी सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) क्या उक्त सहयोग पर सहमति हो गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी०पी० मौर्य) : (क) से (ग) कलकत्ता मेन्ट्रोपालिटन डेवलपमेंट अथारिटी ने सी०एम० डी०ए० द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न जल संभरण योजनाओं के लिए प्रि स्ट्रेस्ड कंक्रीट प्रेशर पाइपों के निर्माण और सप्लाई का कार्य मै० इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी लि० को सौंप दिया है । इस संबंध में मै० इण्डियन ह्यूम पाइप कं० लि० ने स्पेन की कम्पनी टी० ओ० एस० ए० की ओर से डा० काइलोज कारवाजरल से तकनीकी सहयोग करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है और सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। मै० इण्डियन ह्यूम पाइप कं० लि० ने कहा है कि इस सहयोग से प्राप्त की जाने वाली जानकारी का उपयोग क्रंकीट पाइपों की सप्लाई और पाइप बिछाने का इन्दौर जल सम्भरण परियोजना सहित देश की अन्य जल संभरण योजनाओं के लिए भी किया जाएगा ।

Provision for Rural Electrification in Madhya Pradesh in Fifth Plan

1207. **Shrimati V. R. Scindia** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the provision included in the current Fifth Five Year Plan for electricity supply in rural areas of Madhya Pradesh and the share of the Centre and the States in this outlay; and

(b) the officers responsible for taking decision as to which of the villages of a particular district in a particular State should be electrified during a particular financial year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) The size and content of the Fifth Plan has not yet been finalised. However, in the draft plan an outlay of Rs. 20 crores has been proposed under normal State Plan for rural electrification in Madhya Pradesh. Besides, an outlay of Rs. 55 crores has been proposed under Minimum Needs Programme. Additive finances would also be provided by the Rural Electrification Corporation Ltd. which has been set up in the Central Sector. The assistance from this Corporation would depend upon the number of schemes sponsored by the State Electricity Board and approved by the Corporation in accordance with the norms and guidelines prescribed by it.

(b) The decision regarding the selection of villages for electrification is taken by the concerned State Electricity Board.

चंडीगढ़ का दर्जा

1208. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा सरकारों ने चंडीगढ़ पर अपना दावा छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इसे स्थायी रूप से राज्य क्षेत्र घोषित करने का है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) इस मामले में पंजाब तथा हरियाणा सरकारों के विचारों में किसी परिवर्तन की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shifting of Head Office of Bharat Coking Coal Ltd. from Dhanbad to Calcutta

1209. **Shri Shankar Dayal Singh**

Sardar Swaran Singh Sokhi :

Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the reasons for shifting the Head Office of Bharat Coking Coal Ltd. from Dhanbad to Calcutta when coal transactions take place mainly at Dhanbad which is a central place from all points of view ;

(b) whether Bihar Government have ever suggested to Government to have the Head Office at Dhanbad; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Sidheshwar Prasad): (a) to (c) The State Government have expressed concern over speculative reports in the press about shifting of the head-quarters of Bharat Coking Coal Ltd. from Bihar. The matter was also raised in State Legislative Council on 13-12-1975. There is, however, no decision to shift the Head Office of Bharat Coking Coal Ltd. from Dhanbad ot Calcutta.

उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्गों के लिए वर्ष 1975-76 में राज्य को विशेष वित्तीय सहायता

1210. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्गों के लिए वर्ष 1975-76 के लिए पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाओं के लिए राज्य को विशेष वित्तीय सहायता देने पर विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर किए जाने की संभावना है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश के निर्धारित जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वर्ष 1975-76 के दौरान विशेष वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार की सहायता की सुनिश्चित मात्रा पर विचार किया जा रहा है।

डाकघर का दर्जा बढ़ाया जाना

1211. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित अवधि के अन्दर डाकघर का दर्जा बढ़ाने में विभाग के असफल रहने और बाद में एन० आर० सी० में वृद्धि करने के कारण एन० आर० सी० की राशि को मय व्याज के वापस करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मन्डी जिले की ग्राम पंचायत ने धारा 80 के अन्तर्गत डाक-तार अधिकारियों को नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो अगर धनराशि का उचित रूप से निवेश किया जाता तो जो ब्याज प्राप्त होता, उसे ध्यान में रखे बिना ही अधिक मात्रा में एन० आर०सी० की राशि की मांग करने और डाक-घर का दर्जा बढ़ाने में असफल रहने के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एन०आर०सी० की राशि में वृद्धि न करने के लिए डाक-तार विभाग ने कोई निर्देश जारी किया है जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति से बचा जा सके ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) ऐसा कोई नोटिस अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा विदेशों में मशीनी औजार कारखाने स्थापित करना

1212. **श्री वेकारिया**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने विदेशों में मशीनी औजार कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उन कारखानों की स्थापना कब की जायेगी; और

(ग) इस संबंध में मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का विदेशों में मशीन टूल कारखाना स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। फिर भी, उन्होंने कोलम्बो (श्री लंका) के मै०सिलोन स्टील कारपोरेशन तथा फिलीपाइन, मनीला की मशीन टूल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के साथ हिमट के तकनीकी सहयोग से मशीन टूल कारखाना स्थापित करने में उनकी सहायता करने के लिए कुछ तकनीकी सहायता करार किया है।

एम्पलिफायर और स्पीकरों का निर्माण करने वाली कम्पनियां

1213. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टीरियो सिस्टम एम्पलिफायर और स्पीकर बनाने वाली भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों के नाम क्या क्या हैं; और

(ख) क्या विदेशी कम्पनियों को विशेष प्राथमिकता दी गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रोनिक्स मन्त्री, अन्तरिक्ष मन्त्री, योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जो कम्पनियां स्टीरियों सिस्टम, एम्पलीफायर तथा स्पीकर निर्मित कर रही हैं, उनके नाम परिशिष्ट एक और दो में दिये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-9016/75]**

(ख) इन मदों के विषय में विदेशी कम्पनियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। इसके विपरीत, सरकार ने मनोरंजन के लिये एम्पलीफायरों (जिनमें स्टीरियो एम्लीफायर भी शामिल हैं) का निर्माण तथा लाउड स्पीकरों का सज्जीकरण अनन्य रूप से लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए (फरवरी, 1974) से आरक्षित कर दिया है। बड़े पैमाने का जो कारखाना इन मदों का उत्पादन करना चाहता है, उसे अपने वार्षिक उत्पादन की कम से कम 75% मात्रा का निर्यात करना पड़ेगा। इस प्रकार इन मदों का स्वदेशी उत्पादन बड़े घरों और विदेशी साम्य मैजोरिटी कम्पनियों दोनों की प्रतिद्वन्दिता में आने से बच जाता है।

Short Supply of News print

1214. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether newsprint is still in short supply ;

(b) if so, whether the production capacity of Government paper mills has been increased; and

(c) the time upto which short supply of newsprint is likely to continue ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Yes, Sir. Lately the position, however, has shown some improvement.

(b) The production capacity of the NEPA Mills will increase after the expansion scheme currently under implementation is completed.

(c) We are keeping a watch on the international supply position. The time upto which short supply of newsprint is likely to continue cannot be anticipated at present as a forecast is difficult.

राज्यों में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सहायक कार्यालयों की स्थापना

1215. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में संकट ग्रस्त मिलों को चलाने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सहायक कार्यालयों की स्थापना करने का निर्णय किया है; और तथा

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कपड़ा मिलों का प्रबन्ध करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नौ सहायक निगमों का पंजीकरण किया गया है। इन सहायक निगमों के नाम और स्थान संलग्न विवरण में दिये गये हैं। इनमें से छः निगमों ने कार्य शुरु कर दिया है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा राज्यों में स्थित राष्ट्रीकृत मिलों को शीघ्र ही बम्बई और कलकत्ता के सहायक निगमों को स्थानान्तरण करने का अनुमान है ।

विवरण

क्रम सं०	सहायक निगम का नाम	स्थान
1.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) लि०	दिल्ली
2.	—वही— (उत्तर प्रदेश)	कानपुर
3.	—वही— (मध्य प्रदेश)	भोपाल
4.	—वही— (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा)	कलकत्ता
5.	—वही— महाराष्ट्र (उत्तर)	बम्बई
6.	—वही— महाराष्ट्र (दक्षिण)	बम्बई
7.	—वही— (गुजरात)	अहमदाबाद
8.	—वही— (तमिलनाडु और पांडीचेरी)	मद्रास
9.	—वही— (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और मही)	बंगलौर

त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधारों को लागू करना

1216. **श्री दशरथ देब** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों में लागू किये जाने वाले प्रशासनिक सुधारों के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे सुधारों का स्वरुप क्या है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन): (क) और (ख) त्रिपुरा सरकार समेत राज्य सरकारों से 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए उप-योजनाएं तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा अनुरोध किया गया है। उनसे अपने प्रशासनिक ढांचे का भी पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया गया था ताकि यह कार्यान्वियन के लिए प्रभावी माध्यम बन सके। त्रिपुरा की उपयोजना पर योजना आयोग ने हाल ही में विचार-विमर्श किया था और राज्य सरकार से उसे संशोधित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

भारत तथा अन्य देशों में तापीय बिजली घरों का कार्यकरण

1217. **डा० के० एल० राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत, अमरीका ब्रिटेन तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण देशों में तापीय बिजलीघर प्रतिवर्ष औसत में कितने घंटे काम करते हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : नीचे की सारणी में विश्व के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय औसतन यूनिट उत्पादित/किलोवाट प्रतिष्टापित प्रतिवर्ष दिए गए हैं :—

	1968	1969	1970	1971
जापान	5475	5636	5674	5236
ब्रिटेन	3823	4199	4072	4001
अमेरिका	4687	4670	4586	4388
सोवियत रूस	4658	4659	4603	4789
पोलैंड	4905	4788	4775	4857
भारत	3369	3410	3625	3994

Sharing of Atomic know-how with Neighbouring Countries

1218. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) whether Government propose to share knowledge of atomic explosion and atomic know-how with neighbouring countries; and

(b) if so, the steps : so far taken in that direction ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Space, Minister of Planning and Minister of Science and Technology (Shrimati Indira Gandhi). (a) Government is willing to collaborate with friendly countries in the field of peaceful uses of atomic energy ;

(b) We already have collaboration agreements with Afganisthan and Bangladesh.

हंगरी को कोक भट्टी संयंत्र की सप्लाई

1219. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय विशेषज्ञ दल भारत द्वारा एक पूरे कोक भट्टी संयंत्र की सप्लाई किय जाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए हंगरी का दौरा करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड के पास उक्त संयंत्र का कार्य करने की पर्याप्त क्षमता है ;

(ग) क्या किसी अन्य यूरोपीय देश ने भी भारतीय विशेषज्ञता के लिए अनुरोध किया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) एक भारतीय विशेषज्ञ दल ने दिसम्बर, 1974 में पूर्ण कोक भट्टी संयंत्र की सप्लाई की संभावना पर विचार विमर्श करने के लिए हंगरी का दौरा किया था।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां । यूरोप के एक और देश ने भारत से कोक भट्टी उपकरण खरीदने की इच्छा व्यक्त की है ।

मिजो नेशनल फ्रन्ट द्वारा लन्दन में समन्वय सैल का खोला जाना

1220. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जनवरी, 1975 को कलकत्ता के एक अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसके अनुसार बर्मा के अराकान पहाड़ी क्षेत्रों में मिजो विद्रोहियों, मिजोरम के मिजो विद्रोहियों और इस समय कराची में रह रहे मिजो नेशनल फ्रन्ट के प्रधान श्री लाल डेंगा के बीच सम्पर्क कायम करने के लिए मिजो नेनेनल फ्रन्ट ने लन्दन में एक समन्वय सल की स्थापना की है; और

(ख) क्या इस समाचार के बारे में जांच की गई है और इसके सही या गलत होने के बारे में पता लगाया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान । जांच से ऐसे किसी सैल के होने का पता नहीं चला है ।

कोयला खान प्राधिकरण और भारत कोकिंग कोल लि० की कोयला खानों में दुर्घटनायें

1221. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 1974–75 के दौरान कोयला खान प्राधिकरण को पूर्वी डिवीजन में प्राधिकरण की कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं की संख्या और उसके परिणामस्वरूप होने वाली मौतों की संख्या लगभग दुगुनी हो गई है ;

(ख) क्या भारत कोकिंग कोल लि० और कोयला खान प्राधिकरण में मौतों और ऐसी दर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद महानिदेशक ने संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध केवल कुछ मामलों में ही जांच शुरु की है; और

(ग) यदि हां, तो क्रमश: वर्ष 1972, 1973, 1974 के दौरान कोयला खान प्राधिकरण, भारत कोकिंग कोल लि० और गैर सरकारी क्षेत्र की अन्य कोयला खानों में कितनी दुर्घटनायें हुईं और प्रत्येक के विरुद्ध कितने मामलों में अभियोजन की कार्यवाही की गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) देश की सभी कोयला खानों में 1972 से 1974 के बीच हुई घातक और गम्भीर दुर्घटनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	घातक	गम्भीर
1972	200	1540
1973	173	1904
1974	201	1394 (सितम्बर, 74 तक)

(नोट : 1973 और 1974 के आंकड़े अनंतिम हैं) ।

खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा 1972 और 1974 के बीच देश की सभी कोयला खानों के संबद्ध प्राधिकारियों के विरुद्ध चलाये गए अभियोजनों की संख्या निम्नलिखित है :—

1972	273
1973	226
1974 (सितम्बर, 74 तक)	97

वजन करने वाली मशीनों का विदेशों को निर्यात

1222. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मीट्रिकेशन एण्ड मीट्रोलोजी (भार तथा माप) संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में माप लेने के लिए हाल ही में भारत आये कुछ विदेशी प्रतिनिधि मण्डलों ने भारत में बनने वाली वजन करने की मशीनों का उन देशों को निर्यात करने के लिए अपनी रुचि दिखाई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या वजन करने की मशीनों तथा वजन करने के अन्य उपकरणों के लिए कोई क्रयादेश मिले हैं और बुक किए हैं ;

(ग) निर्यात की जाने वाली इन मशीनों की अनुमानित लागत क्या है और क्या भुगतान विदेशी मुद्रा में होगा या वस्तु विनिमय पद्धति के आधार पर; और

(घ) उसके परिणामस्वरूप अनुमानत: कितना लाभ अर्जित किया जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चूंकि सम्मेलन लगभग एक पखवाड़ा पहले ही समाप्त हुआ है, इसलिए विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा दिखाई गई रुचि के अनुसरण में भारत में बनाई जाने वाली वजन करने की मशीनों के निर्यात के लिए सुनिश्चित पूछताछ और आदेश मिलने के कुछ समय बाद ही मूल्यांकन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आय में कमी

1223. **श्री निम्बालकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी उस श्वेत पत्र की ओर ध्यान दिया है जिसमें भारत की राष्ट्रीय आय में वर्ष 1972–73 के दौरान 0.9 प्रतिशत की कमी दिखाई गई है; और

(ख) सरकार का इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। 1972–73 में राष्ट्रीय आय में 0.9 प्रतिशत गिरावट आई। किन्तु 1973–74 में राष्ट्रीय आय में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की दर में वृद्धि करने के लिए जिस व्यापक नीति और उपायों को अपनाए जाने का प्रस्ताव है उन्हें पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में स्पष्ट किया गया है।

1974–75 की वार्षिक योजना राष्ट्रीय आय की दर में वृद्धि करने के लिए तैयार की गई थी। इस सम्बन्ध में अपनाए गए विशेष उपाय सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज में बताए गए थे। अन्य बातों के साथ आंतरिक उत्पादन में वृद्धि को तीव्र करने के लिए 1975–76 की वार्षिक योजना तैयार की जा रही है तथा वर्तमान सत्र में यह दस्तावज सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कोयले का उत्पादन

1224. **श्री एस०आर० दामाणी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में 31 दिसम्बर, 1974 तक कोयले का उत्पादन कितना हुआ तथा इससे पूर्व वर्ष की इसी अवधि में उत्पादन कितना था तथा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में इस उत्पादन का प्रतिशत क्या था ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : चालू वर्ष में अप्रैल से दिसम्बर तक कोयले का उत्पादन 624.50 लाख टन हुआ है जबकि 1973–74 के दौरान इसी अवधि में 567.80 लाख टन उत्पादन था। 1973–74 तथा 1974–75 वर्षों की अप्रैल–दिसम्बर तक की अवधियों की वास्तविक उपलब्धि संबंधित वार्षिक लक्ष्यों के 69.4% तथा 71% के बराबर हुई है।

कालीनदी पन बिजली परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाना

1225. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा**
श्री के० मालन्ना

श्री जी०वाई० कृष्णन :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कालीनदी पन बिजली परियोजना को राष्ट्रीष्य परियोजना बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Electrification of Rural Areas in M.P.

1226. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether the progress in regard to electrification of rural areas for irrigation purposes, particularly in Madhya Pradesh, is not satisfactoy; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps being taken by Government to improve the position in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) & (b) The progress in regard to electrification of rural areas for irrigation purposes, in Madhya Pradesh, has been satisfactory. Against a target of 50,000 pumpsets, 1,13,673 pumpsets had been energized in the State during the Fourth Plan period.

मोदी फ्लोर मिल्स के विरुद्ध आरोप

1227. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी फ्लोर मिल्स के डायरेक्टर तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एक गोदाम में 'लोखाबाह्य' गेहूं रखने के लिए इस बीच आरोप लगा दिये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस मामले का शीघ्र निपटारा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 और 9 के अधीन दण्डनीय अपराध करने के लिए दिनांक 6 जनवरी, 1975 को नई दिल्ली के मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा सर्वश्री एस० के० मोदी, जी० डी० गोयल तथा एस० पी० जैन और एस० के० मोदी के माध्यम से पटियाला फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड को आरोप पत्र दिए गए थे ।

(ग) अभियुक्तों ने आरोपों का खण्डन करने के लिए 5 फरवरी, 1975 को दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की । इसी दौरान उन्होंने विचारण-न्यायालय में, कार्यवाही रोकने के लिए भी आवेदन दिया । 6-2-75 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्यवाही रोकने के आवेदन में नोटिस देने के साथ मुख्य आपराधिक विविध याचिका में 4 मार्च, 1975 के लिए नोटिस जारी

करने का आदेश दिया। तब तक मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कार्यवाही रोकने का आदेश दिया।

दक्षिण कनारा जिले में 'कोरगा' जनजाति के लोग

1228. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के दक्षिण कनारा जिले में 'कोरगा' जनजाति के लोग हैं जो शोषण तथा छूतछात के शिकार बने हुए हैं; और

(ख) क्या उन तरीकों का अध्ययन किया गया है जिनके द्वारा शेष समाज इन जनजाति लोगों का शोषण करता है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और जब प्राप्त होगी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जामनगर के निकट ढुलकोट में एक पुजारी द्वारा हरिजन लड़के की पिटाई द्वारा मार डालना

1229. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1975 के अंतिम सप्ताह में जामनगर के निकट ढुलकोट में एक पुजारी ने एक हरिजन लड़के की इतनी पिटाई की जिससे उस लड़के की मृत्यु हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यह आरोप है कि 29 जनवरी, 1975 को जामनगर जिले के जोड़िया तालुक के ढुलकोट गांव में हनुमान मंदिर के पुजारी ने एक हरिजन लड़के को पीटा जिसके परिणामस्वरूप लड़का घायल हो गया और उसे जामनगर के इर्विन अस्पताल में पहुंचाया गया जहां 30 जनवरी, 1975 की सुबह उसकी मृत्यु हो गई। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/325 तथा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम की धारा 3 व 7 के अधीन पुजारी के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया और उसे 30 जनवरी, 1975 को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट दी गई है कि मामले की जांच पूरी हो गई है और आशा है शीघ्र ही अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।

ढुलकोट ग्राम पंचायत ने मृतक लड़के की मां को 101 रु० की नकद राशि राहत के रूप में दी है। जामनगर जिला पंचायत ने भी उन्हें पंचायत निधि से 1000 रु० की धन राशि स्वीकृति की है। जोड़िया के मामलातदार ने उन्हें 30 रु० प्रति माह भुगतान करने का प्रबन्ध किया है।

हरिजनों पर अत्याचारों के मामलों में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

1230. **श्री अमर सिंह चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में हाल ही में न्यायालय के निर्णयों के अंतर्गत कुछ दोषी व्यक्तियों को हरिजनों तथा अन्य पिछड़े समुदायों के मकानों को आग लगाने, उन की हत्यायें करने तथा उन पर आक्रमण करने और अत्याचार करने के कारण कठोर दंड दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों का तथा दिए गए दंड का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर सरकार और जनता की क्या प्रतिक्रया है ;

(घ) क्या सरकार उन व्यक्तियों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील करेगी जिन्हें छोड़ दिया गया है अथवा मामूली दंड दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ङ) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 22 जून, 1974 की घटना के कारण पैदा हुए मामले में जिसमें सुरेन्दर नगर जिले के रनमलपुर गांव के दो हरिजन मारे गए थे , दोषी व्यक्तियों को कठोर दंड दिया गया है । घटना के बारे में सूचना 7 अगस्त, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 247 के उत्तर में इस सदन में दी गई थी । 30 जनवरी, 1975 को सेशन जज, नरोल, अहमदाबाद द्वारा इस मामले में निर्णय दिया गया था जिसमें 123 दोषी व्यक्तियों में से 17 को दण्ड दिया गया था । दो महिलाओं समेत पांच व्यक्तियों को आजीवन कारावास तथा अन्य 12 को चार वर्ष की कैद की सजा दी गई है । शेष 106 दोषी व्यक्ति दोषमुक्त कर दिये गए हैं । फैसले की जांच करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील करने के प्रश्न पर निर्णय लिया जायेगा । आशा की जाती है कि इस मामले में दी गई सजा से उन सभी पर जो छूआछूत बरतते हैं, निवारक प्रभाव पड़ेगा ।

आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग करने के बारे में राज्यों को अनुदेश

1231. **श्री पी० ए० स्वामीनाथन**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वर्ष 1973 से नजरबन्द एक तस्कर के विरुद्ध पेश बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में 27 जनवरी, 1975 को निर्णय देते समय सरकार को यह आदेश दिया कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग अत्यन्त सावधानी के साथ किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सम्भवत: 1974 की रिट याचिका संख्या 349–तुलसी रविदास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य–पर दिनांक 27-1-1975 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय का हवाला दिया गया है । पश्चिम बंगाल के प्राधिकारियों ने तुलसी रविदास की खाद्यान्नों की तस्करी से संबंधित कुछ गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए समाज के लिये आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं को बनाये रखने के लिए उसे प्रतिकूल ढंग से कार्य करने से रोकने के लिए असुका के अधीन उसे नजरबन्द किया था । उच्चतम न्यायालय ने उसकी रिट याचिका रद्द कर दी परन्तु सरकार की ओर से दाखिल किए गए प्रति-शपथपत्र की कुछ कमियों का संदर्भ देते हुए अन्य बातों के साथ यह उल्लेख किया कि असुका के अधीन सरकार तथा उसके अधिकारियों को दी गई विशिष्ट शक्तियों का जब कभी अवसर उत्पन्न हो प्रयोग किया जाना अभीष्ट है परन्तु उसका प्रयोग सावधानी से करना है । श्रीमान न्यायाधीशों ने आगे कहा कि इस

शक्तियों का खाद्य तथा ऐसी ही आवश्यक वस्तुओं के संवेदनशील क्षेत्र में समाज के संरक्षण के हितकारी प्रयोजन के लिए प्रयोग होना चाहिए। यदि इस क्षेत्र में असफलता होती है तो अधिकारियों को अवश्य डांटना चाहिए क्योंकि इसका शिकार होता है देश तथा समाज और इस पर उच्च स्तर स नजर रखनी चाहिए ताकि आसुका का उद्देश्य वैधता की अवहेलना अथवा आन्तरिक कार्यकरण में उदासीनता से निष्फल न हो।

सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्णय की एक प्रति उनके मार्ग-दर्शन तथा नजरबन्द करने वाले प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए भेजी जा रही है।

कर्नाटक में 'जीता' (गुलाम) प्रथा का समाप्त किया जाना

1232. **श्री के० मालन्ना**
श्री जी०वाई० कृष्णन :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक ने राज्य के कुछ भागों में व्याप्त 'जीता' (गुलाम) प्रथा को समाप्त करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के लेखा अधिकारी के विरुद्ध जांच

1233. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखा अधिकारी, श्री पी० पी० गम्भीर के विरुद्ध वर्ष 1972 से जांच पड़ताल कर रहा था ;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पड़ताल के आधार पर उक्त अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच करने का आदेश दिया गया था ;

(ग) क्या निगम के प्रबंध निदेशक ने सचिव को तरजीह न देकर, जो वित्त प्रभाग के प्रशासन के प्रमुख अधिकारी हैं तथा निगम के सतर्कता अधिकारी भी हैं। निगम के एक पुनर्नियुक्त तकनीकी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के पुराने रेलवे सहयोगी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उक्त लेखा अधिकारी को मुअत्तिल नहीं किया गया तथा उसे विभागीय जांच की अवधि के दौरान काम पर आने की तथा सरकारी कागजात और फाइलों संबंधी कार्य करने की अनुमति दी गई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस जांच का निर्णय क्या है तथा मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) श्री कृष्णन्, जो इस समय राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में 2250–2750 रु० के वेतन मान में विशेषज्ञ (इंजीनियरी उपकरण) के रूप में कार्य कर रहे हैं और जिनका सेवाकाल 4 नवम्बर, 1975 तक बढ़ा दिया गया है, इस मामले की जांच का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में नियुक्त होने से पूर्व वह भारतीय रेलवे में कार्य कर रहे थे।

यह भी कहा जा सकता है कि जांच अधिकारी की नियुक्ति के मामले में आवश्यक यह समझा जाता है कि अधिकारी काफी वरिष्ठ पद का होना चाहिए और जिसे दोषी अधिकारी के प्रति किसी प्रकार का झुकाव न हो और जिसे इससे पूर्व किसी भी अवस्था पर मामले के गुणावगुणों पर राय व्यक्त करने का अवसर न मिला हो। श्री कृष्णन ये सारी बातें पूरी करते थे। सचिव को जो निगम का सतर्कता अधिकारी भी है, जांच अधिकारी नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता—विशेष-रूप से इसलिए कि सतर्कता अधिकारी की हैसियत से सचिव ने मामले की प्रारम्भिक अवस्था पर जांच की थी और उसे मामले के गुणावगुणों पर राय व्यक्त करने का अवसर मिल चुका था। यह कहना भी सच नहीं है कि निगम के सचिव के मुकाबले श्री कृष्णन् को तरजीह देकर जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

(घ) चूंकि केवल मामूली जुर्माना करने के लिए अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्य-वाही की गई है और अधिकारी को मुअत्तिल नहीं किया गया है। फिर भी, अनुशासनिक कार्य-वाही पर निर्णय होने तक उन्हें निगम के लेखा अनुभाग से ऋण अनुभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(ङ) यह जांच श्री पी० पी० गम्भीर द्वारा झूठी रसीद के आधार पर अधिक मकान किराया भत्ता लेने से सम्बद्ध है। जांच की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

बोगस छोटे उद्योग

1234. **श्री वी० मायावन**
डा० हरिप्रसाद शर्मा :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 दिसम्बर, 1974 को बम्बई में अखिल भारत निर्माता संघ के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई गणना से पता चला है कि देश में 33 प्रतिशत छोटे उद्योग बोगस हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस गणना के तथ्य क्या हैं; और

(ग) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० शर्मा) : (क) अखिल भारतीय निर्माता संगठन के सदस्यों के साथ बंबई में 27–12–74 को हुई बैठक में मैंने इस बात का संकेत दिया था कि सरकार द्वारा शुरू की गई लघु औद्योगिक एककों की गणना से यह पता चलता

है कि इस प्रकार के एककों में से काफी बड़ी संख्या में एकक या तो बंद पाये गए हैं अथवा जिन-का पता नहीं चल रहा है या उन्होंने अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में की गई गणना का प्रारंभिक विश्लेषण करने से निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है ।

1. गणना में अब तक शामिल एककों की सख्या	2,32,846
2. जिन एककों का पता नहीं चल सका है	23,907
3. वे एकक जिनका पता लग गया है पर स्थायी रूप से बंद हो गए हैं	53,963
4. उत्तर न प्राप्त होने वाले एककों की संख्या	3,775
5. उन एककों की संख्या जिनमें 1972 के बाद कार्य प्रारम्भ हुआ है	9,247

(ग) राज्य सरकारों को लघु उद्योग एककों की गणना की अवधि में कार्य न करते हुए पाए गए एककों को रजिस्टर से काट देने की सलाह दी गई है ।

राज्य की वार्षिक योजना परिव्यय में उड़ीसा राज्य का हिस्सा

1235. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975–76 में उड़ीसा के लिए योजना परिव्यय हेतु 89 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है :

(ख) यदि हां, तो इसमें राज्य सरकार का हिस्सा कितना है ;

(ग) क्या राज्य आन्तरिक संसाधनों को जुटाकर अपने हिस्से को पूरा करेगा ; और

(घ) मदवार वे विभिन्न शीर्षक कौन-कौन से हैं उसके लिए इस परिव्यय को मंजूर किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) राज्य सरकार के वार्षिक योजना 1975–76 के लिए 104·81 करोड़ रुपये के प्रस्तावों के प्रारूप पर योजना आयोग में विचार-विमर्श हो चुका है । इन विचार-विमर्शों तथा संसाधनों की सुलभता को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना के आकार को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों की बिक्री

1236. **श्री वयालर रवि**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों का कुछ प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र में बेचने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस प्रकार का निर्णय करने के क्या कारण हैं और इस दिशा में पहले क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) परियोजना को गठित करते समय सरकार ने निर्णय किया था कि 51 प्रतिशत शेयर सरकार के होंगे

और बाकी शेयर जनता में बांट दिये जायेंगे। स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड का विचार 215 लाख रुपये तक जो इसकी 500 लाख रुपये की जारी की गई कुल पूंजी का 43 प्रतिशत है अपनी अंग पूंजी के लिए आम जनता से अभिदान आमंत्रित करने का है। जनता से आवेदनपत्र प्राप्त होने के पश्चात शेयरों का आवंटन किया जायेगा और यथासंभव व्यापक रूप से शेयरों को बांटने का प्रयत्न किया जाएगा। यह प्रस्ताव भी है कि जैसा पूंजी निर्गम नियंत्रक ने स्वीकृत किया है, 200–200 शेयरों तक कम्पनी के कर्मचारियों को शेयर प्रस्तावित किये जायेंगे।

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज के कारखानों की स्थापना

1237. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज के कारखाने स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो उनकी स्थापना किस तिथि तक होने की संभावना है ;

(ख) उन पर कितनी लागत आयेगी और प्रत्येक की उत्पादन क्षमता क्या होगी; और

(ग) क्या इन कारखानों में उत्पादन शुरु होने के पश्चात देश अखबारी कागज के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :(क) और (ख) केन्द्र सरकार का महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज का उत्पादन करने का कारखाना स्थापित करने का कोई भी विचार नहीं है। फिर भी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में अखबारी कागज बनाने वाले संयंत्र स्थापित करने के लिये निम्नलिखित योजना के लिए स्वीकृति दी गई है :—

नाम	राज्य	क्षमता	अनुमानित विनियोजन
1. वेस्टकोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	30,000 मी० टन प्रतिवर्ष	35 करोड़ रुपये
2. मै० सूरज इंडस्ट्रियल पैकिंग लि०	उत्तर प्रदेश	60,000 मी० टन प्रतिवर्ष	75 करोड़ रुपये† †बताये गए निवेश में लिखाई और छपाई का कागज तथा अखबारी कागज के साथ-साथ रेयन ग्रेड की लुग्दी का उत्पादन करने के लिए परियोजना अनुमान भी सम्मिलित है।

3. मैं० रामगंगा पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०	उत्तर प्रदेश	30,000 मी० टन प्रतिवर्ष	पार्टी द्वारा संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किये जाने हैं।
4. मैं० बलारपुर पेपर एण्ड स्ट्राबोर्ड मिल्स लि०	हिमाचल प्रदेश	60,000 मी० टन	100 करोड़ रुपये

अखबारी कागज उद्योग की प्रारम्भिक स्थापना अवधि लम्बी होती है और इसमें से किसी भी एकक में पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में उत्पादन शुरू होने की सम्भावना नहीं है। योजना का सम्भरण अवधि में देश में उत्पादन आवश्यकता से काफी बना रहेगा।

Firings in the Country by C.R.P. and B.S.F.

1238. **Shri Jambuwant Dhote** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of times Central Reserve Police and Border Security Force, opened fire in encountering disturbances in various parts of the country during this year and during the last year and the number of persons died as a result thereof ;

(b) the number of cases in which judicial enquiry was instituted; and

(c) the action taken against the culprits in each case ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) During the period from 1st January 1974 to 31st January 1975 the BSF and the CRPF,while on internal security duties with the State Governments/UT Admns. in various parts of the country resorted to firing 54 times. As a result of these firings, 26 persons were reported to have died.

(b) & (c) Judicail inquiries were instituted in two cases. The reports of the Inquiry Commissions are still awaited.

राष्ट्रीय चलचित्र वित्त विकास निगम

1239. **श्री प्रिय रन्जन दास मुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय चलचित्र निगम की स्थापना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या चलचित्र वित्त निगम, के बजट में कोई वृद्धि करनी आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो चलचित्र वित्त निगम की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) मैमोरैंडम आफ एसोसिएशन और आर्टिकल्ज आफ एसोसिएशन तैयार कर लिए गए हैं। कम्पनियों के रजिस्ट्रार ने आर्टिकल्ज आफ एसोसिएशन की पड़ताल कर ली है और मैमोरैंडम आफ एसोसिएशन की पड़ताल कर

रहा है। निगम का रजिस्ट्रेशन औपचारिकतायें मुकम्मल होने के पश्चात् शीघ्र ही मार्च, 1975 तक हो जायेगा।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के वजूद में आने के बाद, फिल्म वित्त निगम की भूमिका का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के पूरे ढांचे और उसके कार्यों को ध्यान में रखते हुए पुनर्विलोकन किया जायेगा और समिति निर्णय तदनुसार लिये जायेंगे।

फिल्म समारोह के आयोजकों द्वारा की गई कथित अनियमितताएं

1240. **श्री भागीरथ भंवर**
श्री शशि भूषण
श्री जगन्नाथराव जोशी
श्री आर०वी० बड़े :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि दिल्ली में पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन करने में मन्त्रालय के अधिकारियों ने बहुत सी अनियमितताएं की हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस आरोप पर भी ध्यान दिया है कि यह समारोह जनता के लिए न होकर अधिकारियों के लिए अधिक था; और

(ग) यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है और इन अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) यह सच्चाई से बहुत दूर है। समारोह जनता और फिल्म निर्माताओं के लिए था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक की कथित टिप्पणी

1241. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक, श्री राज कृष्ण सेठी के उस सद्धरण की जानकारी है जो जनवरी, 1975 की मासिक पत्रिका 'डेबीनेयर' (खंड 4 संख्या 1) में प्रकाशित श्री लुइस एस० आर० वास के 'टोटल करप्शन' शीर्षक के अन्तर्गत लेख में पृष्ठ 30 पर पैरा छह कालम एक में छपा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उद्धरण से सरकारी उपक्रमों की तथा विश्व में हमारे देश की बदनामी नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित चीफ एक्जीक्यूटिव के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर०के० सेठी ने इन्कार किया है कि अभिकथित वक्तव्य नहीं दिया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा पिंजौर में ट्रैक्टरों का उत्पादन

1242. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजौर स्थित कारखाने में वर्ष 1973-74 के 4000 ट्रैक्टरों की तुलना में इस वर्ष 7000 ट्रैक्टरों के उत्पादन की आशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये ट्रैक्टर 65 प्रतिशत स्वदेशी हैं अथवा शतप्रतिशत भारतीय ट्रैक्टर हैं

(ग) क्या पिंजौर में आगामी चार वर्षों में और अधिक ट्रैक्टर बनाये जायेंगे ;

(घ) पिंजौर में ट्रैक्टरों का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ङ) वर्ष 1975 में ट्रैक्टरों की मांग कहां तक पूरी की जा सकेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) से (ङ) गत दो वर्षों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजौर द्वारा ट्रैक्टरों का किया गया उत्पादन निम्न प्रकार है :—

1972-73	2,508 नग
1973-74	4,000 नग

वर्ष 1974-75 में 7,000 ट्रैक्टरों का उत्पादन होने की आशा है। इन ट्रैक्टरों में 65 प्रतिशत पुर्जे देशी हैं।

वर्ष 1975 में ट्रैक्टरों का उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

औद्योगिक क्षेत्र पर अनुसंधान एवं विकास उपकर लगाया जाना

1243. **श्री डी०डी० देसाई**
श्री अनादि चरण दास
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री पी० गंगादेव
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक क्षेत्र पर एक सामान्य अनुसंधान एवं विकास उपकर लगाना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपकर से औद्योगिक अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की वृद्धि होगी ;

(ग) क्या इससे प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या इससे औद्योगिक उत्पादकता में सुधार होगा और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में उपकर लगाने का सुझाव राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इस समय इस सुझाव के ब्यौरे तैयार करने में लगा हुआ है, इन्हें सरकार के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

1244. **श्री शिब्बन लाल सक्सेना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1974 में से प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के रूप में कुल कितनी राशि वितरित की गई; और

(ख) क्या 1972 के पश्चात् मूल्यों में हुए भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन की राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच०मोहसिन) : (क) 1972-73 तथा 1973-74 के वित्तीय वर्षों के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशिन केभुगतान पर हुआ कुल व्यय क्रमश: 63,20,000 रुपये तथा 16,32,05,215 रुपये था।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

फिल्म समारोह में अल्जीरियाई और श्रीलंका का प्रतिनिधि मण्डल

1245. **श्री शशि भूषण** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हुए पांचवें फिल्म समारोह में अल्जीरियाई प्रतिनिधि मंडल को फ्रांसीसी भाषा का इन्टरप्रेटर उपलब्ध नहीं किया गया था और उसने वापस अपने देश चले जाने की धमकी दी थी;

(ख) क्या श्री लंका के प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष को उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के प्रबन्ध की कोई विभागीय जांच कराने का है जिससे भविष्य में आयोजित किये जाने वाले फिल्म समारोह में इसी प्रकार की गड़बड़ी एवं कुप्रबन्ध न हो?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) जी, नहीं। अल्जीरियाई प्रतिनिधि मंडल को नई दिल्ली में उसके प्रवास के दौरान एक फ्रांसीसी इन्टरप्रेटर उपलब्ध किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त टायरों और ट्यूबों के बिना स्कूटरों का किया जाना

1246. **श्री सी०एम० सिन्हा** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि स्कूटर निर्माता अलाटियों को स्कूटर देते समय उनके साथ अतिरिक्त टायर और ट्यूब नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्कूटर निर्माताओं से यह पूछा है कि अलाटियों को अतिरिक्त टायर और ट्यूब किन कारणों से नहीं दे पा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग): बजाज और लम्ब्रेटा स्कूटरों के निर्माता अपने नये स्कूटरों के साथ केवल व्हील रिमें ही सप्लाई कर रहें हैं । इस का कारण स्कूटरों के लिए टायर और ट्यूबों की सप्लाई का कम होना है। सरकार ने टायर और ट्यूबों के निर्माताओं से स्कूटरों के निर्माताओं के लिए टायर और ट्यूबों की सप्लाई में वृद्धि करने को कहा है । मोटरगाड़ी टायर और टयूबों के विद्यमान निर्माताओं से स्कूटरों के टायर और टयूबों के उत्पादन में वृद्धि करने को कहा गया है ।स्कूटरों के टायर और टयूबों की मांग और पूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता की भी स्वीकृति दे दी गई है। जब तक अतिरिक्त क्षमता कार्यान्वित नहीं होती है तब तक के लिए सरकार का विचार इस बात का पता लगाने का है कि यदि थोड़े समय तक स्कूटर के टायरों और टयूबों का आयात किया जाए तो स्थिति में सुधार हो जाएगा ।

Despatch of Telegrams from Delhi

1247. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Government's attention has been drawn to the news report published in a Hindi daily on 25th December, 1974 that 45,000 telegrams were sent from Delhi by post and they did not reach their destinations in time; and

(b) if so, the reasons for delay in their delivery and the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) Yes Sir.

(b) During the period October to December, 1974 mentioned in the Hindi daily paper, 3.24 per cent of traffic had to be despatched by post from Delhi. In January, 1975 the percentage of traffic is 0.64 only.

Reasons for disposal by post were as under :—

(i) Dislocation of telecom. services to important centres in Bihar and West Bengal due to damage to co-axial system during Bihar movement in Oct., 74.

(ii) Heavy absentesism during festival season.

(iii) Failure of channels on account of line failures, and co-axial failures.

(iv) Power shedding in various parts of the country, particularly Haryana, the Punjab and U.P.

Action taken :

(i) Diversion of staff from administrative sections to sections dealing with live traffic.

(ii) Increase in Sunday duties.

(iii) Appointment of new clerks released from training class against vacant clerical posts.

(iv) Provision of additional Despatch Riders for delivery of telegrams.

(v) Provision of engine alternators as stand-by arrangement to overcome power shedding.

Stern Action against movement launched by Shri Jaya Prakash Narayan in Bihar

1248. **Shri Mohammad Ismail :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Chief Minister of Bihar has recently stated that stern attitude will be adopted towards the movement launched by Shri Jaya Prakash Narayan ;

(b) whether he has also threatened to arrest him; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri K. Brahmananda Reddi) : (a) to (c) According to information received from the Government of Bihar, the Chief Minister of Bihar had stated recently at New Delhi, in reply to questions by press reporters about the agitation led by Shri Jaya Prakash Narayan in the State, that the Government had acted with great restraint in dealing with the agitationists who tried to disrupt public life and indulged in large scale violence and arson but now the situation would not be allowed to deteriorate any further and any stringent action permissible by law would be taken by the State Government towards this end. On being further asked by the press reporters whether Government would arrest Shri Jaya Prakash Narayan, the Chief Minister had added that in order to control the situation, if it became necessary, Government would not hesitate to arrest him.

Arrests in connection with the maintenance of law and order are primarily the concern of the State Government.

फिल्म समारोह में आये प्रतिनिधियों के सम्मान में फिल्म फैडरेशन आफ इंडिया द्वारा किया गया भोज

1249. **श्री एन०ई० होरो :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आये विदेशी प्रतिनिधियों के सम्मान में फिल्म फैडरेशन आफ इंडिया ने एक भोज का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग के प्रतिनिधि बम्बई में 30,000 रु० मूल्य की व्हिस्की लाए थे, परन्तु क्रेटों को अन्ततः मन्त्री महोदय के अनुरोध पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने छोड़ा था ;

(ग) क्या अनेक अधिकारी इस भोज में शामिल हुए और उन्होंने व्हिस्की पी और विदेशी प्रतिनिधियों की उपस्थिति बहुत कम थी; और

(घ) यदि हां, तो इस भोज पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, आल इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्ज काउन्सिल, बम्बई द्वारा 30-12-1974 को रात्रि भोज (डिनर) दिया गया था।

(ख) जी, हां। परन्तु रात्रि भोज से पहले राज्य के सीमाशुल्क प्राधिकारियों को कुछ गलत-फहमी हो गई क्योंकि ऐसा डाक्टरी प्रमाण-पत्र कि स्टाक मानव उपभोग के लिए ठीक है, नहीं था। क्योंकि समय बहुत कम था, अत: मन्त्री महोदय के हस्ताक्षेप पर व्हिस्की का एक भाग रात्रि भोज के लिए रिलीज कर दिया गया

(ग) जो विदेशी प्रतिनिधि समारोह के उद्घाटन दिवस तक पहुंच गए थे, उन सभी को और अनेक अधिकारियों और गैर सरकारी व्यक्तियों को रात्रि-भोज में आमन्त्रित किया गया था और वे सभी उसमें उपस्थित हुए।

(घ) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है चूंकि रात्रि-भोज आल इण्डिया फिल्म प्रोड्यूसर्ज काउन्सिल जो एक गैर-सरकारी संगठन है, द्वारा आयोजित किया गया था।

Functioning of Telephones in Hapur

1250. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news report under the caption "Hapur Ke Vyapari telephone Karmachariyon dwara Pareshan" (Harassment of Hapur businessmen by telephone employees) published in a Hindi daily on 28th January, 1975;

(b) if so, whether Government propose to order a high level inquiry into the alleged corruption and take action against all categories of employees found guilty;

(c) whether Government are also aware that most of the telephones of the Hapur Exchange do not function and that inflated bills are sent to the subscribers despite the telephones having remained out of order and closed, thus causing harrassment to them; and

(d) if so, the steps Government propose to take to improve the situation?

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma) : (a) Yes Sir.

(b) The vigilance Cell of the U.P. Telecom. Circle is making investigations. Further action will be taken on the basis of findings of the Vigilance Cell.

(c) & (d) Complaints of improper working of telephones are attended to as promptly as possible. Concerted efforts are being made for the last three months for carrying out special repairs in the exchange and maintenance efforts have been tightended. A team from P&T Directorate also visited Hapur exchange recently

and a number of remedial measures to further improve the working of the system are being taken.

Cases of complaints of excess metering received from time to time are decided after thorough enquiry.

मोटरगाड़ी उद्योग में संकट

1251. **श्री पी० के० देव :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि मोटरगाड़ी उद्योग वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों का सामना कर रहा है और उसमें मंदी भी आई हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं और वर्तमान मंदी का सामना करने के लिए उद्योग की सहायता करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि गाड़ियों की कीमतों तथा रखरखाव लागत में काफी वृद्धि होनें के कारण यात्रीकार उद्योग में उत्पादन में मंदी आई है। सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि सरकार द्वारा उठाये गए कुछ मुद्रास्फीति-विरोधी कदमों जिनमें मुद्रा के सम्भरण और ऋण पर आवश्यक रूप से सख्त नियंत्रण सम्मिलित है, से मुद्रा का प्रसार कम हुआ है और विद्यामान क्रय शक्ति में भी कुछ अपक्षरण हुआ है। सरकार अपनी ऋण नीति को चयनात्मक बनाने के लिए प्रयत्न कर रही है जिससे मुद्रास्फीति कारी और आरम्भिक मन्दीकारी संकटों के खिलाफ अपनी लड़ाई के पूरक के रूप में अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन जारी रखा जा सके और बढ़ाया जा सके। मोटरगाड़ी उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे वाणिज्यिक गाड़ियां, स्कूटरों और मोटरों का चयनात्मक ऋण नीति का लाभ रूप से निश्चित मिलेगा।

Setting up of big factory in M.P. in Fifth Plan

1252. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether Government have made provision to set up a big factory in Madhya Pradesh during the Fifth Five Year Plan keeping in view the backwardness of the State; and

(b) if so, the location thereof and the allocation of money made therefor and the time by which the said factory is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya): (a) and (b) The names of Central industrial and mineral projects to be undertaken during the Fifth Plan in various States, including Madhya Pradesh alongwith their locations and outlays (to the extent decisions have been taken) are indicated at pages 151-155 (Vol. II) of the Draft Fifth Plan Document.

नागा विद्रोहियों द्वारा वार्ता पुनः आरम्भ करना

1253. **चौधरी राम प्रकाश**
श्री एम०एस० पुरती :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोही बिना किन्हीं पूर्व शर्तों के केन्द्र के साथ बातचीत पुनः प्रारम्भ करने को तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) सरकार की यह निश्चित नीति है कि जब तक नागा विद्रोही अपनी हिंसात्मक गतिविधियां तथा पृथकतावादी मांग जारी रखते हैं तब तक कोई सार्थक बात नहीं हो सकती है ।

रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण

1254. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार संवर्धन कार्यक्रम में बेरोजगार युवकों के प्रशिक्षण की योजना भी सम्मिलित है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित लोगों को प्रशिक्षण के पश्चात् लाभप्रद रोजगार प्रदान किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रशिक्षित लोगों को रोजगार न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 प्रकार की प्रशिक्षण स्कीमों की व्यवस्था है :—

(1) उन शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रारंभिक प्रशिक्षण जो अपने स्व-नियोजनार्थ उद्यम स्थापित करना चाहते हैं;

(2) उन शिक्षित नवयुवकों को प्रशिक्षण जिन्हें निगमों और सहकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों सहित गैर सरकारी क्षेत्र एवं विशेष रुप से ऐसे लघु उद्यम जिनमें अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की सामर्थय नहीं है, में नियमित रोजगार में खपाया जाना सुनिश्चित है ।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को प्रशिक्षण ताकि सक्षम निजी एवं संस्थानीय रोजगार दाताओं के यहां, अथवा अपेक्षित न्यूनतम योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के अभाव में रिक्त पड़े आरक्षित कोटे के विशिष्ट सरकारी रोजगारों में उनको अधिक रोजगार प्राप्त हो सकें ।

(ख) अधिकांश मामलों में लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इन लोगों को लाभप्रद रोजगारों में खपाने का प्रश्न तभी उठेगा जब यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा हो जाये । फिर भी राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों को यह परामर्श दिया गया है कि वे इन लोगों को लाभप्रद रोजगारों में खपाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में आदिमजातियों के लोगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए समिति

1255. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में आदिम जातियों के लोगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और जब प्राप्त होगी सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

कलकत्ता के साप्ताहिक पत्र फ्रन्टियर तथा दर्पण के कार्यालयों की लूटपाट

1256. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1975 को कलकत्ता के साप्ताहिक पत्र फ्रन्टियर तथा दर्पण के कार्यालयों की लूटपाट की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनका इस आक्रमण में हाथ है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/149/436/427/323 के अधीन एक मामला 14 जनवरी, 1975 को दर्ज किया गया था और जांच पड़ताल हो रही है ।

राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग का प्रशासकीय ढांचा

1257. **श्री रानेन सेन :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग के प्रशासकीय ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

मैसर्स मारुति लिमिटेड द्वारा इंजन का आयात

1258. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मैसर्स मारुति लिमिटेड' को जारी किये गये आशय पत्र का हाल ही में नवीकरण किया गया है ;

(ख) क्या 'मैसर्स मारुति लिमिटेड' की अपनी सहायक कम्पनी 'मैसर्स मारुति टैक्नीकल सर्विसेज लिमिटेड' और एक जर्मन तकनीशियन 'डब्ल्यू० एच० ई० मुलर' के माध्यम से प्रस्तावित मारुति कार के लिए इन्जन का आयात करने की विशेष अनुमति दी गई थी ;

(ग) क्या इस इन्जन को सीमाशुल्क विभाग से विंग कमान्डर आर० एच० चौधरी द्वारा पास करा लिया था; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने अनधिकृत रुप से भारत में आयात की गई उस मशीन को जब्त कर लिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) शर्तों का पालन करने पर आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया गया है।

(ख) इस मन्त्रालय ने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विशिष्ट राजनीतिक दल की विचारधारा में आस्था रखने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने के बारे में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय

1259. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 5 नवम्बर, 1974 को यह विनिर्णय दिया कि "सरकारी सेवाओं में रोजगार के लिए अभ्यर्थों को राजनैतिक आस्था, विश्वास और सम्बद्धता तथा उसकी भूतपूर्व राजनैतिक गतिविधि के बारे में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने का सम्पूर्ण कार्य संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकारों के विपरीत है और यह कार्य प्रस्तावना में वर्णित आदेशों के प्रति निष्ठावान प्रजातांत्रिक गणराज्य में पूर्णत: गलत लगता है, "

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय का पूर्ण पाठ क्या है ;

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में "विशिष्ट विचारधारा में निष्ठा अथवा विश्वास रखने के कारण" आवेदकों को कितनी बार रोजगार नहीं दिया गया; और

(ङ) क्या उन आवेदकों को आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए रोजगार दिया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशसनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) 5 नवम्बर, 1974 के फैसले का पूर्ण पाठ संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9017/75]**

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

(घ) चरित्र तथा पूर्ववृत्तों के सत्यापन के लिए जिस कार्यविधि को अपनाया जाना चाहिए और जिन मानदण्डों को ध्यान में रखा जाना चाहिये, सरकार ने उनके संबंध में सामान्य आदेश जारी

किए हैं। इन अनुदेशों का पालन करना विभिन्न सरकारी विभागों के नियुक्तिकर्ता प्राधिकारियों का काम है। जिन अधिकारियों को चरित्र तथा पूर्ववृत्तों के सत्यापन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां नहीं दी गई, उनके संबंध में कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किये गए हैं।

(ङ) निर्णय की जटिलताओं का अध्ययन और उनकी जांच किए जाने के बाद ही इस मामले को तय किया जायेगा।

इलैक्ट्रोनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का आयात

1260. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक उद्योग में काम आने वाले अधिकांश कच्चे माल का आयात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किस-किस वस्तु का आयात किया जाता है ;

(ग) क्या उन्हें देशी उत्पादन से उपलब्ध करने की कोई सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने हैं ?

प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मन्त्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एवं (ख) इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग में कच्चे माल की आवश्यकता सब मिला कर घटकों के निर्माण हेतु और अपेक्षाकृत एक मर्यादित सीमा तक उपस्कर के उत्पादन हेतु पड़ती है। अपेक्षित कच्चा माल विनिर्देशन के अर्थों में अपेक्षाकृत विशेष कोटि का होता है (उन उत्पादों के विषय में भी जिनके एक ही नाम हैं अत्युच्च शुद्धता वाले, विभिन्न प्रकार के प्रयोगकर्ताओं के लिए नानारूप गुण वाले, तथा बनावट, आकार आदि में विविधता वाले)। इस प्रकार अर्धकण्डक्टर उद्योग में, सिलीकोन जैसे पदार्थों और इससे प्रयुक्त सभी रसायनों को असाधारण रूप से उच्च शुद्धता का होना जरूरी है। वैद्युत-यांत्रिक घटकों के विषय में, विविध विशिष्ट धातु-मिश्रों (फोस्फर ब्रौंज, कोवर, इनधर, निकल के धातुमिश्र, टंग्सटेन, मोलिबडेनम, आदि) की आवश्यकता होती है। दूसरे कच्चे पदार्थ जिनकी आवश्यकता है, वे हैं फिनोलिक्स माऊल्डिंग योगकि, प्लेटिंग पदार्थ, एपोक्सीज व रेजिन, बहुत पतला कायर इनेमिल तार, इलक्ट्रोनिक्स ऐडेमिल तार, इलक्ट्रोनिक्स एडेसिव आदि के विभिन्न प्रकार। आयात नीति का प्रतिपादन करते समय उद्योग की आवश्यकताओं को प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है। कतिपय अभिज्ञप्त उत्पादों के लिए आयात हेतु अनुमत वर्तमान मदें आयात व्यापार नियंत्रण (लाल पुस्तक), जिल्द I, 1974-75 के परिशिष्ट 28, सूची 4, 38 और 43 में दी गयीं है। आयात प्रतिस्थापन को नियमित, संगठित, आधारपर प्रभाव में लाया जा रहा है, किन्तु जब अतिविशिष्ट पदार्थों, यदि वे रणनीतिक किस्म के नहीं हैं, का थोड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए भारी निवेश करना पड़ता है, तब आयात प्रतिस्थापन को उचित नहीं समझा जाता। इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग के लिए अपेक्षित कच्चे पदार्थ अधिकांशत: स्वदेश में उपलब्ध हैं, परन्तु आवश्यक जटिल कच्चे पदार्थों के एक अर्थपूर्ण आंश को संप्रति आयात किया जा रहा है।

(ग) एवं (घ) पांचवीं योजना अवधि के दौरान इलैक्ट्रोनिक्स सामान के 2300 करोड़ रु० के कुल उत्पादन में, से केवल कच्चे पदार्थों की मांग 190 करोड़ रु० मूल्य की प्राकलित की

गयी है । इस राशि में से, 80 करोड़ रु० के पदार्थों को 17:3 करोड़ रु० के अतिरिक्त निवेश से विशिष्ट रूप से इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग के लिए उत्पादित किये जाने की आशा है । शेष 110 करोड़ रु० में से, एक हिस्सा अन्य क्षेत्रों के निवेश कार्यक्रमों में से उपलब्ध हो सकेगा । फिर भी, ऐसे पदार्थों का स्वदेशी उत्पादन तब ही किया जायेगा जब कि किसी मद विशेष की मांग आर्थिक रूप से जीवनक्षम स्तर तक हो, यह विशेषरूप से इस कारणवश है कि इस क्षेत्र में ऐसे उत्पादन कार्यक्रम अत्यन्त पूंजी गहन होते हैं । इलैक्ट्रोनिक्स विभाग प्रौद्योगिकी विकास परिषद के जरिये पदार्थों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की उन परियोजनाओं का वित्त प्रबंध कर रहा है, जो ऐसे पदार्थों के स्वदेशी उत्पादन पर अंततः अपना प्रभाव छोड़ेगी ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारियों के विदेशी दौरों पर व्यय

1261. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक और मुख्य परामर्शदाता के विदेशी दौरों के बारे में 28 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 380 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य परामर्शदाता के साथ, उत्तर में वर्णित विदेशी दौरों में, कुछ अन्य व्यक्ति भी गए थे, यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा उनका विवरण क्या है और उनको साथ ले जाने की आवश्यकता के क्या हैं;

(ख) प्रत्येक दौरे हर इन व्यक्तियों पर भारतीय तथा विदेशी मुद्रा में पृथक-पृथक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा कितनी राशि खर्चा की गयी; और

(ग) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास लिमिटेड इस विदेश दौरों के दौरान हुए चर्चा तथा बातचीत के परिणामस्वरूप अब तक कोई क्रयादेश प्राप्त करने में सफल हुआ है ; यदि हां, तो कितनी राशि की ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 9018/75]**

दुर्बल वर्गों के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण करने के लिए योजना आवंटन में वृद्धि

1262. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 के दौरान समाज के दुर्बल वर्गों के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण पद्धति की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु योजना आवंटन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान प्रणाली में सुधार करने के लिए कितना आवंटन किए जाने की संभावना है ; और

(ग) क्रियान्विति करने वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा आवंटन का किस प्रकार उपायोग किए जाने की संभावना है ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) संबद्ध सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जय गुरूदेव के पूर्ववृत की जांच

1263. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जय गुरुदेव के नाम से अपने आप को प्रसिद्ध करने वाले व्यक्ति की पहचान, पूर्ववृत तथा गतिविधियों के बारे में कोई जांच की है ;

(ख) उसकी कार्यवाहियां और गतिविधियों के लिए किस तरह और किस के द्वारा पैसा दिया जा रहा है ; और

(ग) क्या उसके आन्दोलन में किसी विदेशी एजेन्सी का हाथ है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (ग) सरकार को जय गुरुदेव उर्फ तुलसी दास नामक एक व्यक्ति, जो ऐटा जिला, उत्तर प्रदेश के एक गांव का है की गतिविधियों की जानकारी है और बताया जाता है कि उसने "धर्म प्रचारक संघ" नामक एक संघ की स्थापना की है । किन्तु उसके द्वारा किसी आध्यात्मिक अथवा राजनैतिक आन्दोलन शुरु किए जाने की कोई सूचना नहीं है । कहा जाता है कि उससे अपने आश्रमों से आय और अपने अनुयाइयों से योगदान प्राप्त हो रहा है । ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वह किसी विदेशी ऐजेंसी से सहायता प्राप्त कर रहा है ।

नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन

1264. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री खोसला द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लुप्त होने के बारे में जांच संबंधी अपने प्रतिवेदन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक के बारे में अनेक प्रतिकूल एवं आक्षेप पूर्ण टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या नेताजी के बारे में इन टिप्पणियों और विचारों को प्रतिवेदन में से निकाला जायेगा ;

(घ) क्या प्रतिवेदन में निष्कर्ष के रूप में दी गई बहुत सी टिप्पणियां और व्यक्त किए विचार आयोग के निर्देश-पदों से संबद्ध नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) सम्भवत: आजाद हिन्द फौज तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के प्रति तत्कालीन जापानी प्राधिकारियों के दृष्टिकोण के बारे में जांच आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणी का हवाला दिया गया है । ये टिप्पणियां जो कि आयोग के सामने प्रस्तुत की गई सामग्री अथवा साक्ष्य पर आधारित प्रतीत होती हैं, इस बात का संकेत देती हैं कि आजाद हिन्द फौज और नेताजी के प्रति तत्कालीन जापानी सरकार की नीति उनके अपने ही हितों के मूल्यांकन तथा जापानी दृष्टिकोण से देखी गई बढ़ती हुई युद्ध की स्थिति की आवश्यकताओं से प्रभावित थी । आयोग ने यह भी लिखा है कि जापानी नेताजी का अत्याधिक आदर करते थे क्योंकि उन्होंने देखा कि वे असाधारण साहस तथा अटूट देश भक्ति वाले व्यक्ति थे । रिपोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी नजर नहीं आती जो कि अध्यक्ष की निजी टिप्पणी के रूप में नेताजी की महत्ता के लिए आक्षेप पूर्ण हो । आयोग ने अन्य बातों के साथ कहा है कि नेताजी का भारत के इतिहास में विशिष्ट तथा अतुलनीय स्थान है ।

(ख) और (ग) सरकार को कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझती ।

(घ) आयोग के निर्देश-पथ, आयोग के सभी निष्कर्षों को समाहित करने के लिए काफी व्यापक थे ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में कई प्राधिकरणों का अस्तित्व

1265. **श्री एच० के०एल०भगत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कई प्राधिकरणों और एजेंसियों के अस्तित्व से दिल्ली के समुचित विकास में बाधा पड़ती है ; और

(ख) स्थिति का सामना करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अनेक प्राधिकरण तथा एजेंसियां कार्य कर रही हैं किन्तु उनमें से प्रत्येक निर्धारित सीमा में कार्य करती हैं तथा निर्धारित कार्यों की देख भाल करती है । सरकार विभिन्न प्राधिकरणों तथा एजेंसियों के प्रयासों के प्रभावी समन्वय द्वारा दिल्ली की समस्याओं के लिए समाकलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को समझती हैं । उप राज्यपाल की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति पहले ही समन्वय एजेंसी के रूप में विद्यमान है । इन प्राधिकरणों तथा एजेंसियों की कार्यवाही का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है ।

भोपाल में केन्द्रीय संचार मन्त्री के घर में गन पाउडर के गोलों का पाया जाना

1266. **श्री भगत राम मनहर**
श्री डी० वी० चन्द्रगोडा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में 3 फरवरी, 1975 को केन्द्रीय संचार मंत्री के शयन कक्ष में गन पाऊडर के दो गोले पाये गए थे जिन में सैफ्टी फ्यूजस्ट्रिंग लगे थे ;

(ख) यदि हां, तो अब तक की गयी जांच कार्यवाही के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या इस संबंध में अब तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) से (ग) मध्यप्रदेश सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने हर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

Grant of Pension to alleged bogus freedom fighters

1267. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether he has been receiving complaints regarding the grant of pensions to bogus freedom fighters from time to time ;

(b) whether the pensions to such bogus freedom fighters have been stopped or discontinued; and

(c) if so, the number of such persons State-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) Complaints are being received from time to time against the grant of pension to freedom fighters who are not eligible for the same under the scheme.

(b) If there is *prima facie* evidence that a person who has been sanctioned a freedom fighters pension is not eligible for it, pension is stopped.

(c) Statement showing the number of such persons State-wise is attached.

Statement

The number of persons to whom pention has been suspended/cancelled (State wise)

Sl. No.	State/Union Territory	Number of cases in which pension has been suspended/cancelled
1.	Andhra Pradesh	13
2.	Assam	3
3.	Bihar	8
4.	Chandigarh	—
5.	Delhi	50
6.	Gujarat	4
7.	Haryana	4
8.	Himachal Pradesh	1
9.	Jammu & Kashmir	—
10.	Karnataka	8
11.	Kerala	1
12.	Maharashtra	14
13.	Madhya Pradesh	10
14.	Orissa	92
15.	Punjab	13
16.	Pondicherry	5
17.	Rajasthan	2
18.	Tamil Nadu	100
19.	Uttar Pradesh	44
20.	West Bengal	5
	Total	377

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के कर्मचारियों की मुअत्तिली

1268. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के 9 कर्मचारियों को हाल ही में मुअत्तिल कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुअत्तिली के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मुअत्तिली के आदेश वापस ले लिए गए हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) इन कर्मचारियों को गम्भीर अनुशानहीनता के कारण निलम्बित किया गया है ।

(ग) क्यों कि इन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है इस लिए निलम्बन के आदेश वापिस नहीं लिए गए हैं ?

सीमेंट की दुहरी मूल्य-निर्धारण प्रणाली

1269. **डा० हरि प्रसाद शर्मा**

श्री निम्बालकर :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की दुहरी मूल्य-निर्धारण नीति लागू करने के प्रश्न पर सरकार अभी हाल में विचार करती रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस योजना से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है, अनधिकृत कालोनियों की वृद्धि और भवन निर्माण में काले धन के प्रयोग को रोकने में इससे किस प्रकार की सहायता मिलेगी ; और

(घ) वास्तविक मकान निर्माताओं को उचित मूल्यों पर सीमेंट की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री बी०पी० मौर्य): (क) और (ख) सीमेंट उद्योग के लिए दुहरी मूल्य प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । सीमेंट नियंत्रण (छठवां संशोधन) आदेश 1974 के माध्यम से विद्यमान एककों द्वारा तैयार किए गए सीमेंट का कारखाने से निकलते समय का साधारण मूल्य निश्चित किया जा चुका है । 1975 में उत्पादन आरम्भ करने वाले एककों का अथवा और उसके पश्चात् पांचवीं योजना-अवधि में उत्पादन आरम्भ करने वाले एककों का कारखाने से निकलते समय का साधारण मूल्य नियत करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) राज्य सरकारों तथा उनके प्राधिकारियों के पास वास्तव में भवन निर्माण करने वालों की आवश्यकता पूरी करने हेतु तिमाही थोक कोटा रख दिया जाता है ।

वर्ष 1976 तक बिजली की स्थिति में सुधार

1270. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 तक बिजली की स्थिति में काफी सुधार होने की संभावना है और

(ख) यदि हां, तो उक्त संभावना का क्या आधार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 1975–76 के दौरान लगभग 2684 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना है । इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप 1976 में विद्युत की स्थिति में सुधार होगा ।

श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा आकाशवाणी के विरुद्ध आन्दोलन

1271. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री जय प्रकाश नारायण की इस चेतावनी की ओर दिलाया गया है कि आकाशवाणी के विरुद्ध, एक आन्दोलन आरम्भ किया जाएगा जिससे उसका कार्यकरण असम्भव बना दिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :(क) जी, हां ।

(ख) सरकार आलोचना को अनुचित समझती है । आकाशवाणी अपने कर्त्तव्यभार को बराबर निभाती रहेगी ।

वर्ष 1975 के दौरान कोयले के उत्पादन का लक्ष्य

1272. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 के दौरान कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें हैं

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मंत्री, (प्रो० सिद्धश्वर प्रसाद) :(क) और (ख) 197576 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य 980 लाख टन नियत किया गया है और इनका संगठन वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

कोयला खान प्राधिकरण लि०	690.00	लाख टन
भारत कोकिंग कोल लि०	190.00	लाख टन
सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०	65.00	लाख टन
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	35.00	लाख टन
कुल	980.00	लाख टन

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन से सहायता

1273. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने अपनी सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि, ब्रिटेन द्वारा भारी उपकरणों की प्राप्ति के लिए दी गई सामान्य सहायता का प्रयोग करते हुए, हाल ही में ब्रिटेन को कुछ भूमिगत खनन मशीनरी के आर्डर दिए गए हैं ।

"अमर प्रेमी शैनी विजानन्द" फिल्म पर रोक

1274. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि 'मारू फिल्म्स' ने हाल ही में एक फिल्म अमर प्रेमी शैनी विजानन्द' तैयार की है जिसे प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र भी मिल गया है ;

(ख) क्या गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चारण लोगों, राजपूतों तथा कुछ अन्य समुदायों ने इस फिल्म के प्रदर्शन के विरुद्ध गम्भीर विरोध किया है जिससे कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है क्योंकि इसमें उनकी पूजनीय देवी का अपमान किया गया है और क्या उन्होंने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में किसी भी सिनेमा हाल ने हिंसक प्रतिक्रिया के भय से इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं किया है ; और

(घ) क्या उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार का कम से कम उन राज्यों में जहां चारण समुदाय के लोग रहते हैं, उक्त फिल्म पर रोक लगाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ विरोध प्राप्त हुए हैं ।

(ग) तथा (घ) मामले की जांच की जा रही है ।

दिल्ली-पुलिस के कर्मचारियों को छुट्टियों की मन्जूरी

1275. **श्रीमती सावित्री श्याम**
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों की तीन राष्ट्रीय छुट्टियों सहित नौ छुट्टियां मंजूर करने के बारे में दिल्ली के पुलिस महानिरीक्षक ने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को कोई निदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) दिल्ली पुलिस के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कितनी राजपत्रित छुट्टियां दी जा रही हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा जारी किये गए निदेशों के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक ने आदेश जारी किए हैं, जिनके द्वारा दिल्ली पुलिस के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तीन राष्ट्रीय छुट्टियों समेत नौ राजपत्रित छुट्टियां लेने की अनुमति है ।

केरल में उद्योगों की स्थापना करने के लिए आवेदन पत्र

1276. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नये उद्योगों की स्थापना करने के लिए 31 दिसम्बर, 1974 तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे;

(ख) उनमें से कितने आवेदन पत्रों के लिए आशय पत्र और लाईसेंस जारी किये गए; और

(ग) कितने आवेदन-पत्र अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) केरल में नए उद्योग स्थापित करने के लिए 1974 में 57 आवेदन प्राप्त हुए ।

(ख) इन आवेदनों पर 13 आशयपत्र और 5 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गए ।

(ग) 12 आवेदन अनिर्णीत पड़े हैं ।

विद्युत संसाधनों के विकास के लिए कर्नाटक द्वारा वित्तीय सहायता का आवेदन

1277. **श्री के० लकप्पा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में विद्युत संसाधनों पर विकास करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कर्नाटक सरकार से अभी हाल में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने कालीनदी चरण-एक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है । जीवन बीमा निगम चालू वर्ष के दौरान मैसूर विद्युत निगम को 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करने के लिए सहमत हो गया है ।

कर्नाटक सरकार ने कोई अन्य जल-विद्युत परियोजनायें भी प्रस्तुत की हैं परन्तु उन्हें पांचवीं योजना के प्रारूप में शामिल नहीं किया गया है ।

भारत द्वारा वैज्ञानिक उपग्रह छोड़े जाने के बारे में भारत और सोवियत संघ के बीच विचार-विमर्श

1278. **श्री भागीरथ भंवर**
श्री समर गुह
श्री वयालार रवि :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक उपग्रह छोड़े जाने के बारे में सोवियत संघ और भारत के बीच विचार-विमर्श हुआ था, यदि हां, तो किन-किन मुख्य बातों पर विचार किया गया; और

(ख) पहला भारतीय उपग्रह कब छोड़ा जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ की एकेडमी आफ साइंसिज की इन्टर-कॉसमॉस कोंसिल के बीच 1972 में एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके अधीन सोवियत राकेट वाहक से एक भारतीय वैज्ञानिक उपग्रह छोड़ा जायेगा । तब से, नियमित रूप से नियत अन्तराल पर, भारतीय और सोवियत

विशेषज्ञों के बीच आवधिक-विचार-विमर्श हो रहे हैं, भारतीय उपग्रह का फ्लाइट मॉडल अब बंगलौर में लगभग पूर्ण होने वाला है, और इसको छोड़ने के सभी आयोजनों को अन्तिम रूप देने के बारे में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के विशेषज्ञों तथा इंजीनियरों के बीच बातचीत चल रही है ।

(ख) उपग्रह के फ्लाइट मॉडल पर वर्तमान परीक्षणों की शृंखला के मार्च, 1975 में पूरा हो जाने के बाद ही, इसके प्रक्षेपण की निश्चित तारीख का पता चलेगा । वर्तमान अनुमान यह है कि इस वर्ष के मध्य से पहले ही उपग्रह को छोड़ना संभव होना चाहिए ।

कर्नाटक के लिए टेलीविजन कार्यक्रम रिले करने वाला केन्द्र

1279. **श्री के० लकप्पा : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन कार्यक्रम तमिलनाडु में आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) क्या टेलीविजन कार्यक्रमों को कर्नाटक में आरम्भ नहीं किया गया है ;

(ग) क्या इस मामले में अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक के साथ भेदभाव किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में एक रिले केन्द्र स्थापित करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, अभी तक नहीं । मद्रास में टेलीविजन केन्द्र निर्माणाधीन है ।

(ख) से (घ) उपग्रह संचार टेलीविजन प्रयोग जो 1975 के मध्य में शुरू होना है और एक वर्ष तक चलेगा, कर्नाटक सहित 6 राज्यों के चुने हुए ग्राम समूहों में सीधा रिसैप्शन उपलब्ध करेगा । निरन्तर सेवा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार क्रमिक रूप से स्थापित स्थलीय ट्रांसमिटरों के माध्यम से उपलब्ध करने की चेष्टा की जानी है । किसी विशिष्ट राज्य से भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं उठता और यह अनुचित है ।

कर्नाटक में उद्योगों को वित्तीय सहायता

1280. **श्री के० लकप्पा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में केन्द्र द्वारा प्रायोजित बड़े, मध्यम और लघु उद्योग कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) इन उद्योगों को गत दो वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०पी०शर्मा) : (क) ऐसा समझा जाता है कि तात्पर्य केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से है कर्नाटक में केन्द्र द्वारा चलाये जा रहे उद्योगों से नहीं । बड़े और मध्यम क्षेत्रों में कोई केन्द्र प्रायोजित योजना नहीं है, केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनायें हैं । ये योजनायें 'असंगठित क्षेत्र में, ग्राम और लघु उद्योगों के आंकड़ों का एकत्रीकरण' और 'ग्रामीणोद्योग परियोजना कार्यक्रम' । पहली योजना के लिए आंकड़े इकठ्ठे करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है और इस स्थिति में इस योजना के स्थल का प्रश्न ही नहीं

उठता । इस समय कर्नाटक स्थित ग्रामोद्योग परियोजनायें और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत परियोजनायें निम्नलिखित हैं :—

1. धारवाड़ जिला
2. टुमकूर जिला
3. शिमोगा जिला
4. बेलगाम जिला
5. बीजापुर जिला
6. बीदर जिला
7. हासन जिला

(ख) कर्नाटक राज्य को इन दोनों योजनाओं के लिए 1972–73 और 1973–74 में दिया गया अनुदान/ऋण इस प्रकार है :—

(रु० लाखों में)

योजना	वर्ष	स्वीकृत अनुदान	स्वीकृत अनुदान	योग
1. ग्रामोद्योग संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण	1972–73	0.5	कुछ नहीं	0.5
	1973–74	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. ग्रामोद्योग परियोजना कार्यक्रम	1972–73	11.23	14.59	25.82
	1973–74	5.99	10.66	16.65

पाण्डिचेरी में हिन्दू विवाह अधिनियम का लागू किया जाना

1281. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में दो प्रकार के नागरिक होने के क्या कारण हैं, जिन में से एक प्रकार के नागरिकों पर हिन्दू विवाह अधिनियम लागू होता है और रिनान्केन्ट्स, नामक अन्य हिन्दुओं पर हिन्दू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता ; और

(ख) इस विसंगति को कब समाप्त किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) 1881 के फ्रान्स के आदेश के अधीन भूतपूर्व फ्रान्सीसी उपनिवेशों के निवासी जाति अथवा धर्म पर ध्यान न देते हुए विवाह, तलाक, सम्पत्ति के निपटान आदि जैसे मामलों में अपने वैयक्तिक कानूनों की बजाय इन उपनिवेशों में फ्रान्सीसी लोगों पर लागू होने वाले कानूनों से शासित होने के लिए विकल्प देने के अधिकारी थे । वे व्यक्ति जिन्होंने ऐसा विकल्प दिया वे रिनान्केन्ट्स कहलाते हैं । इसलिए जब हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 समेत विभिन्न समुदायों पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानूनों का इस संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार किया गया, तो वे कानून रिनान्केन्ट्स के लिए विशिष्ट रूप से अप्रयोज्य बना दिए गए । अपनी वैयक्तिक कानूनी स्थिति की वापसी के लिए उनसे कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

पश्चिम बंगाल-बिहार क्षेत्र में सरकारी स्वामित्व वाली खानों में श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जाना

1282. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल-बिहार क्षेत्र में सरकारी स्वामित्व वाली खानों में श्रम कानूनों तथा खान सुरक्षा उपायों का खुले आम उल्लंघन किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप इन खानों में दुर्घटनायें बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972, 1973 और 1974 में हुई दुर्घटनाओं का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दुर्घटनायें कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) पश्चिमी बंगाल तथा बिहार में सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खानों में 1972 तथा 1974 के बीच हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

कम्पनी का नाम	वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	
		घातक	गम्भीर
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	1972	47	376
	1973	48	339
	1974	45	258
कोयला खान प्राधिकरण का पूर्वी प्रभाग	1972	53	208
	1973	40	255
	1974	46	150
कोयला खान प्राधिकरण का मध्य प्रभाग	1973	21	115
	1974	28	93
		(अक्तूबर 74 तक)	

(ग) कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं । वे प्रयास हैं :—खान सुरक्षा समितियों की कार्य प्रणाली को तेज करना; खान सुरक्षा निदेशक के साथ मासिक बैठकें करना, खान इंजीनियरी संवर्ग से सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, तथा सभी दुर्घटनाओं की सावधानी से छानबीन करना ताकि कारणों को दूर किया जा सके और कामकारों को सुरक्षात्मक खुदाई तरीकों में प्रशिक्षण देना । इसके अलावा, खान के निरीक्षण के लिए एक आन्तरिक संगठन बनाने का भी प्रस्ताव है । यह संगठन उत्पादन स्कंध से स्वतंत्र होगा तथा खान सुरक्षा महानिदेशक के प्रयासों में सहयोग देगा ।

आयुध कारखानों से गोलों की चोरी के बारे में जांच

1283. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के अनुसार समस्तीपुर में जिस गोले का प्रयोग किया गया तथा जिस में भूतभूर्व रेलवे मंत्री की मृत्यु हुई, वह एक ऐसा गोला था जिसका निर्माण देश के आयुध कारखानों में से एक में किया गया था ;

(ख) क्या इसी प्रकार के एक गोले का प्रयोग कुछ महीनों पूर्व आनन्द मार्गियों द्वारा भी किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इस प्रकार के गोलों की कारखानों से किस प्रकार तस्करी हो रही है और जांच के क्या परिणाम निकले और इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (ग) समस्तीपुर घटनाओं की जांच पड़ताल का परिणाम प्रत्याशित हैं ।

पैकिंगों पर अनिवार्य रूप से मूल्य और वजन अंकित किया जाना

1284. **श्री वरके जार्ज** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैकिंग पर मूल्य छापने का कोई कानून विक्रेताओं पर लागू न होने के कारण उपभोक्ताओं को विवश होकर सभी वस्तुओं का अनुचित अधिक मूल्य अदा करना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि वस्तुओं पर उनके मूल्य तथा कुल मात्रा या भार अनिवार्य रूप से अंकित किये जायें; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) विक्रय के लिए अनेक वस्तुओं की पैकेजिंग से ढलाई तथा विवणन में आसानी होती है । तथापि, कानूनी उपबन्धों के अभाव में अनेक वस्तुओं की पैकेजिंग से उपभोक्ताओं को संरक्षण नहीं मिल सकेगा, जब तक कि उस पर निश्चित रूप से भीतर की सामग्री के बारे में ठीक सूचना नहीं दी जाए । इसलिए सरकार उपयुक्त मामलों में विधान बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ताकि उपभोक्ताओं के हित में यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैकेजिंग की शर्तों को पूरा किया जाये, जिससे तोल, मूल्य, विनिर्माण की तारीख आदि देना अनिवार्य हो ।

Setting up of a Super Thermal Power Station in Singrauli in Madhya Pradesh

1285. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state the obstacles in the way of according sanction for setting up of a super thermal power station in Singrauli in Madhya Pradesh in view of the recent reports that large scale mining of coal has been undertaken there in collaboration with USSR and in view of the fact that Power is in great demand in the State on account of expansion of Bhilai Steel Plant ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): The question of setting up large thermal stations near pit heads (including Singrauli Coal Fields) is being looked into by a Committee of Experts and their report is awaited.

Construction work of Power Projects in M. P. affected by non-allotment of Steel and Cement

1286. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether the construction work of power projects in Madhya Pradesh has been adversely affected due to non-allotment of steel and cement in sufficient quantity; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Making available Mata Tila Project Report to M. P. by U. P.

1287. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state whether the Uttar Pradesh Government has been made available to the Madhya Pradesh Government the Mata Tila Project report and other technical details?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): No. Sir.

Supply of Power to Madhya Pradesh from Hirakud Project

1288. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether there is no agreement specifying the quantity of power to be supplied to Madhya Pradesh from Hirakud project ;

(b) if so, the difficulty faced by Government in fixing the quantity of power from Hirakud to which Madhya Pradesh is entitled on the basis of its contribution of water and catchment area ;

(c) whether Madhya Pradesh and Orissa States had agreed to supply power to Madhya Pradesh from Hirakud on the basis of actual cost of generation and transmission; and

(d) if so, the action taken by the Central Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) to (d) The Government of Orissa had agreed to supply 5000 KW of power from Hirakud to Madhya Pradesh. The Madhya Pradesh Government had desired that the Government of Orissa should give power from Hirakud at the cost of generation and transmission. There is, however, a difference of opinion between the two Governments on the rate at which power is to be supplied. The matter has been taken up with the State Governments.

पूर्वी जोन के लिए औद्योगिक परियोजनाएं

1289. **श्री टुना उरांव**

श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मनीपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में औद्योगिक बस्तियों स्थापित करने हेतु वर्ष 1974–75 के लिए अनेक परियोजनायें मंजूर की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजना की, राज्यवार, मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 1974–75 की अवधि में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत अथवा शुरू की गई औद्योगिक बस्ती परियोजनाओं के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी, ग्रामीण और लघु उद्योगों के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के लिए 1974–75 की अवधि में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी-परिव्यय निम्न प्रकार है :—

योजना आयोग द्वारा सहमत पूंजी-परिव्यय ग्रामीण और लघु उद्योग योजनाएं (लाख रु० में)

राज्य का नाम	वार्षिक योजना (1974-75)
1. पश्चिम बंगाल	195.00
2. असम	150.00
3. त्रिपुरा	43.00
4. मणिपुर	59.00
5. नागालैंड	17.00
6. मिजोरम	21.00
7. अरुणाचल प्रदेश	12.40

ऊपर दिये गये पूंजी-परिव्यय में औद्योगिक बस्तियों का पूंजी व्यय शामिल है ।

पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय में कागज परियोजनाओं का स्थापित किया जाना

1290. **श्री टुना उरांव** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय में कागज मिलों को स्थापित करने सम्बन्धी योजनायें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या आशय-पत्र जारी कर दिये गए हैं; और

(ग) राज्य-वार तथा परियोजना-वार योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) संबंधित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०–9019/75]**

पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मनीपुर और मेघालय में डाकघर स्थापित करना

1291. **श्री टुना उरांव**

श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में अब तक पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मनीपुर और मेघालय में स्थापित किए गए डाकघरों की संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघर खोले गए हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर डाकघर खोले गए हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) सम्बन्धित सूचना इस प्रकार है :–

1. पश्चिम बंगाल	66
2. असम	कोई नहीं
3. त्रिपुरा	कोई नहीं
4. मणिपुर	4
5. मेघालय	2

(ख) (i) वर्ष 74-75 में निम्नलिखित राज्यों में देहाती इलाकों में खोले गए डाकघरों की संख्या नीचे बताई गए है :–

1. पश्चिम बंगाल	54
2. असम	कोई नहीं
3. त्रिपुरा	कोई नहीं
4. मणिपुर	4
5. मेघालय	2

(ii) ऊपर (ख) (i) में बताए गए जिन स्थानों पर डाकघर स्थापित किए गए हैं, उनके नाम अनुबन्ध में दिए गए हैं ।

विवरण

खोले गए देहाती डाकघरों के नामों की सूची

(क) **पश्चिम बंगाल**

(1) निम्बुद्रा	(2) हरबरडुबल	(3) साबरी
(4) बुराह	(5) नाथुडांगा	(6) कृष्णनगर
(7) पंचारादेवली	(8) भिकेनदोहो	(9) जिरावेद
(10) मरादिह	(11) राजमाम	(12) कलापाथरी

(13) बागडिहा	(14) अटला	(15) कुखुदिहो
(16) इटागोरिया	(17) गनसारिशा	(18) टामा
(19) मुरसोंग सिनचोना प्लान्टेशिन	(20) चन्द्रबन	(21) मखुंडा
(22) सावानगर	(23) बाउल	(24) कराय
(25) भोलानाथपुर	(26) हालिदानार	(27) पतिराजपुर
(28) आलोकेझारो	(29) छागलबेर	(30) चान्दाचौरा
(31) इथेलबाड़ी क्रासिंग	(32) कलायपुरी	(33) लउपारा
(34) जयन्तीपुर	(35) जुगोडिहा	(36) फुलबारी
(37) मुराबानी	(38) बरसोले	(39) मोरेग्राम
(40) रोसनबाग	(41) गुनानौडावाटो	(42) कदमटाला
(43) भोला	(44) राजधरपारा	(45) अहरीपारा
(46) घरबु इंचा	(47) देवग्राम-गंगआपुर	(48) कल्याणदाहा
(49) तैंगहारी	(50) छोरापोटा-मुकुन्दापुर	(51) डमडमा
(52) वैंद्यट	(53) पुरकैतपारा	(54) अब्दुलपुर

(ख) **मणिपुर** : (1) तारीबेरी (2) खोंग बंग (3) निगांमबाम (4) चलवा

(ग) **मेघालय** : (1) सिमसोनगिरि (2) दारांग

प्रतिवर्ष प्रत्येक पत्रिका को एक पृष्ठ का विज्ञापन दिए जाने की मांग

1292. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता में बड़ी संख्या में छोटे समाचारपत्रों की बैठक में यह मांग की गई कि प्रति वर्ष प्रत्येक पत्रिका को कम से कम एक पृष्ठ का विज्ञापन दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Laying of Telephone Lines from Gwalior to Lahar and Gohad

1293. **Shrimati V. R. Scindia** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the steps taken to implement the scheme already approved for laying new telephone lines from Gwalior to Lahar and Gwalior to Gohad in Bhind district of Madhya Pradesh.

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): There is no scheme for laying new telephone lines from Gwalior to Lahar and Gwalior to Gohad. Gwalior has already a direct circuit to Gohad. It is not technically possible to connect Gwalior directly to Lahar, as Lahar is a small automatic exchange parented to Bhind.

मोटर्स सेल्स लिमिटेड, लखनऊ द्वारा जीपों की बिक्री

1294. **श्री मधु लिमये :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटर्स सेल्स लिमिटेड द्वारा, जो मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड से मिले हुये हैं, जीपों की अनधिकृत बिक्री को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा ने स्पष्ट रूप से बताया है कि मोटर सेल्स लिमिटेड, लखनऊ उनका न तो विक्रेता है और न उप-विक्रेता है तथा उनकी पुरानी जीपों की बिक्री से उनका कोई संबंध नहीं है।

बिहार तथा अन्य राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में दंगे

1295. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में बिहार तथा अन्य राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में दंगे हुए थे;

(ख) क्या बिहार के संथाल परगना जिले में एक आदिवासी ग्राम में अनेक व्यक्ति मारे गये थे और सैकड़ों व्यक्ति घायल हो गये थे ;

(ग) क्या संथाल लोग तोड़ फोड़ करने लगे और उन्होंने ग्राम में आतंक फैला दिया तथा अन्धाधुंध लूट-पाट करने लगे और आग लगाने लगे ;

(घ) क्या गैर आदिवासी लोगों पर आक्रमण किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो देश के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले गैर-आदिवासी लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गांव चिरूडीह, थाना नारायणपुर, जिला सन्थाल परगना में और गिरिडीह जिला के गन्डी थाना में आदिवासियों तथा गैर-आदिवासियों के बीच मुठ भेड़ हुई थी। असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, नागालैण्ड और पंजाब राज्यों में हाल में ऐसी कोई मुठभेड़ सूचित नहीं की गई है। शेष राज्यों के बारे में सूचना प्रत्याशित है।

(ख) से (ङ) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सन्थाल परगना जिले के थाना नारायणपुर के अन्तर्गत गांव पबिया में 21 और 22 जनवरी, 1975 को हिंसक घटनाएं हुई थी। 21 जनवरी को चार आदिवासियों पर आक्रमण किया गया था और उनकी एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई थी। अगले दिन आदिवासियों द्वारा गांव के मुखिया और एक अन्य गैर-आदिवासी पर आक्रमण किया गया था । इन घटनाओं के परिणामस्वरूप 23 जनवरी, 1975 को थाना नारायण-पुर के अन्तर्गत चिरुडीह गांव के पास तनाव बढ़ गया था, जब आदिवासी और गैर-आदिवासी भारी संख्या में जमा हो गए थे। दोनों दलों में मुठभेड़ हुई। गैर-आदिवासियों के 14 मकान जला दिये गये थे और 11 गैर-आदिवासियों की जानें गई। सन्थालों की भीड़ में कुछ व्यक्तियों को सम्भवत: चोटें आई थीं, किन्तु भीड़ उन्हें ले गई थीं । पुलिस ने सात सन्थालों और छ: गैर-सन्थालों समेत 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। चार ज्ञात व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148/149/302/436 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था। तनी गांव की आगजनी की घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/433/

452/380 के अधीन एक दूसरा मामला दर्ज किया था। दोनों मामलों की जांच-पड़ताल हो रही है ।

क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में बताई जाती है। पुलिस अधिकारियों और सशस्त्र बल के साथ मैजिस्ट्रेट उस स्थल पर शिविर डाले हुए हैं। क्षेत्र की गश्त समेत कड़े पूर्वोपाय किए गए हैं।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार ने आदिवासी जिलों में अधिकारियों को सजग रहने के लिए सतर्क किया है ।

Foreign Assistance for Development of Coal Mines

1296. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether foreign assistance is being received for proper and scientific development of Indian coal mines; and

(b) if so, the names of mines for which assistance is being received from other countries indicating the names of such countries?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) Yes, Sir.

(b) Sudamdih and Monidih collieries of Bharat Coking Coal Limited are being developed with Polish assistance. Polish assistance has also been obtained for reorganisation and reconstruction of coking coal mines in the Jharia coalfield. Russian assistance is being received for developing Jayant Mine in Singrauli, Jhanjra mine in Raniganj and an opencast mine at Ramgarh coalfields.

Films shown at Film Festival, Country-wise

1297. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the names of the films screened country-wise in the International Film Festival held in Delhi as also the number of Indian Films among them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): A statement is attached [**Placed in the Library. See No. L.T.-9020/75**].

India was represented in the Festival by one feature film and two short films in the Competition Section; and 15 feature films and 10 short films in the Information Section.

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी

1298. **श्री धामनकर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी-इर्विन समझौते के अन्तर्गत आने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को छोड़कर स्वतन्त्रता सेनानियों के ऐसे मामले कितने हैं जिनमें स्वतन्त्रता सेनानियों को 6 महीने के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया था परन्तु सरकारी अधिकारियों ने उन्हें कारावास की अवधि में केवल अच्छे आचरण के आधार पर 35 दिन तक की छूट दे दी थी ; और

(ख) जेल अधिकारियों द्वारा 6 महीने के कठोर कारावास में अधिकतम कितनी छूट दी जा सकती है और क्या ऐसी छूट स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन की मंजूरी के लिए अनुग्रह अवधि के रूप में दी जाती है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्र करने में लगने वाला समय तथा श्रम, प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) जेल नियम पुस्तिकाओं के अन्तर्गत छः महीने की सजा के लिए स्वीकृत की गई अधिकतम छूट प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। तथापि भारत सरकार ने केन्द्रीय राजनैतिक पेंशन स्वीकृत करने के लिए 30 दिन की अधिकतम छूट देने का निर्णय किया है।

रक्षित बिजली घरों की स्थापना

1300. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े औद्योगिक कारखानों को रक्षित बिजली घरों की स्थापना करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, बशर्ते वे ईंधन की अतिरिक्त खपत किये बिना ही उनका संचालन करें ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने संयंत्रों की स्थापना किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या योजनाबद्ध रूप में इस बात का कोई अध्ययन किया गया है कि इस तरीके से कितनी मात्रा में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जबकि ऐसा कोई साधारण निर्णय नहीं है, परन्तु उद्योगों को ऐसे मामलों में अपने कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है जिनमें प्रक्रिया भाप (प्रोसेस स्टीम) और विद्युत, दोनों कुल ऊर्जा परिकल्पना पर आधारित होते हैं। कप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना के प्रत्येक मामले पर, इसके गुणदोषों के आधार पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

1301. **श्री वयालार रवि**

श्री ए० के० गोपालन :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त वित्तीय सहायता से केरल राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्य की गति हाल में धीमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस राज्य में अब क्रियान्विति की जा रही योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं तथा उनके लिए वर्ष 1974-75 में कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई और इन कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) केरल राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि अल्युमीनियम कन्डक्टरों की कमी के कारण केरल में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन में अस्थायी रूप से धीमी गति आ गई है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाता है और उनके राज्य बिजली बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा योगात्मक ऋण सहायता दी जाती है। निगम ने अब तक केरल राज्य बिजली बोर्ड की 17 स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनके लिए 7.73 करोड़ रुपये की ऋण सहायता अपेक्षित है। इन स्कीमों में केरल के 463 गांवों में 9 036 कृषि पम्पसेटों का अर्जन, 1,517 लघु औद्योगिक यूनिटों, 85,530 वाणिज्यिक और घरेलू कनेक्शनों तथा 18,734 गली-बत्तियों को विद्युत की सप्लाई करना परिकल्पित है। इनमें से 60.05 लाख रुपये की ऋण सहायता वाली एक स्कीम 1974-75 में स्वीकृत की गई है। ये सभी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

ई० सी० ग्रेड एल्युमीनियम के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एल्युमीनियम उद्योग के लिए अधिक विद्युत की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाये गए हैं। इससे ग्राम विद्युतीकरण के कार्यों के लिए एल्युमीनियम कंडक्टरों की उपलब्धता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली से कोचीन और नई दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

1302. **श्री वयालार रवि :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन और नई दिल्ली के बीच और त्रिवेन्द्रम और नई दिल्ली के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में किए गए कार्य में कितनी प्रगति हुई है तथा इसके कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) जी हां।

(ख) (i) त्रिवेन्द्रम—नई दिल्ली उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा को चालू करने की योजना त्रिवेंद्रम, मद्रास और दिल्ली के तीन ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों के जरिये और लम्बी दूरी के चैनलों के लिए त्रिवेन्द्रम-मद्रास, मद्रास-बम्बई और बम्बई-दिल्ली के संक्शनों की चौड़ी पट्टी और माइक्रोवेव/कोएक्सियल माध्यमों का इस्तेमाल करके बनाई गई है। आवश्यक स्कीमों को अन्तिम रूप देकर इनकी मंजूरी दे दी गई है। उपस्कर की स्थापना के लिए उसकी सप्लाई के आर्डर दिए गए हैं। उपस्कर और केबलों आदि की डिलीवरी के मौजूदा अनुमान के आधार पर आशा है कि यह उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग योजना वर्ष 1977 में चालू हो जायेगी।

(ii) प्रस्ताव के अनुसार कोचीन और नई दिल्ली के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा छठी योजना के दौरान चालू होने की सम्भावना है।

उपग्रह कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में टी० वी० सेटों की स्थापना करना

1303. **श्री वयालार रवि :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उस उपग्रह से कार्यक्रमों को प्राप्त करने, जिसके इस वर्ष के मध्य तक हमारे देश की अन्तरिक्ष कक्ष में आने की सम्भावना है और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन सैटों की स्थापना करने सम्बन्धी तैयारी के कार्यों में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) वर्ष 1976 के मध्य के पश्चात् जबकि उपग्रह हमारे देश की अन्तरिक्ष कक्ष से बाहर चला जाएगा, इन कार्यक्रमों के प्रसारण को चालू रखने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अन्तरिक्ष विभाग द्वारा गांवों का चयन लगभग मुकम्मल हो गया है। इलैक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड जिसने 2400 सीधे रिसेप्शन टेलीविजन सैट सप्लाई करने हैं, ऐसे 1300 से अधिक सैट उपग्रह संचार टेलीविजन प्रयोग के विभिन्न समूह मुख्यालयों को दे दिये हैं और इनमें से 1100 से अधिक सामुदायिक केन्द्रों में लगा दिए गए हैं।

राज्य सरकारों ने सभी सामुदायिक केन्द्रों के विद्युतीकरण का दायित्व अपने हाथ में लिया है और यह कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है। यह काम कर्नाटक समूह में पहले ही पूरा हो चुका है।

(ख) प्रयोग की समाप्ति के पश्चात् उपग्रह संचार टेलीविजन प्रयोग के समूह क्षेत्रों में सेवा जारी रखने हेतु प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार, बहुत से ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। विशिष्ट रूप से तैयार किए गये टेलीविजन सैटों में जो प्रयोग के दौरान उपग्रह से सीधे कार्यक्रम प्राप्त करेंगे, स्थलीय ट्रांसमिटरों से कार्यक्रम प्राप्त करने हेतु परिवर्तन किया जा सकता है।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों के नामांकन की कसौटी

1304. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड (सेन्ट्रल बोर्ड आफ फिल्म सेंसरज) के सदस्यों को नामांकन करने के लिए कोई कसौटी बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) सदस्यों की कार्यविधि क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) फिल्म सेंसर बोर्ड चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अनुसार गठित किया जाता है। बोर्ड के अध्यक्ष एक पूर्णकालिक सरकारी अधिकारी हैं जबकि इसके 9 गैर-सरकारी सदस्य अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक रूप में नियुक्त किये जाते हैं। सार्वजनिक जीवन में प्रख्यात व्यक्ति जो फिल्म उद्योग में अथवा पत्रकारिता, शिक्षा, कला, संस्कृति और सामाजिक कार्य जैसे सम्बन्धित क्षेत्रों में सुप्रसिद्ध हैं इसके सदस्य हैं।

विभिन्न भाषाओं की फिल्मों के उत्पादन के लिये सहायता के बारे में सरकार की नीति

1305. **श्री नारायण चन्द परासर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न भाषाओं की फिल्मों के उत्पादन के बारे में अथवा फिल्मों के उत्पादन के लिए सहायता के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) किन भाषाओं को फिल्मों के उत्पादन के लिये सहायता दी जाती है ;

(ग) क्या साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं को उस संबंध में सहायता दी जाती है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस संबंध में कुछ ऐसी भाषाओं को भी सहायता दी जाती है जो न भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित है और न जिन्हें साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कुछ अन्य ऐसी भाषाओं/बोलियों को भी इस प्रकार का संरक्षण दिया जायेगा जिन्हें मान्यता नहीं दी गई किन्तु वे देश में बोली जाती हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) भारत में फिल्म निर्माण निजी क्षेत्र में है। सरकार ने फिल्म उद्योग की भाषा का विचार किए बिना अच्छे स्तर की फिल्में बनाने हेतु धन, वित्तीय अथवा अन्य सुविधायें उपलब्ध कर सहायता करने और उसका विकास करने हेतु, फिल्म वित्त निगम स्थापित किया है

(ख) से (ङ) फिल्म वित्त निगम ऋणों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों पर फिल्म की भाषा का विचार किए बिना विचार करता है। ऋण प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर ही प्रदान किये जाते हैं।

गुरुगोबिन्द सिंह जी के जन्म दिन को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करना

1306. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गुरुगोबिन्द सिंह जी महाराज के जन्म दिन को सरकार द्वारा सार्वजनिक छुट्टी दी जाती है।

(ख) क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जन्म दिन को केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में गुरुगोबिन्द सिंह जी महाराज के जन्म दिन को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने का है?

गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) परक्राम्प लिखित (नेगोसिएबल इन्स्ट्रूमेन्टस) अधिनियम के अधीन बिहार सरकार द्वारा गुरुगोबिन्द सिंह जी के जन्म दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया गया है। किन्तु इस वर्ष चूंकि उनका जन्म दिन रविवार, 19 जनवरी, 1975 को पड़ता था इस लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से छुट्टी की घोषणा नहीं की गई थी। जहां तक बिहार में केन्द्र सरकार के कार्यालयों का सम्बन्ध है, उनके जन्म दिन की वैकल्पिक छुट्टियों की सूची में सम्मिलित किया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) श्री गुरुगोबिन्द सिंह जी महाराज के जन्म दिन को राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोयला उद्योग के लिए आवश्यक विस्फोटकों के निर्माण हेतु नए एकक

1307. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला उद्योग के लिए आवश्यक विस्फोटकों के निर्माण हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में दो नए एकक स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थापना किन किन स्थानों पर की जायेगी और वे कब से काम करना आरम्भ कर देगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) तथा (ख) भण्डारा में एक विस्फोटक संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया गया है तथा इस संबंध में तैयार की गई एक साध्यता रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। यह परियोजना सरकार की स्वीकृति तिथि से लगभग 3 वर्ष के समय में चालू हो पायेगी। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिन्दरी में एक विस्फोटक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। सरकार द्वारा निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने के बाद इस परियोजना के 2 वर्ष में पूरा होने की आशा है। रामगुन्डम में एक विस्फोटक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले का उत्पादन

1308. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद कोककर कोयले का महीनेवार, आज तक कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि में उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी होने के क्या कारण हैं

(ग) क्या प्राक्कलन समिति ने वर्ष 1974-75 के अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीयकरण के बाद कोककर कोयले के उत्पादन में कमी होने पर चिन्ता व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1-5-1972 से हुआ। भारत कोकिंग कोल लि०, कोयला खान प्राधिकरण लि० तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की खानों में कोककर कोयलें का मई, 1972 से दिसम्बर, 1974 के बीच माहवार उत्पादन नीचे दिया गया है :—

महीना	कोककर कोयले का उत्पादन		
	1972	1973	1974
		(लाख टनों में)	
जनवरी	—	14.90	14.70
फरवरी	—	14.40	13.60
मार्च	—	14.30	14.00
अप्रैल	—	13.00	13.00
मई	13.50	12.30	13.90
जून	13.40	13.00	13.30
जुलाई	13.10	13.30	15.40
अगस्त	13.40	13.40	15.60
सितम्बर	13.50	12.80	15.90
अक्तूबर	13.40	11.40	14.80
नवम्बर	13.70	12.70	15.80
दिसम्बर	14.60	13.50	16.90
			(अनन्तिम)

(ख) राष्ट्रीयकरण के बाद भारत कोकिंग कोल लि० की खानों में उत्पादन में मामूली सी कमी हुई जो अधिग्रहण के तत्काल बाद अस्तव्यस्त दशा, दामोदर नदी में बाढ़ के कारण रेत की कमी, अक्तूबर/नवम्बर, 1973 में भारी वर्षा के कारण खानों में पानी भर जाना, बिजली की सप्लाई में कमी, वैगनों तथा विस्फोटकों की कमी आदि के कारण हुई।

(ग) व (घ) जी हां, कोककर कोयला खानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए विविध उपाय किए गए हैं। बिजली सप्लाई की स्थिति में अब सुधार हो गया है। विस्फोटकों की सप्लाई में स्थायित्व आया है। और भारत कोकिंग कोल लि० ने लगभग 500 टन का एक भंडार बनाया है, जो आगामी वर्ष में बढ़ी हुई मांग को पूरा करेगा। हाल ही में ट्रेड यूनियनों के साथ एक मजदूरी समझौता हुआ है, जिससे औद्योगिक संबंधों में सुधार होगा और फलस्वरूप खानों को उत्पादकता में वृद्धि होगी। विवध उपायों के फलस्वरूप अब कोककर कोयले का उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया है।

समानान्तर गणतन्त्र दिवस तथा समारोह

1309. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा समानान्तर गणतन्त्र दिवस परेड और समारोह आयोजित किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) ऐसे समारोहों को आयोजित करने वाले व्यक्तियों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसे गैर-कानूनी कार्यों को रोकने के लिए क्या प्रतिरोधी उपाय किये गये हैं?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

चिनाब नदी पर सिलाल बिजली परियोजना का निर्माण

1310. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिनाब नदी पर सिलाल बिजली परियोजना, जिसके बारे में पाकिस्तान लगातार आपत्ति कर रहा है, अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है; और

(ख) यदि हां, तो उस देश के साथ सुधरते संबंधों को ध्यान में रखते हुए सिंधु जल संधि के अन्तर्गत सदैव के लिए कब तक मामले का समाधान होने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यह परियोजना निर्माणधीन है।

(ख) इस मामले को दोनों देशों के मध्य बातचीत द्वारा यथाशीघ्र हल करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के मूल्य में वृद्धि

1311. **श्री एस० आर० दामाणी**
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद से कोयले के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि हुई है तथा राष्ट्रीयकरण पूर्व के मूल्यों की तुलना में वर्तमान मूल्य कितना है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अकोककर कोयले के मूल्य 1-5-73 को राष्ट्रीयकरण के बाद एक बार तथा कोककर कोयले के मूल्य 1-5-72 को कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद तीन बार बढ़ाए गए हैं। अकोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व विभिन्न ग्रेड और आकार के अकोककर कोयले के मूल्य 31.45 रुपये तथा 48.00 रुपए प्रति टन के बीच थे। अकोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोककर कोयले के मूल्य 30.237 रु० तथा 45.00 रु० प्रति टन के बीच थे। विभिन्न किस्मों के कोयले और कोक के प्रचलित खान मुहाना मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) कोयले के मूल्य, अन्य बातों के अलावा, मजदूरी, उपकरण तथा सामान की लागत कामगारों की सुविधाओं आदि में वृद्धि को ध्यान में रखकर बढ़ाए गए हैं।

विवरण

विभिन्न ग्रेड के कोयले का 1 अप्रैल, 1974 से लागू खान मुहाना मूल्य

कोयले का ग्रेड	स्टीम कोयले का प्रति टन मूल्य	स्लैक कोयले का प्रति टन मूल्य
	अकोककर कोयला	
कम गोला कोयला	रु० पै०	रु० पै०
सलैक्टिड 'ए'	59.00	57.75
सलैक्टिड 'बी'	56.90	55.65
ग्रेड I	54.00	52.75
ग्रेड II	49.60	48.35
ग्रेड III ए	44.20	42.95
ग्रेड III बी	37.55	36.30
ज्यादा गोला कोयला		
सलक्टिड 'ए'	54.75	53.50
सलैक्टिड तथा सलैक्टिड बी	52.95	51.70
ग्रेड I तथा असम कोयला	48.95	47.70
ग्रेड II	43.15	41.90
ग्रेड III	36.80	35.55
बिना ग्रेड का कोयला	28.35	27.10
	प्रति टन औसत मूल्य	
सिंगरैनी कोयला	50.50	

कोककर कोयला

ग्रेड	प्रति टन कोयला मूल्य (आर० ओ० एम०)
	रु० पै०
ग्रेड ए	68.70
ग्रेड बी	67.25
ग्रेड सी	66.15
ग्रेड डी	65.00
ग्रेड ई	63.70
ग्रेड एफ	62.35
ग्रेड जी	61.05
ग्रेड एच	59.80
ग्रेड एच एच	56.00

टिप्पणी:—कोयले के वर्गीकरण की विशिष्टियां वही होंगी जो कोयला बोर्ड द्वारा ग्रेडिंग के लिए स्वीकार की गई हैं ।

हार्ड कोक तथा सौफ्ट कोक

कोक को ग्रेड	प्रति टन मूल्य
	रू० पै०
बो पी हार्ड कोक प्रीमियम	267.00
बीहाइव हार्ड कोक प्रीमियम	235.00
बीहार्डव हाइ कोक (बढ़िया)	164.00
बीहाइव हार्ड कोक (साधारण)	130.00
सौफ्ट कोक	86.00

सरकारी कर्मचारियों को नियत मूल्यों पर दैनिक प्रयोग की आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए स्टोरों का खोला जाना

1312. **श्री एस० आर० हामाणी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए उन स्थानों पर जहां इनकी संख्या अधिक नियत मूल्य पर दैनिक प्रयोग की सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने हेतु स्टोर खोलने में पहल करने पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अंडमान सरकार कृषक कर्मचारी संघ, पोर्ट ब्लेअर की मांगें

1313. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नैमित्तिक तथा दैनिक मंजूरी वाले मजदूरों में से मजदूरों को नियमित ऐसटेब्लिशमेंट में नियुक्त करने के बारे में अंडमान सरकार कृषक कर्मचारी संघ, पोर्ट ब्लेअर द्वारा की गई मांगों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) जब आवश्यकता पड़ती है तो नैमित्तिक मजदूरों को काम पर रखा जाता है। नियमित मजदूरों की रिक्तियां, नैमितिक मजदूरों तथा अवकाश रिक्तियों पर काम करने वाले मजदूरों को उनके गुण दोष के अनुसार उन पर नियुक्त करके भरी जाती है।

Sale of Bogus Educational Certificates

1314. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government's attention has been drawn to the news report in a Hindi daily on the 19th January, 1975 that bogus educational certificates had been sold for five hundred to five thousand rupees:

(b) if so, the Government's reaction thereto; and

(c) what steps are proposed to be taken to ensure that bogus educational certificates are not issued ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) Government have seen the news report published in a Hindi daily on 19-1-1975. On 25-9-1974, on a complaint from the Principal, R.L. Anand College, New Delhi, the R.K. Puram Police Station registered a case, F. I. R. No. 637, under sections, 420/478/471/120-B, I.P.C. and took up investigation. Nine persons have so far been arrested. Prosecution of persons connected with such forgeries and cheating and vigilance on the part of all concerned are expected to go a long way in checking such malpractices.

बहराइच (उत्तर प्रदेश) में बनों पर आधारित उद्योग

1315. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) में बनों पर आधारित कोई उद्योग स्थापित किया जायेगा।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

'पावर टिलरों' का उत्पादन

1316. **श्री मधु लिमये**: क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान की खेती के लिए जापानी किस्म का 'पावर टिलरों, ट्रैक्टरों से अधिक उपयोगी है ;

(ख) यदि हां, तो इन पावर टिलरों के उत्पादन के लिए कुल कितनी क्षमता बनाई गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों में विभिन्न निर्माता एककों में पावर टिलरों का वास्तव में उत्पादन कितना हुआ ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जहां कहीं नमी भूमि और लघु क्षेत्रफल वाली भूमि जुताई करनी होती है, वहां ट्रैक्टरों की अपेक्षा जापान के विद्युत हलों की वरीयता दी जाती है।

(ख) विद्युत हलों के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त क्षमता 36,000 प्रति वर्ष की है, जबकि अधिष्ठापित क्षमता 10,000 प्रतिवर्ष है।

(ग) गत तीन वर्षों में विद्युत हलों का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है :—

वर्ष	उत्पादन (संख्या में)
1972	264
1973	747
1974	2009

ट्रैक्टर उत्पादन

1317. **श्री मधु लिमये**: क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में ट्रैक्टर उत्पादन की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इनका वास्तविक उत्पादन कितना था ;

(ग) क्या देश में ट्रैक्टरों की बिक्री पर अभी भी लाभ होता है; और

(घ) यदि हां, तो देश में ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस समय वार्षिक आधार पर निर्धारित की गई अधिष्ठापित क्षमता 48,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष है।

(ख) गत तीन कलैंडर वर्षों का उत्पादन इस प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (संख्या में)
1972	18,295
1973	23,537
1974	29,052

(ग) एक विशेष प्रकार के ट्रैक्टर की अभी भी इतनी मांग है कि हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं फिर भी, सरकार को चोरबाजारी के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

(घ) गंभीर कठिनाईयों के बावजूद गत तीन वर्षों में ट्रैक्टरों के उत्पादन में वृद्धि की दर सरकार के सभी प्रयत्नों की सूचक है।

हरियाणा में बिजली की कम सप्लाई

1318. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय हरियाणा में बिजली की सप्लाई कम हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) किसानों को समय पर बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए बिजली की खपत को युक्तिसंगत बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) विद्युत की कमी के ये कारण हैं :—

(1) भाखड़ा जल-विद्युत प्रणाली से ऊर्जा की उपलब्धता में कमी होना।

(2) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान प्रणाली से ऊर्जा की उपलब्धता में समय समय पर कमी होना।

(3) फरीदाबाद ताप विद्युत केन्द्र पर यूनिटों को चालू करने तथा सुदृढ़ करने में देरी होना।

(4) विद्युत शक्ति के लिए मांग में वृद्धि होना।

(ग) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने राज्य सरकार के परामर्श से विद्युत की खपत को युक्तिसंगत बनाने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। इनमें राज्य के उद्योगों पर, मांग और ऊर्जा, दोनों पर ही 60 प्रतिशत कटौती तथा नगरीय संभरकों को प्रतिदिन 5 से 6 घण्टे तक बन्द रखना शामिल है। कृषि के क्षेत्र की आवश्यकता पर निर्भर रहते हुए, विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को 6 से 8 घंटे प्रति दिन तक विद्युत उपलब्ध की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार बदरपुर विद्युत केन्द्र से हरियाणा को सहायता करती रही है और इस समय वह राज्य इस केन्द्र में उत्पादित कुल ऊर्जा का लगभग 35 प्रतिशत तक सहायता के रूप में प्राप्त कर रहा है।

हरियाणा को निकटवर्ती प्रणालियों से अतिरिक्त सहायता देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में थोरियम का प्रयोग

1319. **श्री एन० ई० हीरो :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिये इंधन के रूप में थोरियम का प्रयोग करने के बारे में अनुसंधान करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) थोरियम को जब फास्ट ब्रीडर

टैस्ट रिऐक्टर में आवरण पदार्थ के रूप में काम में लाया जाता है तो वह यूरेनियम-233 में बदल जाता है; जिसको कि बिजली पैदा करने के लिए विदल्य पदार्थ के रूप में काम में लाया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टरों का विकास करने का काम शुरु कर दिया है। कलपक्कम स्थित रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र में लगाये जा रहे 40 मैगावाट क्षमता के फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर का उपयोग थोरियम के प्रयोग से सम्बन्धित विभिन्न तकनीकों का विकास करने के लिए किया जायेगा।

खान मालिकों द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कोयले की सप्लाई रोकने की धमकी

1320. **श्री एन० ई० हीरो**
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक खान मालिकों ने यह धमकी दी है कि यदि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान उनको देयभारी ऋण की अदायगी नहीं करता है तो वे उसकी कोयले की सप्लाई रोक देंगे; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित पार्टियों के बीच विवाद का मुख्य ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) तथा (ख) 31-1-1975 तक कोयला खान प्राधिकरण लि० तथा भारत कोकिंग कोल लि० की दिल्ली विद्युत प्रदाय प्रतिष्ठान पर 154.85 लाख रुपये की राशि बकाया है। इन संगठनों ने पत्र लिख कर प्रतिष्ठान से कहा है कि जब तक बकाया राशि नहीं चुकाई जाती कोयला नहीं भेजा जायेगा। यद्यपि पूरी बकाया राशि अभी भी चुकाई नहीं गई है फिर भी कोयले की पूर्ति को निलम्बित नहीं किया गया है क्योंकि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के लिए राजधानी तथा निकटवर्ती क्षेत्र को बिजली की पूर्ति करती है। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर विचार करने के लिए ऊर्जा मन्त्री ने 11-2-75 को सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी जिसमें बकाया राशि के यथा संभव शीघ्र भुगतान करने के लिये दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया था।

पीलीभीत में साम्प्रदायिक दंगा

1321. **श्री एम० के० कृष्णन**
श्री मोहम्मद इस्माइल :

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 दिसम्बर, 1974 को पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में हुए साम्प्रदायिक दंगे की ओर दिलाया गया है जिसमें तीन व्यक्ति मारे गये तथा अल्पसंख्यक सामुदाय की सम्पत्ति को हानि पहुंची;

(ख) यदि हां, तो इस हमले को करने वाले अपराधियों के विरुद्ध क्या कठोर कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या हताहतों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विकास में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पीलीभीत में 18, 19 व 20 दिसम्बर, 1974 को साम्प्रदायिक दंगे हुए जिन के परिणामस्वरूप तीन व्यक्ति मारे गये और सम्पति की हानि हुई। राज्य सरकार ने घटनाओं की जांच की थी और मृतकों के परिवारों को राहत देने तथा घटना से प्रभावित अन्य लोगों की क्षतिपूर्ति करने में 73000 रु० की धन राशि स्वीकृत की थी। इन दंगों के संबंध में 121 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक तथा नगर के कोतवाल का तबादला कर दिया गया है और उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राज्यों को कोयले के वितरण के बारे में योजना

1322. **श्री डी० बी० चन्द्रगोडा**
श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को कोयले के वितरण के बारे में कोई युक्तिसंगत योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) कोयला वितरण की वर्तमान युक्तिसंगत स्कीम के अन्तर्गत, कोककर कोयला, हार्ड कोक तथा प्रक्षालनशाला मिडिलिंग के वितरण पर कानूनी नियंत्रण है। जहां तक अकोककर कोयले का संबंध है, इसके वितरण पर नियंत्रण नहीं है। रेल द्वारा कोयला प्रेषण के लिए संचलन संबंधी प्राथमिकताओं को भारतीय रेलवे द्वारा अधिमान टेरिफ अनुसूची से शासित किया जाता है। रेलवे इस हेतु केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न प्रायोजक प्राधिकरणों की तत्संबंधी सिफारिश को ध्यान में रखता है।

चौथी योजना में विद्युत बोर्डों द्वारा किये गये पूंजी निवेश पर लाभ की दर

1323. **श्री वरके जार्ज** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युत बोर्डों का कुल पूंजी निवेश कितना है ;

(ख) इस पूंजी निवेश पर लाभ की दर क्या है ;

(ग) क्या इस पूंजी निवेश पर लाभ की दर बहुत कम है ; और

(घ) यदि हां, तो लाभ की ऊंची दर को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य बिजली बोर्डों के संबंध में नयी परिसम्पत्तियों का कुल मान तथा निर्माणाधीन कार्य पर व्यय की गई धनराशि का अनुमान 2470 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों के संबंध में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ की औसत दर का अनुमान 6.05 प्रतिशत है।

(ग) लाभ की दरें विभिन्न बोर्डों में और हर वर्ष के लिए भिन्न-भिन्न होती हैं। जबकि कुछ बोर्डों के मामले में लाभ की दरें उचित होती हैं, वे अन्य बोर्डों के संबंध में कम होती हैं।

(घ) बोर्डों के वित्तीय निष्पादन का समय-समय पर पुनर्वलोकन किया जाता है। बोर्डों द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(1) टैरिफ में वृद्धि;

(2) ताप-विद्युत केन्द्रों में अधिकतम उत्पादन करना;

(3) देर से बकाया चली आ रही राशियों की वसूली;

(4) प्रणाली में होने वाली हानियों को कम करना; और

(5) संपत्ति पर नियंत्रण।

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्यकरण की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी हाल में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

पिछड़े जिलों में औद्योगिक लाइसेंस देना

1324. **श्री वसंत साठे**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े जिलों में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए चालू वर्ष में राज्यवार कितने कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गए हैं ;

(ख) वर्ष 1973–74 के दौरान (राज्यवार) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए दिये गये लाइसेंसों की तुलना में चालू वर्ष में दिये गए लाइसेंसों की स्थिति क्या है ;

(ग) पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से औद्योगिक विकास करने हेतु क्या विशेष कदम उठाये गए हैं या उठाने का विचार है ; और

(घ) क्या पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं का कोई वर्तमान मूल्यांकन किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सरकार द्वारा जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों संबंधी आंकड़े केलेन्डर वर्षवार रखे जाते हैं। पिछड़े क्षेत्रों के लिए 1973 और 1974 में जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास और संवर्धन करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रोत्साहनों की घोषणा की है :

1. निश्चित निवेश पर सहायता संबंधी केन्द्रीय योजना। इस योजना के अधीन चुने हुए 98 पिछड़े जिले/क्षेत्र सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।
2. चुने हुए पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की 232 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आई०डी० बी०आई०, आई०एफ०सी० आई० और आई०सी०आई०सी०आई० से रियायती दर पर वित्त की व्यवस्था करना।

3. कच्चे माल और तैयार सामानों के जम्मू तथा काश्मीर उ० प्रदेश हिमाचल प्रदेश आदि में निश्चित स्थानों पर लाने ले जाने की लागत पर परिवहन सहायता प्रदान करना ।

4. केन्द्रीय सहायता के पांच जिलों/क्षेत्रों के लिए मशीनें कच्चे माल और उपकरण के आयात के लिए विशेष सुविधायें प्रदान करना ।

5. रियायती शर्तों पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया खरीद आधार पर मशीनों का संभरण करना ।

6. पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को कृताधान योग्य आय पर 20 प्रतिशत तक लाभ पर छूट देना । 1974–75 की अवधि में विभिन्न राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों और अन्य एजेन्सियों को निश्चित विनियोजन पर केन्द्रीय सहायता की प्रति पूर्ति के लिए करीब 1.25 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत की गई है । 1972–73 में यह स्वीकृत राशि 11.76 लाख रु० थी । इसी प्रकार पिछड़े क्षेत्रों की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए रियायती शर्तों पर सरकारी वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता की राशि 1971–72 के 68.03 करोड़ रु० की राशि से बढ़ाकर 1973–74 में 86.53 करोड़ रु० कर दी गई है । 1969–74 की अवधि में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए 216 लाख रु० मूल्य की मशीनों का संभरण किया गया ।

आई०डी०बी०आई० ने सभी पिछड़े हुए राज्यों संघ क्षेत्रों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है । अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहायता से जिन 48 परियोजनाओं का पता आई०डी० बी०आई० ने लगाया है उनमें कार्यान्वयन हो रहा है ।

पिछड़े क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योग स्थापित किये गए हैं टायर रिट्रेडिंग, कोल्ड स्टोरेज, चावल मिलें, बेकरी, अल्यूमीनियम के बर्तन, डिस्टिलिंग, रिरोलिंग इंजीनियरिंग, फल और वनस्पति, परिष्करणता चमड़ा कमाना, सीमेंट और उसके उत्पाद, कागज उत्पाद, तेल निकालने वाले संयंत्र, ए०सी०सी० और ए०सी०एस०आर० कन्डकटर्स बिजली का माल रेडियो आदि ।

पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए उद्योग विकास विनियमन अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंसों के लिए दिये जाने वाले आवेदनों को प्राथमिकता दी जाती है । जैसा कि निम्नलिखित सारिणी से स्पष्ट होता है इस अधिनियम के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों के लिए दिए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

	1972			1973			1974		
	बी	योग	प्रतिशत	बी	योग	प्रतिशत	बी	योग	प्रतिशत
एल०आई०	108	877	12.3	127	899	14.1	348	1181	29.1
आई०एल०	83	563	14.8	103	596	17.2	298	1099	27.1

बी० पिछड़े क्षेत्र के लिए हैं ।

सरकार द्वारा घोषित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का ब्यौरेवार मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है चूंकि ऐसा अनुभव किया गया है कि किसी भी प्रकार के अर्थपूर्ण अध्ययन करने के लिए इन योजनाओं का संचालन काल पर्याप्त लम्बा नहीं है। किन्तु मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से इन योजनाओं को स्वीकार कर लिया गया है और उद्यमकर्ताओं ने इनमें उत्साह प्रदर्शित किया है।

विवरण

1973 और 1974 में पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी और निजी दोनों के लिये जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	1973	1974
1. आन्ध्र प्रदेश	2	20
2. असम	3	3
3. बिहार	2	3
4. दादरा तथा नागर हवेली	—	1
5. गोआ दमन और दीव	4	6
6. गुजरात	10	18
7. हरियाणा	2	10
8. हिमाचल प्रदेश	—	1
9. जम्मू तथा काश्मीर	1	5
10. कर्नाटक	11	21
11. केरल	4	8
12. महाराष्ट्र	6	30
13. मध्य प्रदेश	2	25
14. मनीपुर	1	—
15. मेघालय	1	3
16. नागालैंड	—	1
17. उड़ीसा	—	7
18. पांडिचेरी	1	3
19. पंजाब	5	11
20. राजस्थान	1	21
21. तमिलनाडु	18	27
22. उत्तर प्रदेश	20	37
23. प० बंगाल	9	37
योग	103	298

आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों से संस्कृत में समाचार बुलेटिन

1325. **श्री बसन्त साठे:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत के समाचार बुलेटिन की अच्छी प्रतिक्रिया और बढ़ती हुई सराहना को देखते हुए सरकार ने आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों से भी संस्कृत में समाचार बुलेटिन प्रासरित करने के बारे में निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किये गये इस निर्णय की रूप रेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आकाशवाणी के माध्यम से संस्कृत के प्रचार के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है और ।

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) संस्कृत में समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के निम्नलिखित 29 केन्द्रों से रिले किया जा रहा है :—

अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुज, बम्बई, कलकत्ता, कालीकट, कटक, दिल्ली, धारवाड़, गोहाटी, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, जम्मू, जलंधर, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, पटना, पूना, पोर्ट-ब्लेयर, राजकोट, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, और विजयवाड़ा ।

फ़िलहाल किसी और केन्द्र में इसका विस्तार करने का विचार नहीं है ।

(ग) और (घ) आकाशवाणी पहले ही संस्कृत में और संस्कृत के उच्च-कोटि के ग्रंथों के बारे में कार्यक्रम प्रसारित करती है । वार्त्तायें, नाटक, कवितायें, संस्कृत भाषा के पाठ और संस्कृत की साहित्यिक रचनाओं का वर्णन आकाशवाणी के कार्यक्रमों का अंग हैं ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक

1326. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक को पुन:पुर:स्थापित करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में केरल की 'कुदुम्बी यूथ एण्ड स्टूडेंट्स फ़ेडेरेशन' से बहुत बड़ी संख्या में संकल्प प्राप्त हुए थे; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) केरल कुदुम्बी स्टूडेंट्स एसोसियेशन और केरल कुदुम्बी फ़ेडेरेशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अनुरोध किया गया है कि केरल की अनुसूचित जातियों की सूची में कुदुम्बी समुदाय को सम्मिलित करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 संबंधी संयुक्त समिति की सिफारिश मान ली जाए और संसद में आवश्यक विधान शीघ्र पुर:स्थापित किया जाए ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन करने के लिए, जितना जल्दी संभव हो सका एक विधान पुर:स्थापित करने का विचार है ।

केरल में नारियल जटा उद्योग को वित्तीय सहायता

1327. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री सी० जनार्दन :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य को नारियल जटा उद्योग को गंभीर संकट से बचा कर इसे सुदृढ़ बनाने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की थी ;

(ख) केरल सरकार द्वारा कितनी राशि का अनुरोध किया गया था और कितनी राशि दी गई थी ; और

(ग) इस परम्परागत उद्योग को बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या अतिरिक्त कदम उठाने का विचार हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) केरल सरकार द्वारा कॉयर विकास कार्यक्रम के लिए तैयार की गई पुनः प्रावस्थाबद्ध योजना में पांचवीं योजनावधि के लिए कुल मिला कर 41.72 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। अधिकांशतः कार्यक्रम के लिए वित्त बैंकों से लिया जाएगा जिसकी अनुपूर्ति सरकारी निधि से भी की जाएगी। पांचवीं योजना के राज्य क्षेत्र के प्रारूप में केरल के कॉयर उद्योग के विकास हेतु 12 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। राज्य योजना परिव्यय के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1973–74 और 1974–75 की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये तक की व्यवस्था राज्य सरकार के लिए की जा चुकी है और इसी कार्य के लिए 1975–76 में भी 1 करोड़ रुपए की सहायता करने का प्रस्ताव है। साथ ही राज्य में कॉयर उद्योग को कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने बैंक से ऋण लेने हेतु रिजर्व बैंक से आवश्यक व्यवस्था कर ली थी।

मिजोरम में कानून और व्यवस्था की स्थिति का घटनास्थल पर अध्ययन

1328. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में पुलिस के तीन उच्चाधिकारियों की हत्या के उपरान्त वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति का घटनास्थल पर ही अध्ययन करने के लिए उन्होंने हाल में मिजोरम का दौरा किया था ;

(ख) क्या उन्होंने विद्रोही नागाओं अथवा मिजो नेताओं के साथ नये सिरे से राजनीतिक वार्ता करने की बात को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था ;

(ग) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि श्री जयप्रकाश नारायण तथा कुछ ईसाई मिशनरियों के संरक्षण में "नागालैण्ड पीस कौंसिल" नामक संगठन विद्रोही नागाओं तथा मिजो नेताओं के साथ राजनीतिक वार्ता के समर्थन में खुले आम प्रचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) गृह मंत्री ने 21 और 22 जनवरी, 1975 को मिजोरम का दौरा किया था और विधि व व्यवस्था की स्थिति का घटनास्थल पर अध्ययन किया ।

(ख) यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक मिजो विद्रोही अपनी देश द्रोही गति विधि जारी रखते है तब तक कोई सार्थक बात चीत नहीं हो सकती ।

(ग) भारत सरकार और भूमिगत नागाओं के बीच बातचीत के माध्यम से नागालैण्ड में शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से नागालैण्ड के गिरजाघरों के नेताओं और कुछ प्रमुख नागरिकों को शामिल करते हुए नागालैण्ड शान्ति परिषद का गठन मार्च, 1974 में किया गया था ।

(घ) सरकार का सदैव यह दृष्टिकोण रहा है कि जब तक भूमिगत नागा अपनी पृथकतावादी मांग पर डटे रहते हैं और अपनी गैर-कानूनी तथा हिंसक गतिविधियां जारी रखते हैं तब तक कोई उद्देश्यपूर्ण बातचीत नहीं हो सकती ।

केरल के स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी मामले

1329. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी अधिकांश मामले इस आधार पर नामंजूर कर दिये गए हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी त्रावणकोर की भूतपूर्व रियासत की सरकार में सर सी०पी० रामास्वामी अय्यर द्वारा जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट संबंधी सरकारी दस्तावेजों को पेश नहीं कर सके जिनके कारण उन्हें भूमिगत होना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दीवान के शासन के समय ऐसे सरकारी रिकार्डों को न रखने की प्रथा थी; और

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव ऐसे मामलों पर अनुकूल ढंग से पुनर्विचार करने का है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) कारावास अथवा अन्य राजनैतिक यातनायें जो स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए योग्यतायें हैं का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना पेंशन योजना का एक आवश्यक अंग है । जहां पर्याप्त प्रमाण होते है उन मामलें में अस्थाई रूप से पेंशन स्वीकृत की जाती है । जहां निर्धारित राजनैतिक यातानाओं का दावा किया जाता है परन्तु आवेदक लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ होते है उनको ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा जाता है । साथ ही राज्य सरकार भी आवेदनों पर विचार करती है और सिफारिश करती है । 15 फरवरी, 1975 तक केरल के 8954 आवेदन पत्रों में से लगभग 4000 इस श्रेणी में आते है । जहां आवेदक अपने ही विवरण के अनुसार निर्धारित राजनैतिक यातनाओं के मानदण्ड पूरे नहीं करता वहां आवेदन अस्वीकृत किये जाते हैं । 15 फरवरी, 1975 तक अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या 3324 थी ।

(ख) इस विषय में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जैसा कि ऊपर कहा गया है ऐसे मामलों में जहां निर्धारित राजनैतिक यातनाओं का दावा किया जाता है परन्तु प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है उनको अंतिम रूप से रद्द नहीं किया जाता है। ज्यों ही उनका प्रमाण उपलब्ध हो जायेगा, उन पर विचार किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश को बिजली की सप्लाई

1330. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि नहीं, तो वहां पर अन्य राज्यों से बिजली की सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। स्थिति पर बराबर निगरानी रखी जा रही है।

उत्तर प्रदेश में अधिक विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना

1331. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में और अधिक विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के लिए पांचवीं योजना के प्रारूप में निम्नलिखित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं शामिल की गई हैं :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट में)
	(क) सतत स्कीमें	
	एक—जल-विद्युत परियोजनायें	
1.	**यमुना चरण–दो**	
	(1) भाग–एक चिबरो विद्युतकेन्द्र	4 × 60
	(2) भाग–दो खोदरी विद्युत केन्द्र	4 × 30
2.	यमुना चरण–चार	
	(1) कुलहल विद्युत केन्द्र	3 × 10
3.	रामगंगा जल-विद्युत	3 × 66
4.	मनेरी भाली भाग–एक	3 × 30
5.	टिहरी बांध	4 × 150
	दो—ताप-विद्युत परियोजनायें	
1.	ओबरा तापीय विस्तार चरण–एक	2 × 100
2.	ओबरा तापीय विस्तार चरण–दो	3 × 200

1	2	3
3.	पंकी तापीय विस्तार	2×110
4.	हरदुआगंज चरण–पांच	1×110
	(ख) नई स्कीमें	
	एक––जल-विद्युत परियोजनायें	
1.	ऋषिकेश–हरिद्वार	3×36
	दो––ताप-विद्युत परियोजनायें	
1.	ओबरा तापीय विस्तार चरण–तीन	2×200
2.	हरदुआगंज चरण–छः	2×55

जिन परियोजनाओं को छठी योजना के लिए अग्रिम कार्यवाही के रूप में हाथ में लिया जाना है, उन्हें अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है ।

शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग

1332. **श्री एस०एम० बनर्जी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा को प्रयोग करने के लिए आगे कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या हाल की उपलब्धियों को दिखाने वाली सूची को सभा पटल पर रखा जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा औद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में करने के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों का ब्यौरा इस विभाग के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन में दिया गया है । यह प्रतिवेदन माननीय सदस्यों के लिए प्रचारित किया गया था तथा उसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) हाल में की गई उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक सूची अनुलग्नक में दी गई है ।

विवरण

पिछले कुछ समय की परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों से सम्बन्धित उपलब्धियां

1. 18 मई, 1974 को राजस्थान के पोखरन नामक स्थान पर शान्तिमय प्रयोजनों क लिये परमाणु विस्फोट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया । यह परीक्षण भू-विज्ञान की दृष्टि से उपयुक्त माध्यम में एवं जमीन के भीतर किया गया था तथा इसका उद्देश्य विभिन्न शान्तिमय अनुप्रयोगों के लिए इस प्रकार के विस्फोट की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करना था । इस परीक्षण के करने से भारत ने अत्यधिक जटिल नाभिकीय तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा कदम रखा है ।

2. गोरिबिदनूर स्थित भूकम्प मापी केन्द्र ने जमीन के भीतर किए गए सभी प्रमुख परमाणुपरीक्षणों का पता लगाया, जिन में पोखरन में किया गया परीक्षण भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, 17 जून, 1974 को चीन द्वारा लाप नौर क्षेत्र में वायुमण्डल में किये गए परमाणु विस्फोट के 4 घंटे के भीतर ही इस केन्द्र ने उस विस्फोट की शिनाख्त करके उसकी शक्ति का पता लगा लिया।

3. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की केन्द्रीय वर्कशाप में विद्युत रियेक्टरों के लिए ईंधन मशीन के प्रमुख उपकरणों सहित बहुत से अत्यन्त परिष्कृत किस्म के उपकरणों का निर्माण किया गया। यह काम नाभिकीय तकनीक में आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

4. कलकत्ता में स्थापित किये जाने वाला परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान का निर्माणकार्य पूरा होने वाला है। नाभिकीय भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी, नाभिकीय रसायन, विकिरण से हुई क्षति एवं पदार्थों की जांच, विकिरण जीव-विज्ञान तथा विकरण आइसोटोपों की सहायता से प्रेरित आवेशित कणों के उत्पादन से संबंधित अध्ययन करने के लिए इस अत्यधिक जटिल साइक्लोट्रान की स्थापना करना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

5. हाल ही में ट्राम्बे में चालू किये गए आइसोमैड नामक संयंत्र से, जो कि डाक्टरी कामकाज में आने वाले सामान को विकिरण की सहायता से निजर्मीकृत बनाता है, सहायक उद्योगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के काम को, खासतौर से डाक्टरी कामकाज में आने वाले प्लास्टिक उपकरणों का निर्माण करने के काम को, प्रमुख रूप से प्रोत्साहन मिला है। यह संयंत्र विकासशील देशों, खासतौर से दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों, के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशयनों को विकिरण द्वारा विसंक्रमण करने के सभी पहलुओं में प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्र के रूप में काम करेगा।

6. हैदराबाद स्थित नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के विशिष्ट सामग्री संयंत्र के 60 किलोवाट क्षमता वाले उच्च शक्ति के इलैक्ट्रान किरण-पुंज की सहायता से संगलन करने वाला एक यूनिट चालू किया गया है। टेंटेलम, नायोबियम तथा जर्कोनियम जैसी अपवर्तनशील तथा प्रतिक्रियाशील धातुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को इस यूनिट से बड़ा लाभ पहुंचेगा।

7. सान देने का काम अत्यधिक परिशुद्धता के साथ करने वाली एक समतल मशीन, जो की भारत में विकसित की गई इस प्रकार की पहली मशीन है, का डिजायन तैयार करने तथा निर्माण करने का काम भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा किया गया। इस मशीन की क्षमता 2000 मिलिमीटर गहराई तक, जिसको कि 3000 मिलिमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, 50 मिलिमीटर से लेकर 125 मिलिमीटर तक के व्यास वाले छेद करने की है। इस मशीन के निर्माण के लिए संघटकों का आयात करने की आवश्यकता नहीं है तथा यह मशीन बाहर से मंगाई जाने वाली इस प्रकार की मशीन से बहुत सस्ती होगी।

8. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लेसर अनुभाग के कार्यक्रम का एक दीर्घकालीन उद्देश्य लेसर से उत्प्रेरित संगलन करना है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित सभी क्षेत्रों में लेसर तकनीक का विकास करना इसका एक संबद्ध कार्यक्रम है। दो प्रकार के मुख्य

लेसरों का विकास किया गया है---अर्थात् नियोडाइमियम-आलेपित ग्लास लेसर तथा कार्बन-डाईआक्साइड लेसर। प्लाजमा चैम्बर, जिसमें कि प्लाजमों पर प्रारम्भिक रूप से प्रयोग किये जायेंगे, बनकर तैयार होने वाला है। स्पंदित नाइट्रोजन लेसरों का संचालन सफलतापूर्वक किया जा चुका है, जोकि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

स्वर्गीय बेगम अख्तर और स्वर्गीय अमीर खां साहेब पर डाक टिकटें

1333. **श्री एस०एम० बनर्जी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विख्यात संगीताज्ञ स्वर्गीय बेगम अख्तय और स्वर्गीय अमीर खां साहेब, जिनका हाल ही में निधन हुआ है की स्मृति में डाक टिकटें जारी करने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) फिलाटली सलाहकार समिति ने बेगम अख्तर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट निकालने के प्रस्ताव पर विचार किया था लेकिन यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका। स्व० अमीर खान साहिब के सम्मान में डाक टिकट जारी करने के बारे में अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन इसे फिलाटली सलाहकार समिति के विचारार्थ रख दिया जाएगा।

प्राथमिकता वाले उद्योगों को कोयले के प्रेषण में वृद्धि

1334. **श्री गजाधर मांझी**
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान प्राथमिकता वाले उद्योगों को कोयले के प्रेषण में हाल ही में कोई वृद्धि हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) कोयला खान प्राधिकरण, भारत कोकिंग कोल लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा गत छः महीनों (जुलाई–दिसम्बर, 74) तथा गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को कोयले के प्रेषण का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है :—

(आंकड़े लाख टनों में)

	अनन्तिम जुलाई–दिसम्बर 1974	जुलाई–दिसम्बर, 1973	अन्तर
1. लोको	72.23	67.01	+ 5.22
2. इस्पात संयंत्र	29.88	29.42	+ .46
3. बिजलीघर	105.97	83.67	+22.30
4. सीमेंट	22.42	16.88	+ 5.54
5. टैक्सटाइल	10.53	8.13	+ 2.40

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का कार्यालय कलकत्ता स्थानान्तरित करने के प्रयत्न में लगे अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

1335. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री एम० वी० कृष्णप्पा
श्री एस० एम० मिश्र :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन आफ इंडिया के कुछ उच्च अधिकारियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो निगम के कार्यालयों को नई दिल्ली से स्थानान्तरित करने का प्रयत्न कर रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान कागज निगम के मुख्यालय का स्थान बदलने के विषय में कुछ सामान्य शिकायतें मिली हैं। इन अभिकथनों में कोई तत्व नहीं है क्योंकि निगम के मुख्य कार्यालय को दिल्ली से कलकत्ता ले जाने का निर्णय केवल गुणाव गुणों पर लिया गया है।

समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन के उद्घाटन के सम्बन्ध में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार बुलेटिनों में गलती

1336. **श्री फूलचन्द वर्मा**
श्री राम रत्न शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय श्री एल०एन० मिश्र द्वारा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन के उद्घाटन उनके भाषण के सारांश और नई रेल गाड़ी को मुजफ्फरपुर के लिये पहली बार चलाये जाने के बारे में 2 जनवरी, 1975 को 2 बजे म०प० और 2 बजकर 10 मिनट म०प० पर आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार बुलेटिनों का सही और पूरा पाठ क्या है ;

(ख) वास्तविक तथ्यों और आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार में गलती होने के क्या कारण थे और इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति का नाम क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में वास्तविक तथ्यों और आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचारों में कितनी बार और किस किस तारीख को गलती हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया के समचार पर आधारित आकाशवाणी के समाचार का पाठ संलग्न है।

(ख) यह गलती इस तथ्य के कारण हुई कि यू०एन०आई० ने अपने संवाददाता से समय पूर्व पहले के एक समाचार के आधार पर तथा उद्घाटन समारोह में देरी की ओर बिना ध्यान दिये समाचार रिलीज कर दिया था।

(ग) आकाशवाणी सुप्रसिद्ध समाचार एजेंसियों सहित अधिकृत या विश्वस्त सूत्रों पर भरोसा रखता है। तथापि, ऐसे अवसर हो सकते हैं जब मानवीय कारण सहित कुछ कारणों से असावधानी से कुछ गलतियां हो सकती हैं। परन्तु इनको तुरन्त ही ठीक कर दिया जाता है।

विवरण

(दो जनवरी, 1975 के 2 बजकर दस मिनट के हिन्दी समाचार बुलेटिन का एक समाचार)

उत्तर पूर्व रलवे के समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशनों के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है। इस काम पर पांच करोड़ रुपया खर्च हुआ और 20 महीनों में यह पूरा हुआ।

नई रेलवे लाइन आज विधिवत चालू कर दी गई। यह रेलवे लाइन उत्तर बिहार के ऐसे इलाकों से गुजरती है जहां आबादी बहुत घनी है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं।

रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने नई रेलवे लाइन का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार में रेल व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने का विचार है। पटना के पास गंगा पर एक रेल पुल बनाया जाएगा जिस के लिए सर्वेक्षण हो रहा है। इस पुल का काम पांचवीं योजना की अवधि में शुरू हो जायेगा। समस्तीपुर और रक्सोल, रांची और लोहार डागा तथा बरोनी और कटिहार के बीच छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। इस सारे काम पर 43 करोड़ रुपया खर्च होगा। श्री मिश्र ने बताया कि बाराबंकी समस्तीपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बलदने के काम का दूसरा चरण शुरू हो गया है।

रेल मंत्री ने कहा कि पिछली मई में हड़ताल के कारण चालू वित्त वर्ष के पहले कुछ महीनों में रेलवे को जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई कर ली गई है, क्योंकि पिछले चार महीनों में रेलवे ने जितना माल सामान की ढुलाई की, वह एक रिकार्ड है। उन्होंने बताया कि अब एक दशक के बाद परिवहन के अन्य साधनों के मुकाबले रेलवे फिर सबसे अधिक माल-सामान ढोने लगी है।

दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधे डायल करने की व्यवस्था

1337. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच सीधे ट्रंक डायल व्यवस्था निश्चित रूप से कबतक संभव हो जायेगी ; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या विशेष उपाय किये हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) आशा है कि भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा वर्ष 1976-77 में चालू हो जाएगी। आवश्यक स्विचिंग और ट्रांसमिशन उपस्करों की व्यवस्था करने की योजनायें मंजूर की जा चुकी है। उपस्करों की स्थापना के लिये उनकी सप्लाई के आर्डर भी दे दिये गए हैं।

आशयपत्र जारी करने के पश्चात् उद्योग को चालू करने सम्बन्धी प्रक्रिया

1338. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री आशय पत्रों को कार्यान्वित न करने के बारे में 4 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3058 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार, कुल कितने उद्योग चालू किये गए ;

(ख) आशय पत्र जारी करने के पश्चात उद्योग को अन्तिम रूप से चालू करने के लिए किन विशेष अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है ; और

(ग) उक्त अवधि में उद्योगों को चालू करने के लिए राज्य-वार कुल कितने आशय पत्र जारी किये गए ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) आशयपत्र धारियों को आवश्यक अनापतियों (क्लीरेन्स) प्राप्त करने और अपने आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने हेतु अधिकतम 2 वर्ष दिये जाते हैं। औद्योगिक लाइसेंस-धारियों को परियोजनाओं को पूरा करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस जारी होने की तिथि से अधिकतम 4 वर्ष दिये जाते हैं। किन्तु दुस्साध्य मामलों से सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन की अवधि 4 वर्षों से अधिक भी बढ़ाई जा सकती है। अनुभव से जाना गया है कि किसी भी नए उपक्रम के चालू होने में लगभग 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। 1972 से 1974 के दौरान जारी किये गये आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वित की विभिन्न स्थितियों में हैं।

(ख) आशय पत्र जारी होने के पश्चात किसी भी उद्योग के अन्तिम रूप से चालू होने में लगने वाला विशिष्ट समय जहां तक सरकारी अनुमतियां देने हेतु उठाये जाने वाले कदमों का संबंध है, इस प्रकार हैं।

(1) पार्टी द्वारा आशय पत्र में दी गई शर्तों, यदि कोई हों तो, का स्वीकार करना।

(2) विदेशी सहयोग और पूंजीगत माल का आयात यदि कोई हो तो, की शर्तों के लिए अनुमति प्राप्त करना; और

(3) विहित शर्तों यदि कोई हों तो, के पूरी करने के उपरान्त आशय पत्र का औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करना।

(ग) 1972–73 और 1974 के केलेण्डर वर्ष में नये उपक्रम स्थापित करने के लिये आशय पत्रों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

उपक्रमों की स्थापना करने के लिए 1972-74 के दौरान जारी किए गए आशयपत्रों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	1972	1973	1974
1. आन्ध्र प्रदेश	22	18	48
2. अण्डमान और निकोबार	—	—	—
3. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
4. असम	6	5	7
5. बिहार	10	14	24
6. चण्डीगढ़	3	—	—
7. दादरा तथा नागर हवेली	—	—	2

राज्य	1972	1973	1974
8. दिल्ली	10	12	10
9. गुजरात	50	35	59
10. गोआ दमन और दीव	3	4	8
11. हरियाणा	55	35	64
12. हिमाचल प्रदेश	2	3	14
13. जम्मू तथा काश्मीर	2	3	5
14. कर्नाटक	28	31	41
15. केरल	13	12	15
16. एल०एम० तथा ए० द्वीपसमूह	—	—	—
17. मध्य प्रदेश	22	19	35
18. महाराष्ट्र	75	109	109
19. मनीपुर	—	—	2
20. मेघालय	1	1	3
21. मिजोरम	—	—	—
22. नागालैण्ड	1	1	—
23. उड़ीसा	2	4	13
24. पांडिचेरी	—	1	1
25. पंजाब	8	13	37
26. राजस्थान	15	12	39
27. तमिलनाडू	27	24	61
28. त्रिपुरा	—	1	1
29. उत्तर प्रदेश	94	64	93
30. प० बंगाल	23	28	66
31. राज्य जो शामिल नहीं किए गए	50	25	8
योग	522	473	758

भद्रक उड़ीसा में मुख्य डाकघर इमारत

1339. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भद्रक जिला बालासौर (उड़ीसा) में मुख्य डाकघर की विभागीय इमारत का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इमारत में दरारों के पड़ने तथा रिसने के कारण रुके हुए निर्माण कार्य को आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद इस समय इसे तत्काल पूरा किए जाने की आवश्यकता है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) अस्थायी तौर पर लगाये गये प्रतिबंध को हटा देने के बाद निर्माण कार्य हाथ में लिया जायेगा और इसे यथासंभव शीघ्र पूरा किया जाएगा ।

(ख) मौजूदा इमारत में विशेष मरम्मत का कार्य चल रहा है ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के पास निर्यात के लिए तथा अन्तर्देशीय क्रयादेश

1340. **श्री आर०एन० बर्मन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत प्रजनन उपकरणों के लिए परियोजित घरेलू आवश्यकताओं को पूरा न करने की स्थिति में होते हुए भी भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० निर्यात क्रयादेशों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो आगामी चार वर्षों में निर्यात के लिये कितने क्रयादेश प्राप्त हुए हैं और उस अवधि के दौरान देश में कितनी मांग होने का अनुमान है ; और

(ग) 15 दिसम्बर, 1974 तक देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल कितने क्रयादेश बाकी रहते हैं और इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विद्युत जनित्रण उपकरणों के लिए परियोजित घरेलू आवश्यकताओं को स्वयम् पूरा करने के लिए अपने आपको तैयार करने के साथ साथ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड निर्यात आर्डरों की तलाश कर रहा है और निर्यात आर्डर प्राप्त कर रहा है ।

(ख) जिन निर्यात आर्डरों को पूरा किया जा चुका हैं उनके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के पास इस समय 309.24 लाख रुपये के मूल्य के निर्यात आर्डर हैं । आगामी चार वर्षों में उन्हें और अधिक निर्यात आर्डर प्राप्त करने की आशा है । घरेलू आवश्यकताओं के संबंध में, पांचवीं योजना के मसौदे में कुल 16,555 मे०वा० की वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है जिसमें से 14,600 मे०वा० को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के साथ जोड़ा गया है ।

(ग) यद्यपि बी०एच०ई०एल० ने अब तक लगभग 6,000 मे०वा० के उपकरणों का संभरण/कार्यशाला परीक्षण पूरा कर लिया लेकिन 15-12-74 को घरेलू क्रयादेश जिन्हें बी० एच०ई०एल० ने पूरा कराना है जिनमें छठी योजना में चालू किए जाने वाले उपकरण भी शामिल हैं, लगभग 10,200 मे०वा० के हैं । इन क्रयादेशों को ग्राहकों के परामर्श से तैयार किए गए प्रावस्थाबद्ध डिलीवरी तालिका के अनुसार पूरा किया जाना है । कुल मिलाकर पांचवीं योजना अवधि में डिलीवरी के लिए आर्डरों के इस डिलीवरी तालिका के अनुसार पूरा किए जाने की आशा है ।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिए सुविधाओं की कमी

1341. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र को कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सुविधाओं के अभाव में लाइसेंस-धारी पश्चिम बंगाल में उद्योग स्थापित करने के मामले में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने बताया है कि बैंक सुविधाओं की कमी औद्योगिक विकास के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) लाइसेंसधारकों से इस प्रकार की विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं कि प० बंगाल में वे औद्योगिक एकक लगाने की कार्यवाही करने में वे असमर्थ हैं ।

(ग) तथा (घ) बैंकिंग की सुविधा के अभाव में प० बंगाल में औद्योगिक लाइसेंसों के उपयोग न किये जा सकने के बारे में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । परन्तु प० बंगाल तथा पूर्वी क्षेत्र में भी ऋण की उपलब्धता सहित बैंकिंग की सुविधाओं के प्रश्न पर विभिन्न स्तरों (फोरमों) पर विचार विमर्श हुआ है । प० बंगाल सहित पूर्वी क्षेत्र जैसे कम विकसित इलाकों में बैंकों द्वारा अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के प्रश्न पर बैंकों में विचार किया जा रहा ।

पश्चिम बंगाल में गांवों और कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता

1342. **श्री आर०एन० बर्मन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल ने केन्द्रीय सरकार को गांवों तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए 45 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि देने का अनुरोध किया था ;

(ख) क्या इस राशि का केवल एक तिहाई भाग ही अब तक दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो बाकी राशि कब तक दे दी जायेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए अपनी पांचवीं योजना के मसौदे में राज्य क्षेत्र में अस्थायी परिव्यय के लिए 45.20 करोड़ रुपये (अनुदान के रूप में नहीं) का सुझाव दिया था । इसमें से योजना आयोग 14.40 करोड़ रुपये के परिव्यये के लिए सहमत हो गया है । ये अस्थाई हैं और वार्षिक योजनाओं के आधार पर लागू किये जायेंगे और प्रत्येक वार्षिक योजना के लिए परिव्यय का निर्धारण वार्षिक स्रोतों की उपलब्धि के आधार पर किया जाता है ।

मिजोरम और नागालैण्ड के क्रियाकलापों में चीन का अन्तर्ग्रस्त होना

1343. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात के कुछ संकेत मिले हैं कि नागालैण्ड और मिजोरम के क्रिया कलापों में चीन अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस को निरुत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान । सरकार को पता है कि नागालैण्ड और मिजोरम में भूमिगत तत्वों का चीन से हथियारों तथा गोलाबारूद, प्रशिक्षण इत्यादि के रूप में सहायता प्राप्त करना जारी है । हमारी सीमाओं के आरपार भूमिगत गिरोहों की गतिविधि को रोकने के लिए हमारी सीमाओं पर और नागालैण्ड राज्य और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र के भीतर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

बाजार में बिक्री कम होने के कारण टेलीविजन निर्माण करने वाले एककों का बन्द होना

1344. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में बिक्री कम होने के कारण टेलीविजन निर्माण करने वाले बहुत से एकक बंद हो गये हैं ;

(ख) क्या टेलीविजन सेटों में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख पुर्जों का जो एक सरकारी कम्पनी द्वारा सप्लाई किये जाते हैं, मूल्य अत्यधिक होता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) टेलीविजन निर्माण करने वाले एककों के बंद होने के विषय में कोई सूचना सरकार के पास नहीं आयी है। फिर भी, सरकार को मालूम है कि वर्ष 1974 में टी०वी० सेटों का उत्पादन वर्ष 1973 के मुकाबले केवल कुछ ही ज्यादा था, और 1974 के दौरान उत्पादन की अर्थपूर्ण वृद्धि में कमी मुख्यत: टी०वी० पिक्चर ट्यूबों के अपर्याप्त उत्पादन और सप्लाई के कारण थी।

(ख) और (ग) पिक्चर ट्यूब जो टी०वी० सेट का एक मूल तत्व है। रक्षा उत्पाद विभाग के अधीन एक पूर्णत: केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र एकक, भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० द्वारा उत्पादित होती है तथा बाजार में लायी जाती है। पिक्चर ट्यूब के उच्च फुटकर मूल्य (संप्रति 565 रु०) का आंशिक कारण है आयातित नेग्लास बल्बों पर उद्ग्राहित अर्थपूर्ण सीमा शुल्क (175%)। सरकार ने भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० की क्षमता को दुगुना करने की मंजूरी दे दी है। (प्रतिवर्ष 1,00,000 नगों की मूल क्षमता से 2,00,000 नग), और 1,69,000 पिक्चर ट्यूबों की कुल क्षमता के लिए निजी क्षेत्र में चार अन्य पार्टियों को भी आशयपत्र प्रदान किये गये हैं। देश में सर्जित और बड़ी क्षमता तथा अभिवृद्धि प्रतियोगिता के फलस्वरूप मूल्य में कुछ कमी आ सकती है, जो केवल सीमान्तरीय प्रकार की होगी।

Cement Factory in Pali (Rajasthan)

1345. **Shri M.C Daga** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the names of persons who have applied for licences for setting up cement factories in Rajasthan indicating the location thereof ;

(b) whether a licence for establishing a cement factory in Pali (Rajasthan) has been applied for by anybody; and

(c) if so, the date thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya): (a) Applications from the following parties for grant of licence/ Letter of Intent, are under consideration of the Government.—

(i) Raymond Woollen Mills Ltd. Bombay	Modak (Distt. Kota)	4.00 lakh tonnes.
(ii) Mysore Cements Ltd.	Beawar (Distt. Ajmer)	5.00 lakh tonnes

(b) and (c) A letter of intent for setting up a cement plant at Pali (Rajasthan) for a capacity of 6.60 lakh tonnes was granted to the Associated Cement Companies Ltd. on the 17th August, 1973. The party has however, since decided to drop this scheme.

Imposition of Fines recommended by Central Vigilance Commission in their Ninth Report for certain I.A.S. and I.P.S Officers

1346. **Shri M.C. Daga :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Central Vigilance Commission in its Ninth Report has recommended that three I.A.S. and two I. P. S. officers should be heavily fined; if so, the reasons therefor ;

(b) whether these officers have been fined and if so, the amount of fine imposed on each of them and the charges against them ; and

(c) if they have not been fined so far, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : (a) There is no recommendation in the Ninth Report of the Central Vigilance Commission that three I.A.S. and two I.P.S. officers should be heavily fined, nor is there any provision in the departmental rules for imposition of fines on delinquent officers. The reference, apparently, is to para 23 of the Report in which it was stated that the officers against whom the Commission had recommended initiation of proceedings as for the imposition of a major penalty included, among others, three I.A.S. and two I.P.S. officers.

(b) & (c) The charges against these officers related to possession of disproportionate assets, showing favours in awarding dealerships and agencies and causing undue pecuniary advantages to certain firms and persons.

Major penalty proceedings intiated against one I.A.S. and one I.P.S. officers have not yet concluded. On the further advice of the Central Vigilance Commission, case against one I.A.S. officer was closed after this retirement, the question of initiating departmental proceedings against one I.A.S. officer has been deferred till the conclusion of criminal proceedings already pending against him and warning has been issued to one I.P.S. officer.

Telephone Arrears

1347. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether telephone arrears amounting to Rs. 3.17 lakhs pertaining to 1971-72 were written off because the concerned departmental files were not available ; and

(b) if so, the names of departments to whom those files belonged and the action taken against the persons responsible ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) Telephone revenue to the extent of Rs. 3.17 lakhs was written off during 1971-72 on account of non-availability of relevant departmental file.

(b) (i) The Units in whose jurisdiction, they were written off and the amount involved are furnished hereunder :

Name of Circle	Amount written-off (Rupees in thousands)
1. Delhi District	281.2
2 Calcutta District	6.0
3. Bombay District	6.8
4. Kanpur District ..	3.3
5. Rajasthan Circle	0.5
6. Punjab Circle ..	8.3
7. Maharashtra Circle ..	1.9
8. U.P. Circle	2.7
9. West Bengal Circle	0.5
10. Karnataka Circle	5.8
	317.0

(ii) Directions have been issued to the Heads of the concerned Circles/Districts to fix responsibility and to take suitable action in the matter.

भारत के समग्र राष्ट्रीय उत्पादन पर औद्योगिक क्षमता के उपयोग का प्रभाव

1348. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी**
श्री अनन्त राव पाटिल
श्री भीकिशन मोदी :

क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 दिसम्बर, 1974 को दिल्ली से प्रकाशित एक अंग्रेजी समाचार पत्र में उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री द्वारा दिये गये वकतव्य के सम्बन्ध में छपे इस समाचार की सरकार को जानकारी है कि अगर वर्तमान औद्योगिक क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जाये, तो भारत के समग्र राष्ट्रीय उत्पादन पांच गुना हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य का क्या आधार है और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इस अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिये अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री टी०ए० पाई): (क) और (ख) एक समाचार 21 दिसम्बर, 1974 के इकोनोमिक टाइम्स में प्रकाशित किया गया था जो उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री द्वारा 20 दिसम्बर, 1975 को भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ में दिये गये वक्तव्य से संबंधित था। देश में विद्यमान क्षमता का पूर्णतय उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मन्त्री महोदय ने बताया था कि बिजली, इस्पात, कोयला, उर्वरक और भारी इंजीनियरी उपकरण के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करने से जो अतिरिक्त उत्पादन होगा उससे उद्योगों को 800 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो सकेगी जिसका भारी बहुगुणीय प्रभाव होगा। इस बहुगुणीय प्रभाव का परिणाम यह होगा कि उत्पादन में 800 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि करीब पांच गुनी हो जाएगी।

(ग) विद्यमान क्षमता के उपयोग में कुछ प्रगति हुई है और बिजली, कोयला और इस्पात के प्रमुखज क्षेत्रों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1974 में सुधार देखे गये हैं। सरकार का, क्षमता के उपयोग को बढ़ाने सम्बन्धी उपाय को चलाते रहने का प्रयास है।

गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में सीमेंट कारखाने

1349. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 जनवरी, 1975 को सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में सीमेंट के कुल कितने कारखाने हैं; और

(ख) 1 जनवरी, 1975 को कारखानों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी थी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी०पी० मौर्य): (क) और (ख) जानकारी नीचे दी जा रही है :—

	सीमेंट संयंत्रों की संख्या	अधिष्ठापित क्षमता (10 लाख मी० टनों में)
निजी क्षेत्र	42	17.55
सरकारी क्षेत्र	9	2.31
योग	51	19.86

विदेशी मुद्रा पर स्कूटरों तथा मोटर कारों का आबंटन

1350. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के प्रत्येक महीने में भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा लाई गई अथवा विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा पर प्राथमिकता के आधार पर कुल कितने स्कूटरों तथा मोटर कारों का आवंटन किया गया ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज): (क) वर्ष 1974 के प्रत्येक महीने तथा 1975 के जनवरी महीने में विदेशी मुद्रा पर प्राथमिकता के आधार पर आवंटित कारों और स्कूटरों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	महीना	आवंटित कारों की कुल संख्या		आवंटित स्कूटरों की कुल संख्या	
		प्रीमियर प्रेसिडेंट	अम्बेसडर	बजाज	लम्ब्रेटा
1	2	3	4	5	6
1974	जनवरी	1	—	97	8
	फरवरी	10	3	290	10
	मार्च	393	15	153	12
	अप्रैल	5	—	230	4
	मई	45	7	835	12
	जून	41	3	711	6
	जुलाई	13	1	694	4
	अगस्त	25	2	1375	5
	सितम्बर	25	—	1788	5
	अक्तूबर	6	—	1360	—
	नवम्बर	14	—	895	—
	दिसम्बर	12	—	3444	7
	योग	590	31	11872	73
1975	जनवरी	17	—	2118	7

(ख) वर्ष 1974 तथा 1975 के जनवरी महीने में अर्जित न्यूनतम विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :—

1-1-1974 से 31-12-1974 तक अर्जित विदेशी मुद्रा	जनवरी, 1975 में अर्जित विदेशी मुद्रा
7.50 करोड़	1.11 करोड़

गोरखपुर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

1351. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार ने इमारत के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया है, यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) गोरखपुर में 2400 लाइनों का एक आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है और इसके उपस्कर की सप्लाई वर्ष 1975-76 में आरम्भ होगी ।

(ख) भूमि का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है । टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत के निर्माण का कार्य चल रहा है और मार्च, 1976 में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है ।

समस्तीपुर में बम विस्फोट

1352. **श्री नरसिंह नारायण पांडे**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समस्तीपुर के उस बम विस्फोट के सिलसिले में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके फलस्वरूप स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र की मृत्यु हो गई थी और अगर उन व्यक्तियों का किन्हीं राजनैतिक दलों अथवा मजदूर संघों से सम्बन्ध है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी): इस सिलसिले में अब तक 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । राजनैतिक दलों अथवा मजदूर संघों के साथ उनके सम्बन्ध का, यदि कोई है, सत्यापन किया जा रहा है ।

स्वीटजरलैंड के सहयोग से घड़ियां बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जाना

1353. **श्री एस०एन मिश्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीटजरलैंड की किसी फर्म ने हमारे देश में घड़ियां बनाने का एक कारखाना बनाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) क्या इस मामले को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी०पी० मौर्य): (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना का पुनः तैयार किया जाना

1354. **श्री प्रसन्नभाई मेहता**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियरी उद्योग संगठन (एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री) के दिसम्बर, 1974 में हुए दो दिवसीय सम्मेलन में सरकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा बनाई गई विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना को पुनः तैयार किये जाने का अनुरोध किया गया है यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ख) भारत सरकार का ध्यान 20-21 दिसम्बर, 1974 को हुए भारतीय इंजीनियरी उद्योग संगठन (एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री) के सम्मेलन तथा ए०आई०ई०आई० के अध्यक्ष द्वारा 10-2-75 को जारी किए गए तथा इसके 'सारांश एवं निष्कर्षों' की ओर दिलाया गया है जिनमें यह कहा गया है कि खाद्य, सिंचाई, बिजली तथा परिवार नियोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना में प्राथमिकताओं को पुन: समायोजित करने की आवश्यकता है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के प्रारूप को, जिसे 26 मार्च, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था सरकार, उद्योग और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं से लिए गए 1800 वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकों, अर्थशास्त्रियों आदि द्वारा तैयार किया गया था और उसमें प्राथमिकताएं निर्धारित की गई थीं ? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना के प्रारूप में प्राथमिकता के क्षेत्र—कृषि जिसमें फसलोत्तर प्रौद्योगिकी शामिल है, ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला प्रौद्योगिकी तथा प्राकृतिक साधनों का व्यापक मूल्यांकन आदि है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवार नियोजन पर समुचित बल दिया गया है । उपर्युक्त बातों को देखते हुए, इसे पुन: तैयार करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा रहा है, यद्यपि इसे निरंतर अद्यतन बनाना परिकल्पित है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव (उत्तर प्रदेश) में जाली औद्योगिक एककों का पंजीकरण रद्द किया जाना

1355. **श्री प्रसन्नभाई मेहता**
श्री पी०ए० स्वामीनाथन :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नाव में 22 जाली औद्योगिक एककों को, जिनका हाल में उत्तर प्रदेश के उद्योग निदेशक द्वारा पंजीकरण रद्द किया गया, दुर्लभ रसायनों के लिए गत तीन वर्षों में कई लाख रुपये के मूल्य के आयात लाइसेंस दिए गए थे;

(ख) क्या इन एककों को मशीनें खरीदने तथा इमारतें बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी गई थी ;

(ग) क्या जांच के पश्चात् इनमें से अधिकांश फर्मों को अस्तित्वधीन पाया गया; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई अथवा की जायेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०पी० शर्मा): (क) उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दो एककों को क्रमश: 8,000 रुपये और 5,000 रुपये का ऋण दिया गया था । इन ऋणों की उनके द्वारा वसूली की जा रही है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) 6 एककों की आयात करने की पात्रता, चार का इस्पात आवंटन और तीन की कोयला आवंटन की पात्रता उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय द्वारा समाप्त कर दी गई है ।

गुजरात में गोली चलने से मरे लोग

1356. **श्री पी० एम० मेहता :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में नव निर्माण समिति द्वारा फिर से आरम्भ किये गये आन्दोलन से राज्य में गोली चलने की घटनाएं बढ़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1974 और जनवरी तथा फरवरी, 1975 में राज्य में गोली चलने की कुल कितनी घटनाएं हुई; और

(ग) इन तीन महीनों में कितने लोग मरे और कितने गिरफ्तार किये गये ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में नव निर्माण समिति द्वारा कोई नया आन्दोलन शुरू नहीं किया गया है तथा दिसम्बर, 1974 से आगे इस सिलसिले में राज्य में कोई गोलीबारी अथवा गिरफ्तारी नहीं हुई है।

नेशनल इंस्ट्रुमेंट लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा अर्जित लाभ

1357. **श्री टुना उरांव**
श्री शंकर नारायण सिंह देव
श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इंस्ट्रुमेंट लिमिटेड, कलकत्ता को गत तीन वर्षों में कितना लाभ हुआ; और

(ख) इन वर्षों में इस एकक के मदवार उत्पादन के बारे में तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी०पी० मौर्य): (क) नेशनल इन्स्ट्रुमेन्टस लि० कलकत्ता द्वारा पिछले तीन वर्षों में अर्जित लाभ-हानि का विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	लाभ/हानि (लाख रुपयों में)
1971–72	(—) 54.15
1972–73	(—) 41.66
1973–74	(+) 17.05

(ख) नेशनल इन्स्ट्रुमेन्टस लि० कलकत्ता के पिछले तीन वर्षों के वस्तुवार उत्पादन के आंकड़े सभा पटल पर रख दिए गए हैं। **[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 9021/75]**

Alternative to Police Firing to check Disturbances

1358 **Shri Jambuwant Dhote :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are resorting to more and more police firing in order to tackle agitations, demonstrations and gatherings in different parts of the country;

(b) whether in many countries of the world, police firing to deal with agitating crowds is prohibited and for this purpose they use special type of rubber bullets or resort to throwing of water at fast speed; and

(c) whether Government propose to evolve new principles and policies after considering this matter afresh keeping in view the democratics system of Government and if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H Mohsin) : (a) No, Sir.

(b) It is a fact that rubber bullets etc. are in use in some countries. The Government, however, have no information that police firing to deal with violently agitating crowds has been prohibited in any country.

(c) The matter as to how best to carry out riot control operations is under constant review.

दिल्ली के निकट के कस्बों को स्थानीय काल

1359. **श्री हरि सिंह** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकटवर्ती कस्बों अर्थात गाजियाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ को दिल्ली के स्थानीय काल क्षेत्र से बाहर करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) और (ख) दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई को बहु एक्सचेंज प्रणालियों के लिए इलाकों को ठीक प्रकार से निर्धारित करने के एक प्रस्ताव की जांच विभिन्न तकनीकी और दूसरे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में राष्ट्रीयकरण से पूर्व तथा पश्चात् कोयले का उत्पादन

1360. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के उत्पादन में संतोषप्रद वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकरण से पूर्व कितना उत्पादन था और राष्ट्रीयकरण के पश्चात् अब तक कितना उत्पादन है; और

(ग) इस असफलता के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) तथा (ख) भारत कोकिंग कोल लि० की खानों में राष्ट्रीयकरण के बाद उत्पादन में कुछ कमी हुई है। यह बात राष्ट्रीयकरण से पूर्व तथा बाद (राष्ट्रीयकरण की तिथि) 1-5-1972 के निम्नलिखित उत्पादन आंकड़ों से स्पष्ट है :—

(हजार टनों में)

वर्ष	कोककर	प्रकोककर	जोड़
1971–72	10349	6962	17311
1972–73	0107	6947	17054
1973–74	9284	7054	16338
1974–75 (जनवरी, 75 तक)	8019	6241	14260

(ग) उत्पादन में कमी मुख्य रूप से इन कारणों से हुई---अधिग्रहण के शीघ्र बाद अस्त-व्यस्त दशाएं, 1973 में भारी वर्षा के कारण खानों में पानी भर जाना, दामोदर नदी में बाढ़ के कारण बालू की कमी, बिजली सप्लाई में कमी, विस्फोटकों की कमी, अपर्याप्त परिवहन आदि ।

निवेशित पूंजी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पांचवी योजना की नीति में परिवर्तन

1361. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री पी० गंगादेव
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रारूप की नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा रहा है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) अब तक निवेशित पूंजी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पांचवीं योजना में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) आन्तरिक और बाह्य विभिन्न गतिविधियों के बावजूद भी पांचवीं योजना के प्रारूप में उल्लिखित मूल उद्देश्य और नीति सम्बन्धी ढांचा अभी भी बरकरार है । अतः पांचवीं योजना के प्रारूप में नीति सम्बन्धी कोई खास परिवर्तन करने आवश्यक नहीं समझे गये हैं । केवल इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कार्यक्रमों के अनुक्रम व संरचना में मामूली समायोजन किया गया है ।

(ख) पांचवीं योजना प्रारूप में उल्लिखित नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है---विद्यमान क्षमताओं और पहले से किए गए पूंजी-निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करना । इस दिशा में की जा रही प्रमुख कार्यवाहियां निम्न प्रकार से हैं :---

(1) महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, बिजली, सिंचाई आदि की परियोजनाओं और कार्यक्रमों, विशेषतः वे जो अग्रिम चरण में हैं और जो संभवतः अगले दो वर्षों में पूरी हो जाएगी, के लिए वार्षिक योजना 1974-75 और 1975-76 में योजना निधियों के आवंटन को उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

(2) खास-खास बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए समेकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को तेज किया जा रहा है ताकि पहले से निर्मित सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके ।

(3) उन बाधाओं (जैसे बिजली, परिवहन, कच्चा माल) को दूर करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो विद्यमान क्षमताओं, विशेषतः महत्वपूर्ण उद्योगों में जैसे इस्पात, कोयला, उर्वरक, सीमेन्ट आदि, के पूर्ण उपयोग में रुकावट डाल रहे हैं । फालतू पुर्जों व उपकरणों की आयात नीति और क्षमताओं के विविधीकरण में ढील बरती गई है ।

(4) ऋण नीति को नई दिशा प्रदान की जा रही है ताकि उत्पादक प्रयोजनों, विशेषत: महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण सुलभ हो सके ।

(5) खास-खास परियोजनाओं की प्रगति के बारे में नियमित जानकारी इस दृष्टि से प्राप्त की जा रही है, कि उनको तेजी से क्रियान्वित करने के लिए कतिपय उपचार सम्बन्धी उपायों का सुझाव दिया जा सके ।

विद्युत उत्पादन संयंत्रों और विद्युत उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की नई दिल्ली में दिसम्बर, 1974 में हुई बैठक

1362. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री पी० गंगादेव
श्री श्रीकिशन मोदी
श्री पुरूषोतम काकोडकर :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन संयंत्रों और विद्युत उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की नई दिल्ली में दिसम्बर, 1974 के अन्तिम सप्ताह में उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत उत्पादन के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार किया गया था;

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्डों और भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स के प्रतिनिधियों ने भी उक्त बैठक में भाग लिया था; और

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य निर्णय लिये गये ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (घ) जी, हां । नई देशी यूनिटों को चालू करने में पेश आई तकनीकी समस्याओं और दोषों को दूर करने के लिए एक समान प्रक्रिया को विकसित करने तथा दोनों विनिर्माताओं द्वारा सप्लाई किए गए विभिन्न यूनिटों के परीक्षण के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए 21 दिसम्बर, 1974 को नई दिल्ली में भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लिमिटेड और इन्स्ट्रुमेंटेशन लि० कोटा के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी । इस बैठक में मैसर्ज भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०, मैसर्ज इन्स्ट्रुमेंटेशन लि० कोटा, और उन राज्य बिजली बोर्डों जिनमें उपस्कर स्थापित किए गए हैं, के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । ऊर्जा मन्त्री ने बैठक में थोड़े समय के लिए ही भाग लिया । यह निर्णय लिया गया कि मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० छोटे कार्यकारी दल स्थापित करेगा, जो उन विभिन्न विद्युत केन्द्रों, जिनमें उनके उपस्कर प्रतिष्ठापित किए गए हैं, के कार्य निष्पादन संबंधी परीक्षण करेंगे, परियोजना प्राधिकारियों को पेश आने वाली समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए विद्युत केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे और उनके प्रचालनाधीन अथवा चालू किए जा रहे यूनिटों के प्रचालन संबंधी अनुभव का प्रचार करने के लिए एक तकनीकी पत्रिका प्रकाशित करेंगे ।

औद्योगिक विकास नीति समूह का गठन करना

1363. **श्री डी०डी० देसाई**
श्री अनादि चरण दास
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री पी० गंगा देव
श्री श्रीकिशन मोदी
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक विकास नीति समूह गठित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ग) क्या समूह औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भी अपने साथ संबद्ध करेगा; और

(घ) समिति के अन्य कार्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में मन्त्री (श्री टी०ए० पाई): (क) से (घ) सरकार ने उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में अर्थ-व्यवस्था की बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ावा देने और उन्नति शील बनाने हेतु अर्थोपायों का सुझाव देने के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के एक औद्योगिक नीति दल की स्थापना की है ।

सरकार की औद्योगिक नीति के निरन्तर कार्यान्वयन की जांच करने की जिम्मेदारी इस समूह की है जिससे सामाजिक आर्थिक प्राथमिकता के अनुसार देश का औद्योगिक विकास हो सके और सरकारी तंत्र औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की दर बढ़ाने की तात्कालिक आवश्यकता समुचित रूप से पूरी कर सके ।

समाचार पत्रों द्वारा अखबारी कागज के उपयोग पर लगे प्रतिबन्ध में छूट

1364. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री पी० गंगादेव
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों द्वारा अखबारी कागज के उपयोग पर लगे प्रतिबन्ध में कोई छूट देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी छूट देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बारे में रूप-रेखा तैयार कर ली गई है ;

(घ) क्या छोटे समाचार पत्र अपने अखबारी कागज के कोटे की डिलीवरी नहीं लेते; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) से (ग) अखबारी कागज की सप्लाई स्थिति, जिस पर बराबर पुनर्विलोकन किया जाता है, को देखते हुए, दैनिक समाचार पत्रों की 7 प्रतिशत तक की हकदारी, जो उनको छपाई कागज में दी जानी थी, अब अखबारी कागज में दी जायेगी । समाचार पत्रों को 1974-75 की उनकी हकदारी के अलावा, परन्तु 1972-73

की उनकी हकदारी के अन्दर अन्दर; नेपा के छोटे बड़े आकार के अखबारी कागज के आवंटन की भी व्यवस्था की गई है ।

(घ) तथा (ङ) जी, नहीं । समाचारपत्र अखबारी कागज का कोटा उठा रहे हैं ।

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के 'सेल' द्वारा किए गए कार्यों की पुनरीक्षा

1365. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए योजना आयोग में किसी 'सेल' का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका गठन किस तिथि को किया गया था; और

(ग) इस सेल द्वारा किए गए कार्यों की पुनरीक्षा तथा यह सेल (1) रेल लाइनों, सड़कों तथा अन्य संचार साधनों की व्यवस्था के लिए आवंटनों और (2) पहाड़ी क्षेत्रों के कच्चे माल पर आधारित नये उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्रों की समुचित विकासात्मक आयोजना के कार्य में कहां तक लाभप्रद सिद्ध हुआ है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी, हां ।

(ख) अक्तूबर, 1972 ।

(ग) जब कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी मुख्त: राज्य सरकारों पर है, फिर भी पर्वतीय क्षेत्रों का 'सेल' पर्वतीय क्षेत्रों की संसाधन क्षमता के आधार पर उनके विकास के लिए नीति निर्धारण सम्बन्धी कार्यप्रणाली बनाने तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए समेकित विकास योजनायें (साथ में सड़कों, संचार और उद्योगों को शामिल करते हुए) तैयार करने में राज्य सरकारों की मदद कर रहा है । सम्बन्धित मन्त्रालयों और योजना आयोग के प्रभागों के परामर्श से यह 'सेल' उत्तर पूर्वी परिषद और पश्चिमी घाट क्षेत्र के योजना प्रस्तावों की जांच के लिए भी उत्तरदायी है ।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रतिनिधि

1365. **श्री एम० कतामुतु**

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने वाले विदेशी प्रतिनिधि विभिन्न कारणों से असन्तुष्ट रहे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धमवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय फिल्म नीति

1367. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे सिने दर्शकों और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समुचित शैक्षणिक, उद्देश्यपूर्ण, खेल कूद और कार्टून फिल्मों के उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सरकार ने फिल्म निर्माताओं से अपील करना और उसे सुझाव देना शुरू कर दिया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार ने इस बारे में कोई शुरुआत की है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय फिल्म नीति बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ख) भारत में फिल्म उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में है और सरकार का फिल्मों के निर्माण पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

(ग) देश की वाणिज्यिक वित्तीय, आयात और निर्यात आवश्यकताओं और बाद में उद्योग के प्रदर्शन पहलुओं की देखभाल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में एक बहुमुखी, बहुकार्य करने वाली निकाय अर्थात राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम स्थापित करने का निर्णय किया गया है। यह फिल्म उद्योग की विकासात्मक आवश्यकताओं की भी देख-रेख करेगा।

वाणिज्यिक प्रसारणों से आय

1368. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक प्रसारणों से वर्ष प्रति वर्ष आय बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 और 1974 में क्या क्या आय हुई।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) कुल जो आय हुई वह इस प्रकार थी :—

1972-73	लगभग 4 करोड़ 68 लाख रुपये
1973-74	लगभग 4 करोड़ 86 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश में छोटे समाचार पत्रों में लघु उद्योग घोषित करना

1369 **श्री राजदेव सिंह :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय कर लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के 20,000 या इससे कम परिचालन संख्या वाले सभी छोटे समाचारपत्रों को शीघ्र ही लघु उद्योग घोषित कर दिया जायेगा और उन्हें मुद्रणालय लगाने हेतु ऋण सहित वित्तीय सहायता दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नीति केवल उत्तर प्रदेश के लिए है अथवा अन्य राज्यों के लिए भी ;

(ग) क्या अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था पहले ही से लागू है और उत्तर प्रदेश में यह अब लागू होगी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०पी० शर्मा): (क) इस मन्त्रालय को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

Increase in Allocations for Development of Ladakh

1370. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minitser of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Starred question No. 528 on 18th December, 1974 regarding development of Ladakh and state :

(a) whether Government propose to increase allocations in various fields for the Ladakh Five Year Plan; if so, the amounts thereof; and

(b) the progress so far made in implementation of the schemes undertaken under that Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) An outlay of Rs. 18 crores has been provisionally agreed to for the Fifth Five Year Plan of Ladakh. This will be finalised alongwith the State's Fifth Five Year Plan.

(b) As against the current year's approved outlay of Rs.2.07crores for Ladakh the State Government expects an expenditure of Rs. 2.09 crores during 1974-75.

अन्तः राज्यीय और अन्तः प्रदेशीय विद्युत सम्पर्कों की योजनाओं को कार्यान्वित करना

1371. **श्री के० मालन्ना :** क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तः राज्यीय एवं अन्तः प्रदेशीय विद्युत सप्लाई स्थापित करने की योजनायें केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है और राज्यों को धनराशि उनकी योजना-सीमा से बाहर उपलब्ध की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

उर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों संघ-राज्य क्षेत्रों को अन्तर्राज्यीय/अन्तःक्षेत्रीय सम्पर्कों के निर्माण के लिए उनकी योजना सीमा से बाहर शत-प्रतिशत ऋण सहायता दीजाती है । इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से अब तक 133/220 के० वी० के आठ अन्तर्राज्यीय/अन्त : क्षेत्रीय सम्पर्क पहले ही पूर्ण किए जा चुके है और इस समय 23 अन्तर्राज्यीय/अन्तः क्षेत्रीय सम्पर्क निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 28.30 करोड़ रुपये की राशि के ऋण दिए गए थे । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

Visit by Minister of Energy to Coal Mine areas during January 1975

1372. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether he visited various coal mine areas during January, 1975 and there various Trade Unions and individuals submitted some memoranda regarding the problems of the coal mine areas ;

(b) if so, the gist of the memoranda; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir. ?

(b) The memoranda, *inter alia*, touched the following issues :

(i) Improvement in the facilities and amenities available to workers .

(ii) Uniform promotion policy.

(iii) Supply of adequate materials for increasing production.

(iv) Setting up of Committees at various levels for exercising vigilance.

(v) Diverse aspects of recruitment policy.

(vi) Repair of roads in the coalfields

(vii) Demurrage paid to railways.

(viii) Contract system.

(ix) Reopening of closed mines.

(x) Incentive schemes.

(c) Appropriate action will be taken, wherever necessary.

इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट प्रोमोशन कारपोरेशन को बंद करना

1373. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट प्रोमोशन कारपोरेशन को बन्द करके एक ऐसा नया निगम बनाने के लिए इस बीच कार्यवाही की गई है जो अन्य बातों के साथ-साथ चलचित्रों के निर्यात संवर्धन पर भी ध्यान देगा ; और

(ख) यदि हां, तो नये निगम की, यदि वह बना दिया गया है तो, रचना और कृत्यों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम बनाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं जो फिल्मों के निर्यात का काम हाथ लेगा। तथापि, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम को बंद करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

(ख) नये निगम का अभी तक गठन नहीं हुआ हैं। उम्मीद है कि इसका गठन मार्च, 1975 के अन्त तक हो जायेगा। यह चलचित्रों (एक्सपोज्ड), उपकरणों और कच्ची फिल्मों के आयात, निर्यात और वितरण; फिल्मों के प्रदर्शन और फिल्म उद्योग में अनुसंधान और उद्योग के विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा। नये निकाय की रचना का यथासमय फैसला किया जायेगा।

राजस्थान विद्युत प्रणाली को भाखड़ा के समानान्तर बनाने संबंधी प्रस्ताव

1374. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी**
डा० कर्णी सिंह :

क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान विद्युत प्रणाली को भाखड़ा के समानान्तर बनाने के केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव का मध्य प्रदेश और राजस्थान के चम्बल सिंचाई तथा बिजली नियंत्रण बोर्ड ने विरोध किया हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने उक्त प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया है कि इंजीनियरों और अन्य विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार विद्युत प्रणालियों का समानान्तर किया जाना तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है, क्योंकि राजस्थान में पनबिजली, ताप बिजली और परमाणु बिजली की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जबकि राज्य सरकारों के समानान्तर प्रचालनों की तकनीकी व्यवहार्यता के बारे में अपने-अपने अलग विचार थे, भारत सरकार के विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोनों प्रणालियों को समानान्तर प्रचालन किया जा सकता है । 27 जनवरी, 1975 को प्रणालियों का समानान्तर प्रचालन प्रारम्भ किया गया, और अब तक उस समानान्तर प्रचालन में कोई तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न नहीं हुई हैं।

अफ्रीकी-एशियाई चलचित्र समारोह का आयोजन

1375. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अफ्रीकी-एशियाई देशों में बने चलचित्रों का समारोह करने को वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा समारोह कब आयोजित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) समारोह स्रोतों के उपलब्ध होने पर आयोजित किया जायेगा।

देश म 'बन्द'

1376. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में देश में राज्यवार कितने-कितने 'बन्द' आयोजित किये गये;

(ख) क्या सरकार को भी कोई हानि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो वह किस सीमा तक हुई है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1-8-74 से 31-1-75 तक की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में 2 बन्द, कर्नाटक में 18, त्रिपुरा में 2, दिल्ली में 2 तथा अण्डमान व निकोबार और गोवा, दमन व दीव में एक-एक बन्द हुए थे। हरियाणा, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल की सरकारों तथा चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने संबद्ध अवधि के दौरान किसी बन्द की सूचना नहीं दी है। अन्य राज्य सरकारों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) तथा (ग) कर्नाटक सरकार ने बन्दों के परिणाम-स्वरूप 5050 रुपये क्षति होने की सूचना दी है। दिल्ली प्रशासन ने बन्द के दौरान 10,925 रुपये की क्षति होने की सूचना दी है। आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, अण्डमान व निकोबार और गोवा, दमण व दीव में बन्दों से कोई क्षति नहीं हुई। असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है

वर्ष 1974-75 में बिहार में गांवों का विद्युतीकरण

1377. **श्री एन० ई० होरो**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वर्ष 1974-75 के लिए बिहार राज्य को कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ख) राज्य के प्रत्येक जिले में कितने गांवों में बिजली लगाई गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 1974-75 के दौरान बिहार राज्य बिजली बोर्ड को अब तक 19.02 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है ।

(ख) 31-3-1974 को बिहार में विद्युतीकृत गांवों के जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9022/75]**

बिजली की कमी के कारण हरियाणा म उद्योगों को हानि

1378. **चौधरी राम प्रकाश**
श्री भान सिंह भोरा :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1973-74 में बिजली की कमी के कारण हरियाणा के औद्योगिक उत्पादन को हुई हानि का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और

(ग) इस संबंधी में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) हरियाणा सरकार द्वारा जुलाई से दिसम्बर, 1974 की अवधि में बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन की आंकी गई हानि करीब 147.75 करोड़ रुपये की है।

(ग) किए गए अभ्युपाय निम्न लिखित हैं :—

(1) 60 मेगावाट की फरीदाबाद विस्तार परियोजना के सम्बन्ध में जो 22 दिसम्बर, 1974 को चालू की गई सभी उपकरणों के सम्भरण कर्त्ता मै० बी० एच० ई० एल० को एकक द्वारा महसूस की जा रही प्रारम्भिक कठिनाइयों को दूर करने तथा इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कहा गया है कि एकक अपनी निर्धारित क्षमता का नियमित आधार पर शीघ्र उत्पादन करने में समर्थ रहे ।

(2) फरीदाबाद विस्तार परियोजना के अधीन 60 मेगावाट क्षमता का दूसरा एकक शीघ्र ही चालू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

(3) बदरपुर थरमल पावर स्टशन पर 100 मेगावाट का तीसरा एकक भी शीघ्र चालू करने के लिए कार्य चल रहा है।

(4) हाल ही में आर०ए०पी०पी० न्यूक्लिअर पावर स्टेशन को भी उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड के राजस्थान सिस्टम के समानान्तर करके उत्तरी क्षेतीय ग्रिड में ले लिया गया है। अलग-अलग आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार 50/60 मेगावाट तक बिजली पंजाब और हरियाणा राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही है।

नेपा मिल्स का कार्यकरण

1379. **श्री मधु लिमये** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपा मिल्स के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या मिल्स का कार्यकरण तथा उत्पादित अखबारी कागज की किस्म और सप्लाई असंतोषजनक है; और

(ग) यदि हां, तो कार्यकरण में सुधार करने तथा शिकायतों के कारण को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी०पी० मौर्य): (क) अखबारी कागज की क्वालिटी तथा नेपा मिल के कार्यकरण के कुछ अन्य पहलुओं के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) नेपा मिल के अखबारी कागज की खराब क्वालिटी कुछ तो उपलब्ध कच्चे माल की क्वालिटी तथा कुछ बिजली की सप्लाई में रुकावट आने के कारण हुई है। नेपा मिल में अखबारी कागज का उत्पादन पर्याप्त रूप से बढ़ा है। मिल का कार्य सामान्य रूप से संतोषजनक रहा है और मिल के अखबारी कागज की पूर्ति अखबारी कागज के पंजीयक द्वारा किए गए आवंटनों के अनुसार रही है।

(ग) मिलों के कार्य में सुधार करने के लिए सतत प्रयत्न किए जा रहे हैं। नेपा मिल्स से नान-स्टैन्डर्ड साईज के अखबारी कागज की मांग करने के कारण जिनकी आवश्यकताओं को नेपा मिल्ज ने पूरा नहीं किया था अखबारों की शिकायतों को दूर करने के विचार से अखबारी कागज के आवंटन की प्रणाली को सुप्रवाही बनाया जा रहा है।

केरल में आदिम जाति ब्लाक खोले जाना

1380. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय कितने आदिम जाति ब्लाक हैं ;

(ख) क्या केरल में और अधिक आदिम जाति ब्लाक खोलने के लिए केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) केरल में एक आदिवासी विकास खण्ड है अर्थात अट्टापड़ी आदिवासी विकास खण्ड।

(ख) और (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए एक उप-योजना बनाई जा रही है। जनवरी, 1975 में योजना आयोग ने केरल की उपयोजना पर विचार-विमर्श किया था और राज्य सरकार से उसे संशोधित करने के लिए अनुरोध किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष से आदिवासी विकास खण्ड का वर्तमान ढांचा समाप्त हो जाएगा और उपयोजना क्षेत्रों का समाहित करने के लिए एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं बनाई जाएगी। राज्य सरकार से इन क्षेत्रों के लिए एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

डाक तार विभाग में ओवरसियरों द्वारा की गई मांगें।

1381. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान डाक-तार विभाग में क्रैश तथा मेल ओवरसियरों द्वारा दैनिक भत्ता दिये जाने के बारे में की गई मांगों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) तीसरे वेतन आयोग ने इस मांग पर विचार किया था । आयोग ने दैनिक भत्ता मंजूर करने की सिफारिश नहीं की । तथापि इस श्रेणी के कर्मचारी सड़क के जरिए जो यात्रा करते हैं उन्हें उसके वास्तविक परिवहन चार्ज की प्रतिपूर्ति की मंजूरी दे दी जाती है । जो यात्रा रेलवे स्टीमर से करते हैं, उसके लिए उन्हें माइलेज भत्ता दिया जाता है । वे रात्री विश्राम भत्ता पाने के भी अधिकारी हैं ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधीन कुसुन्दा कोयला खानों में कदाचार

1382. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या उन का ध्यान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधीन कुसुन्दा कोयला खानों में विद्यमान कदाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कदाचारों में जिनका हाथ है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अगस्त, 1974 में बिहार कोलरी कामगार यूनियन ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधीन कुसुन्दा कोयला खानों में कुछ कदाचार के आरोप लगाए थे । मामले की जांच की गई और यह पाया गया कि आरोप सिद्ध नहीं हो सकते । दिसम्बर, 1974 में कुछ अन्य आरोप भी कुसुन्दा कोयला खानों के कुछ कामगारों द्वारा लगाए गए, जिनकी जांच की जा रही है ।

पटना में जे०पी० के जलूस पर बम फेंकने के सम्बन्ध में रामेश्वर नाथ याड से पूछताछ किया जाना

1383. **श्री मधु दंडवते** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेंसी—अनुसंधान तथा विश्लेषण विंग का रामेश्वर नाथ याड द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है ;

(ख) क्या रामेश्वरनाथ याड पटना में 'इन्दिरा ब्रिगेड' का संगठन करते रहे हैं; और

(ग) क्या इन्दिरा ब्रिगेड के सदस्यों द्वारा 19 नवम्बर, 1974 में पटना में जे०पी० के जलूस पर कथित बम फेंकने के संबंध में जांच के सिलसिले में हाल में पटना में रामेश्वर नाथ याड से पूछताछ की गयी थी ?

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (ग) प्रश्न में सम्भवत: मंत्रिमंडल कार्य-विभाग में सचिव श्री आर०एन० काव का उल्लेख है । इन्दिरा ब्रिगेड से उनका किसी भी तरह का संबंध नहीं है और पटना में श्री जय प्रकाश नारायण के जलूस पर कथित बम फेंकने के संबंध में उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है ।

तरुण भारत, बेलगाम दैनिक के प्रतिनिधि को मान्यता दिये जाने के बारे में निलम्बित पड़ा आवेदन-पत्र

1384. **श्री मधु दंडवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तरुण भारत बलगाम (दैनिक) के प्रतिनिधि का एक आवेदन-पत्र केन्द्रीय प्रैस प्रत्यायन (सैन्ट्रल प्रैस एक्रीडिटेशन) द्वारा मान्यता दिये जाने के लिए एक वर्ष से भी अधिक समय से समिति के समक्ष विचाराधीन पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन साप्ताहिक पत्रों पथा दैनिक पत्रों को प्रत्यय पत्र दिये गए हैं जो कि नियमों के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं तथा उन की पत्रिकायें कौन सी हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं । "तरुण भारत" बेलगाव के सम्पादक श्री आर०सी० प्रधान को उनके संवाददाता के रूप में प्रत्यायित करने के लिए प्रार्थना जो मार्च, 1973 में प्राप्त हुई थी, पर शुरू में केन्द्रीय प्रैस प्रत्यायन समिति ने दिसम्बर, 1973 को अपनी बैठक में सिफारिश नहीं की थी और यह बात संपादक को बता दी गई थी । बाद में समिति ने दिसम्बर, 1974 को अपनी बैठक में, (1) 'तरुण भारत', बेलगाव, (2) 'जनता', बम्बई तथा (3) 'साधना', पूना की ओर से संयुक्त रूप से श्री प्रधान के प्रत्यायन के मामले पर विचार किया और संबंधित संपादकों की औपचारिक प्रार्थना, जो अभी प्राप्त होनी है, मिलने पर संयुक्त रूप से पहले दो पत्रों के लिए प्रत्यायन की सिफारिश की थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । प्रत्यायन-पत्र केन्द्रीय प्रैस प्रत्यायन समिति, जो कोई भी सिफारिश करने से पूर्व प्रत्यायन संबंधी नियमों तथा परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवेदन-पत्रों की जांच करती है, की सिफारिश पर दिया जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर प्रदेश में ईसाई धर्म में परिवर्तन

1385. **श्री मधु दंडवते** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक भूतपूर्व अधिकारी के नेतृत्व में एक संगठन सारे पूर्वोत्तर प्रदेश में सक्रिय है और उस के द्वारा गैर-ईसाई जनजातीय व्यक्तियों को ईसाई बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) नार्थ बैंक बेप्टिस्ट क्रिश्चियन एसोसियेशन नामक एक संगठन जिसका मुख्यालय दारंग जिला (असम) में है और जिसके साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक भूतपूर्व अधिकारी का संबंध है, असम के कुछ जिलों में और उसके आसपास मिशनरी कार्य करता हुआ ध्यान में आया है ।

(ग) जब कभी कानून का उल्लंघन करने वाली कोई गतिविधि ध्यान में आती है तो उचित कार्यवाही की जाती है ।

मैसर्स मारुति लिमिटेड को छोटी कार के लिए लाइसेंस जारी करना

1386. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड, हरियाणा को जारी किए गए 'आशय पत्र' में यह शर्त है कि कम्पनी की फैक्टरी में बनाई जाने वाली छोटी कार शत-प्रतिशत स्वदेशी होगी और उसके लिए सारी मशीनरी तथा उपकरण स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त किये जाने हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वी०आर०डी०ई०, अहमदाबाद को भेजा गया 'मारुतिकार' का नमूना सरकार द्वारा मंजूर किया गया था और मारुति लि० को उसके निर्माण के लिए लाइसेंस जारी किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह आरोप लगाया गया है कि जो कार अहमदाबाद भेजी गयी थी और अभी भी वहीं पर है, उसमें पश्चिम जर्मनी से आयात किया गया इंजन लगा है ;

(घ) क्या यह भी आरोप लगाया गया है कि मैसर्स मारुति टेक्नीकल सर्विसेज लिमिटेड में काम कर रहे एक विदेशी तकनीशियन, श्री डब्ल्यू० एच० एफ० मुलर उक्त आयातित इंजन वायुयान द्वारा लाये थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) गाड़ी अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान द्वारा आद्यरूप के स्वीकृत किए जाने पर लाइसेंस दिया गया था ।

(ग) इस मंत्रालय को यह नहीं मालूम है कि आद्यरूप जिसे परीक्षण के लिये गाड़ी अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान में भेजा गया था उसमें आयातित इंजन लगा हुआ था । निर्माता ने यह निश्चय पूर्वक कहा है कि आद्यरूप में लगाये गये सभी हिस्से पुर्जे देशी हैं ।

(घ) और (ङ) मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि आद्य रूप में लगे इंजन का उक्त ढंग से आयात किया गया था जैसा कि आरोप लगाया गया है ।

औद्योगिक लाइसेंस नीति में परिवर्तन

1387. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंस नीति में आमूल परिवर्तन करने हेतु सरकार ने कोई प्रस्ताव तैयार किया है ;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव के अनुसार 'क्षमता निर्धारण' का सिद्धांत छोड़ना पड़ेगा और लाइसेंसों में क्षमता सीमा नहीं होगी ।

(ग) उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या वे इस बात से सहमत हैं कि उक्त प्रस्ताव से, यदि क्रियान्वित किया गया तो, अधिक बड़े तथा बड़े व्यापार गृहों में स्थिति में और अधिक सुदृढ़ता आयेगी ;

(ङ) क्या वे इस बात से भी सहमत हैं कि उक्त प्रस्ताव के, यदि क्रियान्वित किया गया तो, हजारों छोटे उद्यमकर्ताओं का नाश हो जाएगा; और

(च) यदि (घ) और (ङ) का उत्तर नकारात्मक हो तो, प्रस्ताव के समर्थन में उनके तर्क क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति में कोई आमूल परिवर्तन करने का सरकार की औद्योगिक नीति 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प निदर्शित होती है ।

(ख) और (ग) क्षमता निर्धारण को छोड़ देने की कोई भी विचार न हो कर अपितु उसे केवल युक्ति युक्त बनाना, चीनी और सूती वस्त्र जैसे उद्योगों में पहले से लागू धारणा—निविष्टि और मशीनों की क्षमता के रूप में जहां कहीं संभव हो सके क्षमता के प्रतिमान निश्चित करने की धारणा का विस्तार करना है जिससे लाइसेंस प्राप्त क्षमता को और अधिक स्पष्ट किया जा सके तथा इन्हीं उपकरणों से उत्पादिता बढ़ाकर अधिक उत्पादन करने की संभावना हो सके । अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं के निर्माण में और अधिक लोहा लाने उदाहरणार्थ औद्योगिक मशीनरी और मशीनी औजार उद्योग की लाइसेंस प्राप्त क्षमता में विविधीकरण करने का भी विचार है ताकि मशीनरी निर्माण क्षमता का पूर्ण सीमा तक उपयोग हो सके और किसी विशिष्ट उत्पाद की मांग में अस्थायी रूप से गिरावट आने से उपकरण संबंधी उन अन्य वस्तुओं की मांग न गिर जाये जिसकी मांग बनी रह सकती है और जिसके लिए इस समय अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग किया जा सकता है ।

(घ) जी नहीं । यह प्रस्ताव अत्यावश्यक वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि और न्यूनतम विनियोजन से रोजगार वृद्धि और आने वाली लम्बी अवधि में अधिष्ठापित क्षमता संबंधी धारणा में और अधिक स्पष्टता लाने के कार्य को सुगम बनाने के लिये वहां किया गया है जहां निविष्टियों या मशीन की क्षमता की दृष्टि से क्षमता की पुनः परिभाषा करना संभव है ।

(ङ) और (च) प्रश्न् ही नहीं उठते ।

अत्यावश्यक वस्तुओं तथा आम उपयोग की वस्तुओं सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्विति

1388. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अत्यावश्यक वस्तुओं तथा आम उपभोग की वस्तुओं के बारे में योजना आयोग द्वारा बनाई गई समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति के संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : आवश्यक वस्तुओं की कमियों को दूर करने और उनका उत्पादन तथा वितरण बढ़ाने के लिये कार्यवाही की गई है । योजना आयोग द्वारा आवश्यक वस्तुओं तथा आम उपभोग की वस्तुओं के बारे में बनाई गई समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर जरूरी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकता का निर्धारण करने के बारे में हाल ही में हुए खाद्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता राज्य मंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलनों में चर्चा की गई थी । सर्वसम्मत राय यह थी कि प्रारम्भ में महानगरों तथा बड़े शहरी क्षेत्रों, खानों, औद्योगिक तथा बागानी क्षेत्रों के मजदूरों के रहने वाले इलाकों, जिला मुख्यालयों, पहाड़ी इलाकों

और बार-बार अभाव तथा कमी से प्रभावित होने वाले जिलों के ग्रामीण इलाकों जैसे जरूरत मंद क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकता की वस्तुओं अर्थात् खाद्यान्नों, जिनमें, जहां आवश्यक हो, मोटे अनाज तथा दालें भी शामिल हैं, चीनी, स्टैंडर्ड कपड़ा, वनस्पति, जिसमें खाने के तेल भी शामिल हैं, सस्ता ईंधन (साफ्ट कोक तथा मिट्टी का तेल) और नमक के वितरण को प्राथमिकता दी जाए । पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में दालों, पहाड़ी क्षेत्रों और महाराष्ट्र तथा गुजरात में मोटे अनाज़ों, पश्चिम बंगाल में सरसों के तेल और पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में नमक जैसे पदार्थों की मांग को विशेष रूप से पूरा करना होगा । यह सिफारिश भी की गई थी कि सीमैंट, विद्यार्थियों के लिए कागज तथा लेखन-सामग्री, कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल तेल, आवश्यक दवाओं, साबुन, दियासलाइयों, बेबी फ़ूड, टायर तथा ट्यूबों, ग्राम जूतों तथा सोडा राख का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए कारगर उपाय किये जायें ।

रेलवे को वैगनों की सप्लाई

1389. **श्री धामनकर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगन-निर्माण उद्योग की क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तथा बेहतर ढंग से निर्यात के लिए योजनाबद्ध उत्पादन हेतु मूल्य वृद्धि के लिए समुचित उपबन्ध करने के साथ-साथ वैगनों के लिए रेलवे के साथ कोई दीर्घ अवधि वाली ठेके की प्रणाली तैयार की जा रही है ;

(ख) क्या इस समय रेलवे को सप्लाई किये जाने के लिए पिछला बकाया लगभग 30,000 वैगनों का है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कच्चे माल की कीमतों में अत्याधिक उतार-चढ़ाव होने के कारण वर्तमान मूल्य निर्धारण सूत्र में कोई परिवर्तन किये जाने की संभावना है ताकि निर्माण करने वाले एककों की क्षतिपूर्ति हो सके ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अभी नहीं, श्रीमान ।

(ख) जी, हां । इसका कारण मुख्यत: संचालन और वित्तीय कठिनाईयां, पुर्जों की समय पर सप्लाई न होना और माल का उपलब्ध न होना है ।

(ग) ऐसा एक फार्मूला तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें आधार के रूप में केवल वास्तविक लागू मूल्य को ही ध्यान में नहीं रखा जाएगा अपितु कार्य निष्पादन के समय वृद्धि की महत्वपूर्ण बातें भी शामिल होंगी ।

स्कूटरों के लिए टायर और ट्यूबों का आयात

1390. **श्री धामनकर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मांग और पूर्ति के बीच के अन्तराल को पूरा करने हेतु स्कूटरों के लिए टायरों और ट्यूबों का आयात करने की अनुमति देने संबंधी प्रश्न की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले से अंतिम निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) मांग और पूर्ति के बीच के अन्तराल को पूरा करने हेतु स्कूटरों के लिए टायरों और ट्यूबों का आयात करने संबंधी प्रश्न की जांच की जा रही है ।

"लास्ट डेज़ आफ नेताजी" नामक पुस्तक के प्रकाशन के लिए सामग्री

1391. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री खोसला द्वारा "लास्ट डेज़ आफ नेताजी" शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक की ओर दिलाया गया है जिसमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लुप्त होने के बारे में जांच के प्रतिवेदन से विस्तृत शब्दशः उद्धरण हैं ;

(ख) क्या उक्त पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करने और उसकी छपाई आदि से 3 सितम्बर, 1974 को लोक सभा के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी सामग्री प्रकट हो गई थी ;

(ग) क्या प्रतिवेदन को लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी सामग्री का पूर्व उपयोग करने के लिए सरकार से अनुमति ली गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) क्या श्री खोसला ने इस रूप में पुस्तक प्रकाशित करके आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति की शर्तों का उल्लंघन किया है और यदि हां, तो सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) सरकार ने न्यायमूर्ति श्री खोसला द्वारा लिखित "लास्ट डेज़ आफ नेताजी" नामक पुस्तक देखी है ।

(ख) तथा (घ) पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

(ग) जी, नहीं श्रीमान ।

आजाद हिन्द फौज के असैनिक कर्मचारियों तथा आई० आई० एल० के सदस्यों में से स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना

1392. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजाद हिन्द फौज के असैनिक कर्मचारियों और 'इंडियन इंडेपेंडेंस लीग' के सदस्यों के, जिन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व के अधीन भारत के स्वाधीनता युद्ध में वीरतापूर्ण भूमिका अदा की, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उनमें से कितने लोगों को राज्यवार, अब तक पेंशन मंजूर की गई है ;

(ग) आवेदनों पर शीघ्रता से विचार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या 'इंडियन इंडेपेंडेंस लीग' के एक असैनिक कर्मचारी, श्री आनन्द मोहन सहाय को जो मंत्रिमंडल सचिव थे और जोकि भूतपूर्व आजाद हिन्द सरकार के एक मात्र जीवित उच्च अधिकारी हैं, आजाद हिन्द फौज के असैनिक कर्मचारियों तथा 'इंडियन इंडेपेंडेंस लीग' के सदस्यों से

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों के निपटान के लिये सरकार की सहायता के लिए सलाहकारी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) आजाद हिन्द फौज के असैनिक कर्मचारियों और इंडियन इंडेपेंडेंस लीग के सदस्यों से अब तक 13,036 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है ।

(ग) चे (ङ) भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज से उन कर्मचारियों से पेंशन के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच करने के लिये, जो अपनी यातनाओं के बारे में लिखित सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, श्री शाहनवाज खां की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । समिति की रचना इस प्रकार है :—

1. श्री शाहनवाज खां—अध्यक्ष
2. श्री मोहन सिंह, संसद सदस्य—सदस्य
3. श्री एस०एम० घोष, स्वतंत्रता सेनानी—सदस्य
4. श्री रविन्द्र नाथ त्यागी, (उप सचिव, रक्षा मंत्रालय)—सदस्य
5. श्री एल०डी० हिन्दी (उप सचिव, गृह मंत्रालय) सदस्य, सचिव ।

चूंकि इस समिति में पहले ही भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के दो सदस्य श्री शाहनवाज खां और श्री मोहन सिंह हैं, अतः इस का और विस्तार करने का विचार नहीं है ।

विवरण

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों (असैनिक) जिन्हें, पेंशन स्वीकृत की गई है, की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नम	पेंशन स्वीकृत किये गए व्यक्तियों की कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	बिहार	1
3.	चंडीगढ़	6
4.	दिल्ली	4
5.	हरियाणा	3
6.	केरल	3
7.	मणिपुर	1
8.	महाराष्ट्र	1
9.	पंजाब	697
10.	नमिलनाडु	3
11.	उत्तर प्रदेश	2
12.	पश्चिम बंगाल	2
	जोड़	726

संसद के घेराव की धमकी

1393. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सार्वजनिक व्यक्तियों एवं शक्तियों ने संसद का घेराव करने की खुली धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सरकार को यह सूचना है कि कुछ विपक्षी दल 6 मार्च, 1975 को संसद की ओर एक रैली का आयोजन कर रहे हैं पूरी निगरानी रखी जा रही और विधि व व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपयुक्त उपाय किये जाएंगे ।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और कनाडा के बीच सहयोग

1394. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कनाडा के प्रतिनिधियों के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के मामले में कोई बातचीत हुई है या होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, अन्तरिक्ष मन्त्री, योजना मन्त्री तथा प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत तथा कनाडा के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में बातचीत हुई थी ।

(ख) इस बातचीत के दौरान वस्तु-स्थिति का जायजा लिया गया तथा किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंचा गया ।

उष्मसहों (रिफ्रैक्टरीज) के उत्पादन के कर्नाटक राज्य औद्योगिक विकास निगम को आशयपत्र

1395. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उष्मसहों (रिफ्रैक्टरीज) के उत्पादन के लिए कर्नाटक राज्य औद्योगिक विकास निगम ने एक आशयपत्र प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो आशयपत्र की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उष्मसहों के उत्पादन के लिए निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम लि० को 6 अक्टूबर, 1971 को होस्पेट (कर्नाटक) में निम्नलिखित रिफ्रैक्टरी वस्तुओं का प्रत्यक के समक्ष दिखाई गई क्षमता तक उत्पादन करने के लिए एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु इस शर्त के साथ एक आशय

पत्र जारी किया गया था कि वे सरकार के लिए सन्तोषजनक रूप में पूंजीगत वस्तुओं के आयात संबंधी व्यवस्था कर लेंगे :

1. फायरब्रिक्स	70,000 मी० टन प्रति वर्ष
2. सिलिका ब्रिक्स	20,000 मी० टन प्रति वर्ष
3. बेसिक ब्रिक्स	40,000 मी० टन प्रति वर्ष

(ग) निगम ने रिफ्रेक्टरी वस्तुओं के उत्पादन के लिये परियोजना स्थापित करने के संबंध में अभी तक कोई अभ्युपाय नहीं किए हैं क्यों कि वह संयुक्त क्षेत्र में परियोजना का क्रियात्वयन करने वाली किसी पार्टी की तलाश नहीं कर सका है अथवा स्वयं परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त साधन नहीं जुटा सका है ।

हाइड्रोथर्मल परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए कर्नाटक द्वारा सहायता की मांग

1396. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन हाइड्रोथर्मल परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता क्रमशः कितनी कितनी है जिनको कर्नाटक राज्य में क्रियान्वित किया जाना है ;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कर्नाटक की पांचवीं योजना के प्रारूप में सम्मिलित सभी परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं । बहरहाल, राज्य सरकार ने काली-नदी परियोजना, जो कार्यान्वित की जा रही है, के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना की सीमा के बाहर अतिरिक्त धनराशि की मांग की है ।

कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित पांच परियोजनाओं के लिये भी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :—

1 वराही	प्रतिष्ठापित क्षमता 2×115 मै०वा०
2 बेड्थी	प्रतिष्ठापित क्षमता 2×105 मै०वा०
3 चक्र व्यपर्तन स्कीम, जिससे शरावती से 500 मिलियन यूनिट वार्षिक उत्पादन हो सकेगा ।	
कालीनदी चरण-दो	2×25 मै०वा० $+ 3 \times 32$ मै०वा० $+ 3 \times 25$ मै०वा०
5. शरावती टेलरेस	6×40 मै०वा०

इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रश्न तभी पैदा होगा जब उन्हें योजना में सम्मिलित कर लिया जाएगा और उनके लिए वित्तीय संसाधनों का पता लगा लिया जाएगा ।

पश्चिमी "घाटों के विकास" हेतु उप-योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

1397. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी घाटों के विकास हेतु उप-योजना को पूरा कर लिया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1974–75 में उप-योजना की क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी सहायता दी गयी है; और

(ग) वर्ष 1975–76 में, राज्यवार, कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) पश्चिमी घाट क्षेत्र के लिए उप-योजना बनाने की इस समय कोई परिकल्पना नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए स्कीमें बनाई गई हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(ख) 1974–75 में संबंधित राज्यों को 1.50 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित किए गए हैं ।

(ग) वर्ष 1975–76 में दी जाने वाली सहायता राशि के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (इंटरनेशनल)

1398. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने अपनी सहायक यूनिट, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (इंटरनैशनल) की हाल में स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके गठन का ब्यौरा क्या है तथा इसके कृत्य क्या-क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी, हां । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों को अपने हाथ में लेने के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (इन्टरनैशनल) को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में नियमित किया गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय बंगलौर में है । इसके अतिरिक्त, सहायक कम्पनी अन्य प्रसिद्ध भारतीय फर्मों के संबद्ध उत्पादों के निर्यात की देख रेख करेंगी; निर्यात बाजारों को भारतीय उत्पादों और प्रौद्योगिकी सक्षमता के लिए परीक्षण स्थलों के रूप में इस्तेमाल करेगी और भारतीय उत्पादों की टेक्नोलाजी को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक प्रतिसंभरण जानकारी प्रदान करेगी ।

छोटे समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन

1399. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के कुल विज्ञापन बजट का 62 प्रतिशत भाग देश के पांच बड़े समाचार-पत्रों को मिला जबकि शेष भाग हजारों छोटे समाचार-पत्रों में बांट दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) छोटे समाचार-पत्रों को प्रोत्साहित करने के लिये क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

"पूअर प्लांट मैंटेनेंस ब्लेम्ड फार पावर कट्स" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

1400 **श्री राम सहाय पांडे**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1975 के एक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में "पूअर पलांट मैंटेनेंस ब्लेम्ड फार पावर कट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उपमन्त्री प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद, : (क) और (ख) जलाशयों में जल की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए जल विद्युत केन्द्रों का इष्टतम क्षमता तक समुपयोजन किया जा रहा है। जहां तक तापीय केन्द्रों से उत्पादन बढ़ाने का प्रश्न है, ऊर्जा मन्त्रालय ने कोयले की उपयुक्त किस्म की व्यवस्था करना, देशी और आयात किए गए दोनों प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों की समय पर सप्लाई, प्रचालन और अनुरक्षण से संबंधित कर्मचारियों के उपयुक्त प्रशिक्षण तथा अनुरक्षण संबंधी कार्यवधियों के आधुनिकीकरण आदि जैसे कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों से ताप-विद्युत के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार देखने में आया है, जो अप्रैल से दिसम्बर, 1975 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत बढ़ गया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE
अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार तथा संसदीय-कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा० सां० नि० 1348 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें दिनांक 26 अगस्त, 1974 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 378(ङ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) सा०सां०नि०1349 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिस में दिनांक 26 अगस्त, 1974 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 377 (ङ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(तीन) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 24 जनवरी, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 17(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 25 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 92 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 25 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 93 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 25 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 94 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 25 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 95 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) अखिल भारतीय सेवायें (महंगाई भत्ता) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 28 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 20(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) सा० सां० नि० 176 जो दिनांक 8 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें दिनांक 16 जलाई, 1974 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 778 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

[ग्रन्थालय में रखी गईं । देखिए संख्या एल० टी० 9008/75]

अधिसूचना के सभा पटल पर विलम्ब से रखे जाने का कारण बताने वाला एक विवरण तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1165 को, जो दिनांक 2 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9009/75]**

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) कागज संरक्षण तथा (प्रयोग का विनियमन) संशोधन आदेश, 1974 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 742(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) कागज (उत्पादन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 172 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल०टी० 9010/75]**

नारियल जटा बोर्ड के वर्ष 1972–73 के प्रमाणित लेखे

श्री ए०पी० शर्मा : मैं श्री जियाउर्र हमान अन्सारी की ओर से नारियल जटा उद्योग अधिनियम 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड, एनरनाकुलम के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल०टी० 9011/75]**

भारतीय तार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1342 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 9012/75]**

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

51 वां प्रतिवेदन

श्री जी०जी० स्वैल (स्वायतशासी जिले) : मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 51वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि हम आज अपनी संसद तथा संविधान की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आप कृपया कम से कम आज यहां अवश्य उपस्थित रहें। हमने एक विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था की है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा): क्या आप मूल संविधान का समारोह मना रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब आप नए संविधान को लागू करने में सफल होंगे तो हम उसका समारोह भी मनायेंगे ।

क्या हमें समय बढ़ाना चाहिए ? यदि आप लोग चाहें तो मैं आधा अथवा एक घंटे तक का समय और बढ़ा सकता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सरिमपुर) : आप एक घंटे का समय और बढ़ा दीजिए क्योंकि यह कार्य आज समाप्त नहीं होगा ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी
MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

Shri Pratap Singh Negi (Garhwal) : I am happy to see that the President delivered his address both in Hindi and English.

It can be said without any hesitation that the President presented a very correct picture of the national situation. The President also described the ways to deal with the situation. It is hoped that Government will succeed in its efforts and the country will go on progressing.

Government is being criticised by the opposition parties by saying that there is scarcity, unemployment, corruption and inflation in the country. No duoubt, these drawbacks are there but we have to see as to why that is so ? It is natural that production will suffer and prices will go up if the workers resort to strikes on the calls of opposition parties. The opposition parties are, therefore, also responsible for the present state of affairs. The opposition parties want to malign Government in order to come to power but they are not going to succeed in their mission.

It is really regrettable that some people are inciting the army to break discipline. The time has come when firm action should be taken against such forces.

Reaching an accord with Sheikh Abdullah is an act of great political wisdom on the post of the Prime Minister as a result of which Sheikh Abdullah has assumed power there. This is purely our internal matter. Shri Bhutto is raising a hue and cry about it at the instance of the U.S.A. which is very strange. But what is even more strange is that even some of our own countrymen are opposing the agreement. Should it mean that they are also agents of the U.S.A. ?

There are no means of communications in my area which is hilly as a result of which it remained backward. There are 8 such hill districts in Uttar Pradesh. If they are formed into a separate state then there is more possibility of development there. Recently, a Hill Development Council has been set up with this view but it has not been very effective because of lack of funds. If it is not possible to give full statehood to these districts, they should be made a centrally administered territory so that they could develop well. I support the motion of thanks on President's Address.

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजेरी) : राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों में जब अपना अभिभाषण दिया था तो मेरा दल जामा मस्जिद क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति के कारण उसमें भाग नहीं ले सका। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए क्योंकि सदन के कई सदस्यों द्वारा आरोप लगाए गये हैं। सच्चाई का पता केवल न्यायिक जांच द्वारा ही लग सकता है।

आर्थिक अपराधों के बारे में की गई कार्यवाही की चर्चा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की है। प्रसन्नता की बात है कि इसका वांच्छित प्रभाव पड़ा है। लेकिन सरकार को इस मामले में बड़ा सतर्क रहना चाहिए। केरल में लोगों की यह धारणा हैं कि 'आंसुका' का प्रयोग साम्प्रदायिक पक्षपात के लिए हो रहा है। कई भोलेभाले निरपराध व्यक्तियों को अफसरों द्वारा दी गई गलत रिपोर्ट के कारण भारतीय रक्षा नियम तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत बन्द रखा गया है। इस सम्बन्ध में एक जांच कराई जानी चाहिए ताकि बेगुनाह व्यक्तियों के निराधार रिपोर्टों के कारण दंड न भोगना पड़े।

मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि मालाबार विद्रोह या भोपाल विद्रोह में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। केरल सरकार ने उन्हें देश भक्त माना है तथा उन्हें सहायता और पेंशन दी है लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उन्हें देश भक्त नहीं माना और उन्हें पेंशन देने से इनकार किया है। सरकार को इस पक्षपात को समाप्त करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उन्हें भी पेंशन मिले।

मुस्लिम जाति के सेवाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल के मामले में जांच करानी चाहिए और इस तथ्य का पता लगाना चाहिए कि मुस्लिमों की सरकारी सेवाओं में क्या प्रतिशतता है? इस बात के लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए कि अल्प संख्यकों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले।

केरल ने चाय, काफी, इलाची, अदरक, टिम्बर और अन्य वस्तुओं का निर्यात करके देश के लिए विदेशीय मुद्रा अर्जित करने में सहायता दी है पर फिर भी यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है और वहां पर पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार को केरल को पर्याप्त सहायता देनी चाहिए।

मालाबार क्षेत्र व्यापार का एक बहुत बड़ा केन्द्र है लेकिन दुर्भाग्यवश इसे कालीकट के हवाई अड्डे से नहीं जोड़ा गया है और सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया सरकार को इस दिशा में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने बिजली की कमी का जिक्र किया है लेकिन दुर्भाग्यवश केरल की बिजली योजनाओं में धनाभाव के कारण विलम्ब हो रहा है। केन्द्र सरकार को केरल सरकार की पनबिजली योजनाओं को पूरा करने में सहायता देने का आश्वासन देना चाहिए।

राष्ट्रपति ने इस आर्थिक संकट के समय संसद के दोनों सदनों में अपना अभिभाषण दिया है लेकिन उसमें देश की बुराईयों को दूर करने के संबंध में किसी प्रभावपूर्ण नीति का उल्लेख नहीं किया गया है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहें हैं। मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावशाली उपाय अपनाए जाने चाहिए।

खाद्यान्नों पर रेल भाड़े में वृद्धि की गई है। यदि खाद्य पदार्थ, कपड़े तथा अन्य चीजों जैसी आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर जनता तक नहीं पहुंचाया गया तो देश की आर्थिक समस्या हल नहीं होगी।

Shri Swami Brahamanand ji (Hamirpur) : I support the Motion of thanks on the President's Address. The President has made a reference to the backward areas and backward classes of the society and has said that special attention will be paid to their development during this year.

It has been said time and again that fundamental changes will be made in the educational system but the same have not been made so far. It is so because implementation is not in the hands of Ministers. It depends on the bureaucrats who are the real rulers of the country.

All parties are saying that corruption should be eradicated. Even then corruption is rampant in the country and the biggest form of corruption is nepotism. This has to be stopped.

We have been sending complaints to the Ministers and we have been informed that the complaints are baseless. This reply is given on the basis of the enquiry made by the bureaucrats who hold real power in the administration of our country and the Minister are there only in name.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : I support the Motion of thanks on President's Address. Yesterday, Shri Sharad Yadav said during the question hour that he comes from a Hindi speaking State. It is not proper to say so. Shri Yadav should realise that Hindi is not the language of any State, it is the language of the whole country.

The Muslim League Members, Shri Koya, said that the communal feelings still persist in the country, especially in Kerala. This is very unfortunate. Let us not have a jaundiced view about any thing. Let us not think in terms of Hindus and Muslims because all of us are Indians first.

The Government has increased the salary of the employees of Reserve Bank of India. There is no need to do that. If they went on strikes, Government should dismiss them and recruit new people.

Andhra Pradesh has been supplying a large quantity of rice to the rest of the country. If more water is made available for irrigation in that state, it could produce more rice to feed the country. But that is not being done. There are many irrigation schemes in the state but they are not being speedily implemented. Let the Centre take over these schemes so that they are speedily implemented.

The biggest problem before the country is that of population explosion. That is why Government has undertaken family planning. But some political parties have been opposing it. This is very unfortunate. The family planning programme should be implemented properly because on its success the future of the country depends.

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : The President read his Address first in Hindi for which he deserves congratulations. But it is regrettable that he has not presented any solution of the problems facing the country.

It is being said by Government for same time that the rising trends in prices have been arrested and that they have started falling. If one visits the market one

finds that this is a totally false propaganda. Except for oil, the price of no other commodity has actually fallen.

Much has been said against the movement launched by Shri Jaiprakash Narayan. But what is wrong about the movement ? All that Shri Jaiprakash Narayan wants to do is to fight against unemployment, corruption and price rise.

If we really want to solve the problem of unemployment, it is very necessary that more and more small scale industries are set up wherein more people could be absorbed. But we do not find any such thing being done by the Government.

Some special steps should be taken to arrest rise in prices. More attention will have to be paid to the farmers and all incentives will have to be given to them so that they are encouraged to produce more.

Radical changes are needed in the present system of education. Religious and moral education is badly needed at present when we find the students indulging in acts of thefts and decoities.

It is regrettable that in the new system of education evolved in Delhi. Sanskrit has not found any place. Sanskrit is our ancient language which is the storehouse of our culture. It is, therefore, very necessary that Sanskrit continues to have the same place as it had in the past.

तत्पश्चात्, लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई
The Kok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा 2 बज कर 5 मिन्ट म०प० पर समवेत हुई ।
The Lok Sabha re-assembled at five minutes past Fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

दिल्ली के अध्यापकों द्वारा किये गयें प्रदर्शन के बारे में
RE DEMONSTRATION BY DELHI TEACHERS

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Deputy Speaker, Sir, thousands of Teachers are demonstrating at the Boat Club for enhanced pay scales. Government should give a statement and arrive at some agreement with them othervise it will lead to some agitation.

Shri H.K.L. Bhagat (East Delhi) : The issue of teachers is pending since long. Some solution should be found to settle the same.

श्री बी० वी० नायक (कनारा): कावेरी जल विवाद के बारे में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों के बीच बातचीत चल रही है । मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को ध्यानार्कषण प्रस्ताव के रूप में एजेन्डे में शामिल किया जाये ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी
MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

Shri R.P. Yadav (Madhepura) : I support the motion of thanks on President's Address.

The President has presented a very attractive picture of 1975. We saw great ups and downs during the year 1974. There was nerve-breaking price rise but thanks to the steps taken by Government to check smuggling because of which the situation has now improved. It is hoped thvt with a good Rabi-crop, the situation will improve further.

The President has said that the thermal plants and the D.V.C. plant has produced more power to the extent of 14 per cent and 34 per cent respectively. This is really creditable. But even this increased production is not going to fulfill the needs of the country. So there should be no slackening in our efforts in this regard. In Bihar there is acute shortage of power. Since the state has many coal mines, many thermal plants could be set up there. If this is done, all the shortage can be made up.

It has been said from the very beginning that special attention will be paid towards the weaker sections and backward areas but such assurances are not being implemented. Necessary infra-structure should be provided for the backward areas so that industries could be set up there.

Some people are pleading the cause of total revolution as a result of which a climate of violence and chaos has been created in the country. These people have also raised the question of unemployment. We also want to remove unemployment. We appeal to Government to pay special attention towards this .

These people have also taken up the issues of pricc rise. They are themselves responsible for priee rise because they have been disrupting the movement of foodgrains and other essential commodities by stopping the buses and trains. They talk of removing the corruption, unemployment and price rise and use destructive method to achieve their objectives. (*Interruptions*) They have been imposing their ideas on others and this is what is called fascism.

In fact their ideas are full of contradictions. On the one hand they talk of non-violence and on the other they indulge in arson and looting.

I am fully convinced that all people in the villages of Bihar are in favour of the Congress and will remain with the congress. They have been saying that they will finish the Congress in Bihar, but their calls for resignations by the MLAs was ignored by them.

I want to congratulate Government for solving the issue of Jammu and Kashmir. It is hoped that under the leadership of Sheikh Abdullah the State will make much progress.

We are having cordial relations with the neighbouring countries. Last year, several heads of states visited our country but we are sorry that the USA has decided to resume the supply arms to Pakistan even after Dr. Kissinger's visit to our country. Government should take some concrete steps in this direction.

With these words. I support the motion of thanks on President's Address.

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : राष्ट्रपति का अभिभाषण पूर्णतः अवास्तविक, तथहीन और निराशाजनक है तथा उसमें तथ्यों को छिपाया गया है। जनता के विभाग पर मुख्य रूप से हावी आपात स्थिति को बनाए रखने के सम्बन्ध में इसमें तनिक भी जिक्र नहीं किया गया है। पाकिस्तान से सम्बन्ध सामान्य हो जाने के कारण किसी वर्तमान खतरे की सम्भावना न होने पर भी आपात स्थिति के अन्तर्गत कार्यपालिका को निरंकुश अधिकार दिए जाने का क्या औचित्य है।

पिछले सत्र में तस्करों के विरुद्ध लाए गए कानून के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि यह कानून अत्यधिक ढीला है। पर इसका उपयोग भी तस्करों के विरुद्ध न होकर राजनीतिज्ञों, डाक्टरों, इंजीनियरों, अध्यापकों आदि के विरुद्ध किया जाता है। और ऐसा जब तक आपात स्थिति रहेगी होता रहेगा। सरकार इस स्थिति को कायम रखना चाहती है क्योंकि वह सामान्य विधि के द्वारा राजकाज नहीं चला सकती। 13 दिन के युद्ध के परिणामस्वरूप यह आपात स्थिति और कितने समय तक बनी रहेगी।

अभिभाषण में रेलवे हड़ताल के बाद की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह स्वाभाविक ही है। जो सरकार भूतपूर्व रेल मन्त्री की हत्या को भूल गई हो वह बेचारे कर्मचारियों की क्यों परवाह करने लगे ? उन पर ढाए जा रहे जुल्मों पर क्यों ध्यान देने लगी। उसके नौकशाहों ने हड़ताल से पहले ही कुछ लोगों को निकाल बाहर करने का निर्णय ले चुके थे। जबकि तथाकथित निष्ठावान कर्मचारियों के सम्बन्धियों को भरती के नियमों को ताक में रखकर नौकरी पर लगाया गया। यहां तक कि नियुक्ति पत्र में अयुक्त का बेटा लिखकर ही नियुक्ति की गई।

दूसरी ओर एक सम्बन्धी के हड़ताल पर जाने पर दूसरे को भी नौकरी से निकाल दिया गया। इन हरकतों पर सरकार चाहती है कि जनता उनका साथ दे।

यह आर्थिक दीवालियापन सरकार की थोथली नीतियों के कारण आया है। 70 प्रतिशत जनता निर्धनता से भी निचले स्तर पर रह रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन सभी बातों का कोई जिक्र नहीं है इस लिए वह सर्वथा गुमराह करने वाला भ्रामक है।

Shri Tarkeshwar Pandey (Salempur) : Nothing has been said about the backward areas of eastern Uttar Pradesh in the Address. Secondly there is wide spread unemployment in the country, Government should start some so as to give financial help to the educated unemployed.

Education system should be reformed and some basic changes should be made.

This is for the first time that mention for putting a ceiling on urban property has been made. But there is not much entusiasm in this regard. The ceiling on agricultural land has not been very helpful in improving the lot of the poor.

So much is said about the public sector. This concept of public and private sector cannot do much good. Unless all the industries are brought under public sector, socialism cannot be established. This unhealthy competition between private and public sector had got to be ended.

Shri Sarjoo Pandey (Gajipur): The Presidential Address is of the same old pattern. The capitalist forces are growing stronger and the per capita income of common man is declining. Government have done nothing to unearth black money. Corruption is rampant. Standard of education is going down and this is the reason on account of which the reactionaries get an opportunity to misguide the students.

Under this system of capitalism, backward areas have become more backward. All the industries are being set up in and big developed cities. Rural areas has been totally neglected. In Uttar Pradesh, Gazipur is a backward district but the state government has not paid any attention towards its development. These facts have created a sense of discontentment and resentment in the minds of the people.

The imperialist powers like the U.S.A. by lifting embargo on the sale of arms to Pakistan, have acted against the interests of India and it has given rise to great resentment in the minds of Indian public. Therefore, the need of the hour is that radical changes be made in the policies of Government so as to save the country from these capitalist forces.

Shri Jagdish Chandra Dixit (Sitapur) : Inspite of difficult economic situation efforts has been made for a break through in the fields of science and technology, but there was no room for complacency. Much had still to be achieved. Adequate measures had not been taken to improve the condition of the poor. Even after 22 years of independence, the system of slavery still prevailed in the rural areas of the country. The system of bonded labour still continued in different states in the country in one firm or other and that is known by different names in different states. The fact is this that though we apply our minds to big economic plans, yet we have ignored the social broblems. This House should take stern measures to abolish this system of bonded labour.

In the field of labour, though orders in regard to minimum wages have been issued, no machinery has been devised so far to ensure their implementation. The result is this that the labour class is deprived of basic facilities. Government should pay more attention to this aspect. Unless the disparities in industrial relations that has been mentioned by the Gajendragadkar Commission in their report, are removed, the labour class will not feel contented and there cannot be any industrial progress.

There is an urgent need for introducing radical changes in (our education) system. The efficacy of education should be judge on the basis of productivity. It should be examined how far the expenditure on education is conducive to the industrial development. The educational structure in the country should he reorganised on the lines as suggested by Gandhiji, which should be based on dignity of labour.

Shri Sudhakar Pandey (Chandauli): Every body suggested that there should be a total revolution in the field of education. Shri Jai Prakash Narain has also made an effort to bring about that revolution by setting up Gandhi Educational Institution at Varanasi but it has proved a failure. Our Parliament has carved

out an educational policy but the tragedy is that it is not being implemented. This revolution can not be brought about through the medium of a foreign language. It is unfortunate that even so long after our independence, we have not been able to bring about uniformity in choosing one medium of instruction in our educational institutions. Nothing can be more tragic than the fact that even Sanskrit is being taught in this country through the medium of English. It is the U.P.S.C. and the High Courts which have contributed to the continuance of use of English in this country. The result is this that people in general will be isolated from the mainstream of life.

There is a good deal of talk about corruption in the country. The country is passing through severe economic crisis. On the one side the exploitation by capitalists still continues and on the other, shirking of work is being preached. The tendency to shirk work has grown considerably after independence, which should be condemned. The leadership in the country should think over this phenomenon at the national level—rather all parties should start a movement against it.

The former ex-rulers have still large valuable treasures of art and literature which they have maintained as their personal property. A legislation should be enacted to take it over.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The President in his Address has expressed an optimistic note that our relations with other countries in the world will improve further in future. But the U.S.A. by taking a decision to resume arms supply to Pakistan has not only watered down all our efforts to improve our relations with U.S.A. but has definitely committed an unfriendly act against India.

Past experience has shown that arms supplied to Pakistan had been used against India. The present resumption of arms supply to Pakistan will not only hamper the efforts to establish durable peace in this part of the world but these American weapons will be used to suppress the democratic movements in Pakistan.

It is unfortunate that Government of India could not anticipate the intentions of United State. It appears that United States of America has been taking this action deliberately. There are no differences in the country in regard to the resentment of Indian people against the U.S. decision. But the Government of India has not taken any steps to express effiectively the sentiment of Indians people over this question. For this purpose both the Houses of Parliament should pass a resolution unanimously condemning the U.S.A's decision to resume arms supply to Pakistan.

As regards the agreement on Kashmir, we held different views. It is a domestic question Mr. Bhutto of Pakistan has no right to interfere. Pakistan is an aggressor and they should vacate one third part of Kashmir. The issue today is not of accession but it is a question of integration in-toto. The decision about Kashmir's accession to the federal union of India is irrevocable and it was taken with people's support. If Pakistan still interferes in this affair, New Delhi should openly support the movement for an independent Pakhtoonistan. A mere protest-note is not enough. We will have to talk with Pakistan in the language they understand.

Therefore, the situation that has been created by the supply of American arms to Pakistan is not only a cause of concern for us but also for Afghanistan. India and Afghanistan should therefore, jointly discuss this situation during the ensuing visit of Afghanistan's President here. We have to prevent Pakistan being made a base for international conspirators. A joint effort should be made to find a way out of this crisis.

The President has mentioned in his Address that Government will soon hold deliberations with the leaders of opposition parties in regard to proposals for amendments in election laws. But I would like to know when they will do it ? A joint select committee has made certain unanimous recommendations in their Report in 1972 in this connection, but Government has not so far adopted and implemented them. Under such conditions one fails to follow the propriety for fresh deliberations. Today it is not a question of policy, it is a question of intention. Unanimous recommendations of a Parliamentary committee have been put into cold storage and invitations are being sent for fresh discussions. It creates a sense of suspicision about Government's intention. Even major recommendations such as making the Election Commission a multi-member body as envisaged in article 342(2) of the constitution, allotment of equal time to all political parties on All India Radio have not been accepted so far. I submit that these unanimous recommendations should be implemented.

The President has also made a reference to the Lok Pal and Lokayukta Bills. It is an issue which has been pending for a pretty long time. So, why should it not be finalised in this very year, in this session ?

Corruption is prevalent in every field of life but the question is what measures are being taken to eradicate corruption. In several states Lokayukta Act has been passed. But who is there to enquire into the allegations made against the Chief Ministers ? It is regrettable that even after 27 years of independence we have not been able to evolve any definite procedure for probing into allegations of corruption. The Santhanam Committee had recommended formation of a panel consisting of a Supreme Court Judge, a legal expert and a popular representative of the people. That panel will examine whether there is any *prima facie* case for further enquiry. However there is still time and we can evolve a definite procedure applicable to all States.

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support the motion of thanks to the President. In his Address, the President has given a correct picture of progress the country has made and the difficulties and challenges we faced during the recent past. The credit goes to the leadership in the country, that these challenges and hardships have been met with courage and strength.

Although the general price level has not come down there is certainly stabilisation of prices. Stern action is being taken against economic offenders.

It is a pitty that some reactionary elements have been trying to take advantage of the economic hardship of the people. They are all trying to come under one banner and agitate against the Government. The opposition is expected to help the

Government in facing the chellanges before the nation but they are not doing so. Instead of helping they are creating obstacles. In fact their whole movement is aimed not only against Shrimati Indira Gandhi but against democracy itself.

The Congress party has formulated some policies and we are trying to implement them. Sometimes we do commit mistakes and the people have a right to express their resentment as they have done in the case of Jabalpur by-election. The congress candidate was defeated badly. We are not sorry about it but we will try to imrpove our performance.

I am happy that Shri Vajpayee has criticised the U.S.A. for lifting the embargo on arms supply to Pakistan. I am also of the view that we, irrespective of party affliations, should condemn this action of U.S.A. by passing a resolution in Parliament and by holding demonstrations.

The President in his Address has referred to the talks that are going on between the Prime Minister and Sheikh Abdullah. It is a matter of gratification that the accord has taken a practical shape and I hope Shri Abdullah will sincerely implement the policies of Government, the principles of secularism and socialism in that part of the country. The annual budget is going to be presented and the Planning Commission is drafting the next five year plan. I want that these plans should be so framed that poverty could be revmoved from the country. Although four plans have been completed our poverty line has gone down below 40 per cent.

1975 is the International-Women's Year. It is unfortunate that none of the male Members cared to suggest as to how and in what positive manner this should be celebrated.

I am a member of the 'Status of Women Committee' set up by the U.N. This committee has made some recommendations which should be discussed so that we could come to some conclusion as to what laws should be made for the emancipation of women. In our country women are working in the same way as men. but they are not getting equal pay for equal work. They have no doubt got some rights but still they are under the domination of man. Their economic rights are practically nil.

The condition of women in India is far from satisfactory. For example, we are told that in Gujarat men severe relations with their wives on small pretexis and then they are made to serve their husbands like domestic servants. They almost live like bonded slaves.

Again in coal mines in Dhanbad, women labourers work inside the mines carrying infants with them. This is a misrable state of affairs. With these words I support the motion of thanks.

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर-पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

मैं अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की निन्दा करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि श्री वाजपेयी ने भी इस संबंध में सरकार की नीति का

समर्थन किया है। श्री वाजपेयी यह महसूस करते हैं कि इस बारे में राष्ट्रीय मतैक्य हो सकता है लेकिन उन्होंने साथ साथ यह भी कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष के बीच दूरी बढ़ती जा रही है और इस प्रकार राष्ट्रीय मतैक्य प्राप्त करना कठिन हो रहा है तथा इस प्रकार प्रजातन्त्र खतरे में है। इस प्रकार के सिद्धान्त सभी राजनैतिक दलों के एक प्रकार के परम्परागत सिद्धान्त हैं यदि आज हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर तीव्र प्रगति नहीं कर पा रहे तो इसके लिए विरोधी पक्ष भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। हम विरोधी पक्ष को समाप्त नहीं करना चाहते लेकिन सदैव सरकार की नीतियों में दोष निकालना और उनकी कार्यवाहियों की आलोचना करना कहां तक उचित है। यदि विरोधी दल प्रजातन्त्र को बचाना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपने को और अपने अतीत को देखना चाहिए। वे दावा करते आ रहे हैं कि उनके पास देश की सभी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं के समाधान है लेकिन वह अपनी योग्यता और क्षमता का अपने ही दलों के विकास में भी उपयोग करने में असफल हुए हैं। वह उन्हें एक शक्ति दल नहीं बना सके हैं। आज भी पिछले 25 वर्षों के दौरान सरकार ने केवल इस सभा में ही संसदीय प्रजातन्त्र की नींव नहीं डाली अपितु समाज में भी प्रजातंत्र की नींव डाली है। प्रजातन्त्रीय आधार को व्यापक बनाने के लिए पिछले 25 वर्षों के दौरान कई आर्थिक परम्पराएं और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। लेकिन विरोधी दलों ने समाज की आर्थिक संस्थाओं के प्रजातंत्रीयकरण की कभी अनुमति नहीं दी। प्रजातन्त्र के विकास हेतु यह सरकार जो भी कार्यक्रम बनाती है उसे क्रियान्वित करने में विरोधी पक्ष के लोग बाधा डालते हैं और कहते हैं कि सरकार जनता के हित को नहीं देखती। हमारा रवैया उपेक्षापूर्ण है यही एक वजह है जिसके कारण विरोधी पक्ष को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती वह अपनी पहले की पद्धति से लाभ नहीं उठाना चाहते उससे पाठ नहीं सीखना चाहते। वह बार बार गलतियों को दोहरा रहे हैं। कुछ इस प्रकार के संकेत मिले हैं कि सन् 1971 के पहले की तरह अब भी सभी विरोधी दलों का गठबंधन होगा। कोई नहीं जानता कि इसे कहां तक सफलता प्राप्त होगी। यदि विरोधी पक्ष सब मिलकर एक हो जाएं तो उनका प्रजातंत्र के प्रति महायोगदान होगा। आज देश को सशक्त विरोधी पक्ष की आवश्यकता है। प्रधान मन्त्री तथा सरकार की नीतियों की बार बार आलोचना करना केवल जनता को गुमराह करने के लिए है। विरोधी पक्ष ने अभी तक इस बात को नहीं समझा है कि प्रजातन्त्र की नींव सतारूढ दल ने सरकार की नीतियों ने और योजना आयोग ने मिलकर डाली है अतः मेरा विरोधी पक्ष से अनुरोध है कि यदि वह सत्तारूढ़ दल और अपने बीच की खाई को दूर करना चाहते हैं तो उन्हें पुराने विचारों को त्याग देना चाहिए।

भारत ही एक ऐसा देश है जहां आर्थिक कठिनाईयों के बावजूद भी संसदीय प्रजातन्त्र बना हुआ है। भारत सभी विकासशील देशों के लिए संसदीय प्रजातन्त्र के मामले में आदर्श रूप है। यदि विरोधी दल वास्तव में प्रजातन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं तो आर्थिक हितों के लिए सभी आर्थिक संस्थाओं के प्रजातंत्रीयकरण के लिए आह्वान दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस की शक्ति उसकी एकता में निहित है और विरोधी पक्ष के किसी एक दल में ऐसी एकता के दर्शन नहीं होते। सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध में नौकरशाही व्याप्त है। इस बारे में विरोधी पक्ष ने क्या किया। क्या उन्होंने नौकरशाही को दूर करने के लिए उसके स्थान पर आधारभूत योजना दी है?

विरोधी दलों को सत्तारूढ़ दल से प्रजातन्त्र और समाजवाद का पाठ सीखना चाहिए। हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ें और न केवल संसदीय प्रजातन्त्र तथा राजनीतिक प्रणाली को कायम रखें अपितु देश की आर्थिक तथा सामाजिक संस्थाओं का प्रजातंत्रीयकरण करने के लिए सारे विश्व में एक आदर्श बने।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I did not want to participate in this debate but after listening to the speeches made by a few hon. Members I felt that I must say a few words on this subject.

The President in his address has referred to total revolution and said that the people who talk of total revolution aim at disintegration of the country by putting an end to democracy. In this connection we have to consider the present thinking in the ruling party. Shri Sudhanshu Das is an article in the 'Indian Express' and Shri Ramesh Thapar in the 'Political and Economic Weekly' have given a hint of the thinking of the ruling party. Shri Sudhanshu Das has stated that some Members of the ruling party have come to the conclusion that Parliament sessions should be shortened. Shri Ramesh Thapar has stated that the Prime Minister has unnecessarily started the talk of a snap poll. Also Shri Thapar has given a suggestion that term of present Lok Sabha should be extended by two years. During this period constructive steps should be taken to resolve the economic crisis being faced by the country. This is the thinking of the ruling party reflected by the press representatives.

During a state of emergency under proviso to Article 83 of the constitution Parliament has got the power to extend the term of Lok Sabha by one year at a time by an ordinary law. In the interest of preserving democracy the state of emergency should be ended. I would like to remind the hon. Members that President Hidenburg of Germany used to have Parliament. He thought it to be a nuisance. He reduced the duration of Parliament sessions considerably. Previously the laws were enacted by the Parliament but during his tenure of office he started making laws through the power of decree. Likewise our Ministers and bureaucrats also want to reduce the duration of sessions because they also think that Parliament to be a nuisance. They say they cannot work during Lok Sabha sessions. As if they work a lot.

Special Cells have been created in ministries to cook up answers and to evade questions. In this context I would like to refer to Paramount Engineering Company. It is a bogus firm. This company sold the licences which they got through the influence of Minister of Steel and Mines, Shri Chandrajit Yadav. I have raised a question of privilege in this regard. A Parliamentary Committee should be constituted to go into this matter.

The President has referred to corruption. In a Parliamentary system unless there are proper relations between different organs corruption will not end. Question arises as to what should be the relations between courts and Parliament, between bureaucracy and Ministers. A Parliamentary Committee should go deep into this question and come to a certain conclusions and these conclusions should come before the House.

The Director of Industries of U.P. has said that more than 30 per cent firms are bogus firms in the small scale industries of U.P. This Paramount firm is also one among them. On preliminary enquiries the details of annual consumptions

were sought, but the firm failed to give any positive reply and was thus caught. Therefore I again submit that a Parliamentary committee should be constituted to go into this matter.

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसा अभिभाषण केवल वही सरकार तैयार कर सकती है जिसका सिर रेत में हो। वर्तमान परिस्थितियों को नजरअंदाज किय गया है या सरकार ने इन्हें जानबूझ कर टाल दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सबसे आपत्तिजनक बात यह थी कि संभवत: पहली बार अभिभाषण का राजनैतिक बनाने का अशिष्ट और स्पष्ट प्रयास किया गया। बिहार आन्दोलन के महत्व को कम करने का प्रयास किया गया है।

प्रधान मंत्री तथा उनके सहयोगियों का कहना है कि दलविहीन प्रजातंत्र की धारणा प्रजातंत्र पद्धति के लिए अत्यन्त घातक है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि जम्मू-कश्मीर के मामले में क्या हुआ है। शेख अब्दुल्ला वहां के कांग्रेस विधायक दल के नेता नहीं हैं और न ही उनके मंत्री किसी दल में से हैं। दलहीन प्रजातंत्र इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है। सत्तारूढ़ दल विशेषकर प्रधान मंत्री ने दलहीन प्रजातंत्र का सूत्रपात किया है।

दलहीन प्रजातंत्र के बारे में महान नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान आन्दोलन द्वारा वे इसे प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि दलहीन प्रजातंत्र एक वर्गहीन समाज द्वारा ही संभव है।

राष्ट्रपति को सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता बनाया गया है तथा उन्हें सत्तारूढ़ दल तथा लोगों के बीच विभिन्न मामलों पर यथा भ्रष्टाचार के मामले पर, निर्वाचन पद्धति में सुधार तथा शैक्षिक सुधार के मामल पर बेरोजगार और बढ़ती कीमतों के बारे में जो संघर्ष चल रहा है, उसको रजनीति में उलझाने की कोशश की गई है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र की दुखद हत्या की कोई चर्चा नहीं की गई है। क्या सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। सरकार इस मामले को फिर टाल देगी।

मैं आर्थिक पक्ष को लेता हूं। भारत आज भी उसी स्थिति में है जिस पर वह वर्ष 1965–66 में था। 1965–66 के बाद किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हुई है। आजका पूंजीनिवेश 1965–66 के स्तर से भी कम है। 1965–66 में विनियोजन की दर 14 प्रतिशत तक पहुंची थी और अब यह 10 प्रतिशत से भी कम है। 1969 के बाद चार वर्षों में वस्तुओं के थोक मूल्य 60 प्रतिशत और खाद्यान्न के 62 प्रतिशत बढ़ गए हैं। यह एक ऐसा रिकार्ड है जिसे विश्व के केवल कुछ देशों द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता। प्रधान मंत्री चाहती हैं कि लोग इस बात पर विश्वास करें कि हमारे आर्थिक संकट कुछ विदेशी कारणों से हैं लेकिन प्रधान मंत्री के इस प्रचार पर कौन विश्वास करेगा। हमारी अर्थव्यवस्था हमारी राष्ट्रीय आय के केवल 5 प्रतिशत तक के आयात पर निर्भर करती है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे आर्थिक संकट विदेशी कारणों से हैं। हाल ही में इंग्लैण्ड के अर्थशास्त्रियों से पूछा गया कि इंग्लैंड में आर्थिक संकट का क्या कारण है तो अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस आर्थिक संकट के लिए घरेलू कारण जिम्मेदार हैं। ऐसी बात यदि उस देश के बारे में सच हो सकती है जो कि आयात पर बहुत अधिक सीमा तक निर्भर करता है तो भारत जैसे देश के लिए जिसमें राष्ट्रीय आय के केवल 5 प्रतिशत तक आयात होता है यह कैसे मान लिया जाए कि यहां आर्थिक संकट विदेशी कारणों से हैं।

1965–66 तक गैर कृषि प्रतिष्ठानों में रोजगार 5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था। लेकिन अब यह 1 प्रतिशत की दर से भी कम बढ़ रहा है। आज की सरकार की यह महान सफलता है।

आर्थिक संकट के एक अन्य पहलू प्रति व्यक्ति आय की ओर भी ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा। वर्ष 1975 में देश की प्रति व्यक्ति आय 1965–66 से कम है। प्रधानमंत्री लोगों से यह कहती आ रही हैं कि विरोधी दल वर्तमान आर्थिक स्थिति से अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। क्या वह किसी एक ऐसे देश का उदाहरण दे सकती हैं जहां विरोधी दलों ने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी तथा आर्थिक संकट के प्रश्नों को न उठाया हो यदि विरोधी दल इन प्रश्नों को न उठाते तो वे अपने अस्तित्व के प्रति न्याय न करते।

सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति संबंधी घोषणा की बहुत चर्चा हुई है। अभी हाल ही में श्री टी०ए० पाई ने राष्ट्रीय क्षेत्र के बारे में कहा है। यह समझ नहीं आता कि राष्ट्रीय क्षेत्र से उनका क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय क्षेत्र से उनका तात्पर्य यही है कि 49 प्रतिशत गैर सरकारी पूंजी निवेश करने से सरकारी क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्र बन जायेगा। क्या श्री टी०ए० पाई का यह स्पष्ट अर्थ नहीं है

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए।
Shri Dinesh Chandra Gosvami in the Chair]

कि गैर सरकारी पूंजी लगायी जाने से पहले सरकारी क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्र नहीं है ? श्री पाई ने जो कुछ कहा है वह सरकार के नीति निर्माताओं की अभिव्यक्ति से बिल्कुल विपरीत है। अतः सरकारी क्षेत्र को राष्ट्रीय क्षेत्र मानना पड़ेगा।

हमने देखा है कि गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा बनायी गई गैर कानूनी क्षमता को किस प्रकार विनियमित कियागया है। सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात तो यह है कि शराब उद्योग द्वारा बनायी गई गैर कानूनी क्षमता को भी किस प्रकार विनियमित किया गया है। गैर कानूनी क्षमता, फालतू क्षमता, यहां तक कि शराब उद्योग द्वारा इस प्रकार बनायी गई तथा बढ़ाई गई क्षमता को विनियमित करने की क्या सामाजिक आवश्यकता थी ? अब हम सुन रहे हैं कि लाइसैंस जारी करने के लिए क्षमता सीमा समाप्त की जा रही है।

हमारी प्रधान मंत्री, जो योजना आयोग की अध्यक्ष भी हैं, देश की योजना पर अपना थोड़ा सा समय भी नहीं लगाती हैं। इस देश में आयोजना के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। प्रधान मंत्री तो योजना आयोग के मैम्बरों के साथ खिलवाड़ करने में ही व्यस्त हैं। हमारी आज की अर्थ-व्यवस्था एक आयोजित एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था ही नहीं है।

जब हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाते हैं, तो हमारी प्रधान मंत्री इन भ्रष्टाचारों की जांच कराने के बजाय हम से यही कहती हैं कि विपक्ष भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। मैं यह चुनौती देता हूं कि वे विपक्ष के किसी एक व्यक्ति का नाम बतायें जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गए हों। विपक्ष को भ्रष्ट तरीके अपनाने का कोई अधिकार नहीं है।

विपक्ष ने अपना राष्ट्रीय कर्त्तव्य समझकर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं। लेकिन प्रधान मंत्री उन पर गम्भीरता से विचार नहीं करेगी। 122 संसद सदस्यों ने हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे और जिस ढंग से सरकार ने इन आरोपों पर कार्यवाही

की उससे सरकार की प्रशंसा नहीं की जा सकती । प्रधान मंत्री ने उन आरोपों को मंत्रियों की एक समिति, जिसमें विधि मंत्री भी थे, को सौंप दिया । इससे लोगों के दिलों में विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता ।

हमने प्रश्न उठाया था कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड में बड़ी हेरा-फेरी हुई है । महालेखा परीक्षक ने स्पष्ट सिद्ध किया है कि हरियाणा बिजली बोर्ड के हिसाब में 12.50 करोड़ रुपये का गोलमाल हुआ है । सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अभी हाल ही में कांग्रेस तथा अन्य दलों के जिम्मेदार लोगों ने कर्नाटक राज्य के मुख्य मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये हैं । इन अरोपों की सूचना प्रधान मंत्री को कई महीने पहले ही दे दी गई थी, लेकिन प्रधान मंत्री ने इन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया है । इसलिए अब विरोधी दल प्रधान मंत्री को ज्ञापन देने के लिए बाध्य हुए हैं ।

अब प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर शिकायत कर रही हैं कि विपक्ष ने उन्हें सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र बनाया है । क्या विश्व भर में कोई प्रधान मंत्री विपक्ष के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत करता है ? वस्तुतः प्रजातंत्र में प्रधान मंत्री को आक्रमण का केन्द्र बिन्दु बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है । प्रधान मंत्री ने यह कह कर लोकतान्त्रिक व्यवहार नहीं किया है कि विपक्ष ने उन्हें हटाने का प्रयत्न किया है । लेकिन विपक्ष का यह कार्य है ही नहीं । वास्तव में विपक्ष का कर्त्तव्य है विरोध करना, भंडाफोड़ करना, पदच्युत करना एवं प्रस्ताव करना ।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : श्यामनन्दन बाबू, आपको प्रधान मंत्री का भय सवार हो गया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मुझे प्रधान मंत्री का भय नहीं है । लेकिन मैं प्रधान मंत्री को फिर आश्वासन देता हूं कि विपक्ष का ऐसा कोई आशय नहीं है । अपितु प्रधान मंत्री लोकतंत्र के साथ स्वयं अन्याय कर रही हैं । यह सरकार नैतिक मूल्यों को बिल्कुल नहीं मानती है । सत्ताधारी दल दल बदल करने का संगठन बना रहा है जबकि उन्होंने दल बदल विरोध विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी है । फिर भी सत्ताधारी दल ही दल बदल करने को बढ़ावा दे रहा है ।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सारे सदन ने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर लगे प्रतिबंध को हटाये जाने की निन्दा की है । क्या इस तरह से रोना चिल्लाना किसी देश के आत्म सम्मान के अनुसार है ? हम अमरीका से किसी ऐसी बात की आशा नहीं रखते जिसे कि वह अपने राष्ट्रीय हितों में नहीं समझता हो । हमें भी अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना चाहिए । इस बारे में अन्य शक्तियों से शिकायतबाजी न कर अपनी सुरक्षा का स्वयं प्रबन्ध करना चाहिए ।

अतः राष्ट्रपति का भाषण इतना प्रभावपूर्ण नहीं है जिससे हमारी भावना उद्वेलित हो और जिसका कि हम जोरदार समर्थन करें ।

Shri Chiranjib Jha (Saharsa) : Our country has faced many a crisis in the recent past. Inspite of those difficult situations achievements of our country in the domestic as well as international sphere have been prais-worthy. We have established friendly relations with our neighbours and also with other countries

that shows the success of our foreign policy. Even a country like Portugal has now tried to establish friendly relations with our country. Developments in Sikkim are also one of the great achievements of our Government.

It has been our constant endeavour to have friendly relations with Pakistan. Of late there have been certain efforts to normalise rleations with that country. But the American decision to lift the embargo on the supply of arms to Pakistan will create tension in the sub-continent.

The Kashmir accord is another feather in the cap of our Government led by the Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi. It is gratifying that a lasting solution to the Kashmir problem has been found.

The atomic explosion carried out by our atomic scientists has made our country a nuclear power. It is a great achievement of our country.

Success in oil exploration, advance in agricultural development, curb on the rising prices and effective steps to check smuggling are among the many achievements of our Government. Our Government deserve all credit for its performance in various spheres.

Certain elements have been creating an atmosphere of violence and hatred in the country. It is posing danger and is a matter of great anxiety for us all. This atmosphere is responsible for the murder of Shri Lalit Narain Mishra.

Shri Vinoba Bhave has expreseed the view that the Government alone is not responsible for the present ills of the country. All of us are responsible for the present state of affairs. The problems of corruption and price spiral should be discussed fully. There should not be any agitation on this ground. I have also stated that all of us should join hands to reforming the electoral system. Shri Bhave has praised the Prime Minister's achievements in our foreign policy.

We have in our country an out-moded administrative machinery. This machinery has not been able to implement the progressive policies of the Government. Our administrative set up requires to be over-hauled. The Government should consider this matter.

The Government should provide employment allowance to the unemployed or who are not able to get jobs. Government should also consider to give old age pension to old people belonging to the poor sections of our society.

Devnagri script should be made common script for all the Indian languages. This will facilitate learning of various Indian languages.

No powers have been deligated to the Gram-panchayats at present. The Government should vest in panchayats some powers and authority so that they can function effectively and help in the development of our country.

Shri N. E. Horo (Khunti): Sir, President's Address does not seem to be much enthusiastic. During 27 years of our independence neither the Government at

the centre nor the State Governments have done anything worthwhile for upliftment and betterment of the Harijans and Adivasis, inspite of the provisions made in the constitution and the policies framed by the Government in this regard. The Home Ministry has circulated various instructions and circulars for reservation of posts in different Departments and Public Undertakings for these people. But the reservation quota of the posts has not been filled up in any of the departments. The Home Ministry itself have not implemented these instructions and circulars. In both the Parliament Secretariats we do not find even a single tribal person as a messenger even.

Bihar Government by passing certain laws, have uprooted Adivasis and Harijans from their lands in the jungles. Uptill now only big landlords have been harassing and exploiting them but now the courts have also started their exploitations after the enactment of these laws. Government should see that if such things continue, there might be revolution in the country, especially in the eastern region.

A reference has been made in the President's Address to the economic offences. Hoarders and black marketeers are responsible for this state of affairs. But if you look towards the eastern region of the country you will find that this Government is responsible for the economic and regional offences.

In the Western sector, the States of Punjab, Haryana and Maharashtra have achieved progress which lacks in the eastern sector of the country. The eastern sector of our country is very backward despite the fact that plenty of raw material is available there. Steps should be taken for the development of this eastern region of the country.

People are demanding the creation of new states U.P. is a very big state which should be bifurcated. Similarly we should have a separate state by taking some districts of Bihar some of West Bengal and some of Orissa.

The Government should build up infra-structure which is necessary for the development of eastern region of our country unless this is done this region will remain backward. With these words I support the motion of thanks.

Shri Chandra Shailani (Hathras) : Sir, I stand to support the motion of thanks on the President's Address, yet the President has not given clear picture of the situation in the country in his Address. During the last 27 years no doubt some big development works have been completed, but there are certain basic problems, which have remained unattended. Unless steps are taken to tackle these problems, the future of the country will remain uncertain.

Today our country is faced with grave problems of starvation, corruption, unemployment, casteism and untouchability. The inhuman treatment being meted out to the people belonging to scheduled castes and scheduled tribes all these years is a blot on the fair name of our country. It is really regrettable that there is no reference to this problem in the President's Address.

During the last 27 years henous cruelties have been perpetrated on scheduled caste and scheduled tribe people. Their women have been insulted and youngmen have been killed. In January, 1975 in Raghunath Purarm village in Khammam district af Andhra Pradesh police molested women-folk in huts belonging to Harijans and maltreated them in the police station. Government should take suitable action in regard thereto.

In another incident in Rajasthan 150 huts belonging to the people of Harijans Community have been burnt in the month of February, 1975. A Harijan girl was purchased by a Zamindar for rupees eight thousand in Chhatisgarh District of Madhya Pradesh. Such are the heart rending taies of woes of Harijans and yet Government have not given due attention to the problems of these poor people. A separate Ministry should be created at the centre for dealing with the problems of the people belonging to scheduled castes and scheduled tribes.

The Government has taken welcome steps to curb rising prices. As a result of these steps prices have come down. The steps taken to check smuggling also deserve all praise I hope, Government will search the Houses of ex-rulers and unearth hidden wealth.

The nuclear explosion conducted on May 18, 1974 is a great achievement of our scientists. This has enhanced the prestige of our country.

The Prime Minister has tackled the long standing Kashmir Problem in a befiting manner. The Kashmir accord is welcome step to all the progressive forces.

Shri Jaya Prakash Narain has launched a movement to eradicate corruption and to bring about other reforms. How can corruption be removed by the corrupt people ? The J.P. movement has support of the big capitalists and well-to-do people. The poor people and exploited sections of our society are not behind this movement. The movement cannot thwart the progress of the country on the path of socialism.

This J.P. movement is vitiating the atmosphere in the country. The atmosphere of violence and hatred created by this movement is responsible for the murder of Shri L.N. Mishra. The Government should be firm in this regard and should deal with this movement with a heavy hand.

Shri Ram Hedaoo (Ramtek) : Sir, people have no faith in the promises made by the President in his Address. Government have been misleading the people by making false promises all these years. During these 27 years the Government have failed to provide even the basic necessities of life to the people. There are crores of people living below the poverty line in the country. People are not able to get adequate food. People are willing to work but they do not get employment the number of unemployed persons is increasing day by day.

Powerty is a greatest threat to our democracy. If the people in this democracy cannot get employment, this is a meaningless democracy. The Government should take steps to provide food and jobs to the people.

Government have promised to provide foodgrains to the people through fair-price shops, but there are no satisfactory arrangements for distribution of the foodgrains. The per capita ration quota is 7 to 8 Kg. in the cities whereas in villages even two kg. ration is not provided to the people regularly. The quality of foodgrains supplied to the people in rural areas is inferior to that of the foodgrains supplied to the people in the urban areas. The disparity in the distribution of foodgrains in rural and urban areas should be removed. Steps should be taken to give 8 Kgs. of ration throughout the country, otherwise there will be a national upsurge.

Rice is being sold at the rate of Rs. 4/- per kg. in Chanda and Bhandare districts of Vidarbha. The poor people cannot afford to purchase rice at such a high price.

There have been big talks of changing our educational system for the last 27 years, but no change is coming about. The present system of education produced only clerks. This present system of Education should be changed.

We require job-oriented and industry-oriented education in our country so that a person after completing his education may be in a position to earn his livelihood.

There are different types of educational institutions at present in our country. Public schools are for the children of the rich and higher officers, whereas the others are for the children of common people. There should be a uniform pattern of education with a uniform curriculum throughout the country.

We find children of poor people begging at railway platforms. There is no proper and adequate arrangement for providing food, clothing and education to these children. Adequate arrangements in regard thereto should be made.

श्री पाओकाई हाओकिप (वाह्य मनीपुर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण से आगामी वर्ष के लिये नई आशायें बन्धी हैं। अपने अभिभाषण में उन्होंने हर पहलू पर प्रकाश डाला है। अब उन्हें क्रियान्वित करना सदन का काम रह गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अद्भुत उपलब्धियां हुई हैं। यह हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत ही उत्साहजनक है।

आन्दोलनों, घेरावों, हड़तालों पर आधारित रहना सरकार और विपक्षी दलों दोनों के लिए ही हानिकारक रहेगा। उनके लिए तथा देश के लिए सरकार की उपलब्धियों और प्रधान मंत्री की सराहना करना अधिक लाभदायक होगा। सरकार ने देश के विकास के लिए कुछ उठा नहीं रखा है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। तथा सरकार उसके प्रति जागरूक है।

देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या एक ज्वलंत समस्या है। यह स्थिति नागा और मिजो विद्रोहियों की बनाई हुई है। ऐजल में कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की हत्या से हमें बड़ा धक्का लगा है। ऐसे हिंसात्मक वातावरण में वहां विभिन्न योजनाओं को लागू करना बहुत असंभव हो गया है।

मेरा यह सुझाव है कि नागा और मिजो विद्रोहियों को हिंसा के मार्ग से केवल उनमें विश्वास पैदा करके ही हटाया जा सकता है। हत्या, आगजनी, बलात्कार देश में समाप्त किए जाने चाहिए तथा मृत व्यक्तियों के परिवारों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए।

सरकार का पहला काम यह है कि वह गुमराह छिपे लोगों को सही मार्ग पर लाये और ऐसे उपाय करे जिससे वहां हिंसा की घटनाओं को बन्द किया जाए।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पैंशन संबंधी योजना नीति हमारी प्रधान मंत्री द्वारा वर्ष 1972 में चालू की गई थी। लोगों ने इस योजना का स्वागत किया है। लेकिन कई स्वतंत्रता सेनानियों को अभी तक पैंशन नहीं मिली है। सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और इस बात के लिए उपाय करने चाहिए कि मृत स्वतंत्रता सेनानियों की पैंशन उनके परिवार के सदस्यों को दी जाये। अरुणाचल प्रदेश एक नया संघ राज्य क्षेत्र है। सरकार को वहां के लोगों की लोकप्रिय सरकार स्थापित करने की मांग को स्वीकार करना चाहिए।

श्री बोरेन एंगती (दीफू) : आसाम सरकार ने कई बार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि आसाम में दो और तेल शोधक कारखाने स्थापित किये जायें। आसाम में सबसे अधिक मात्रा में अशोधित तेल निकलता है। इसीलिये आसाम के लोगों की मांग बिल्कुल उचित है।

सरकार को आसाम में ब्रह्मपुत्र बाढ़-नियंत्रण मामले के संबंध में एक उपयुक्त कानून बनाना चाहिए क्योंकि यह मामला बहुत समय से खटाई में पड़ा है।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि न्यू बोगाई गांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन का विस्तार किया जाए। यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि इसके बिना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को काफी कष्ट उठाना पड़ता है। यही रेलवे लाइन वहां की एक मात्र रेलवे लाइन है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के लोग अन्य राज्यों के लोगों से संपर्क स्थापित रखते हैं।

मिकिर पहाड़ियां और उत्तरी कछार पहाड़ियां इस देश में सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं। सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास के मामले में काफी गम्भीर है और वह पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा रही है। अतः सरकार को मिकिर पहाड़ियों और उत्तरी कछार की पहाड़ियों में संचार साधन जुटाने चाहियें। सरकार को आसाम के इन दो जिलों के विकास के मामले में विशेष ध्यान देना चाहिए।

मेरे अपने जिले में टेलीफोन की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, वहां ट्रंक काल की सुविधायें भी नहीं हैं। वहां ये सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि लांग राज्य की राजधानी से सम्पर्क स्थापित रख सकें।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
52 वां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया): मैं कार्य मंत्रणा समिति का 52वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोकसभा गुरुवार 27 फरवरी, 1975/8 फाल्गुन, 1896 (शक) के ग्यारह बजे मध्याह्न-पूर्व तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha than adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, February 27, 1975/Phalguna 8, 1896 (Saka)

MGIPNLK—6/Lok Sabha/75—200 Copies.